सत्यमेव जयते

राज्य के वित्त पर
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए



उत्तराखण्ड सरकार

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
	अध्याय- 1: राज्य सरकार का वित्त		
3.	उत्तराखण्ड की रूपरेखा	1.1	1
4.	चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेन का सार	1.1.1	2
5.	राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
6.	बजट आकलन और वास्तविक	1.1.3	4
7.	जेण्डर बजटिंग	1.1.4	5
8.	राज्य के संसाधन	1.2	7
9.	राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	10
10.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	16
11.	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	17
12.	संसाधनों का उपयोग	1.6	17
13.	व्यय की गुणवत्ता	1.7	25
14.	सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण	1.8	27
15.	परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	31
16.	ऋण प्रबन्धन	1.10	34
17.	राजकोषीय असंतुलन	1.11	37
18.	विगत राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	1.12	40
19.	निष्कर्ष	1.13	40
20.	संस्तुतियाँ	1.14	42
	अध्याय- 2: वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण		
21.	प्रस्तावना	2.1	43
22.	विनियोग लेखे का सारांश	2.2	43
23.	वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबन्धन	2.3	44
24.	विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	2.4	50
25.	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.5	52
26.	बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ	2.6	53
27.	सहायता अनुदानों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	2.7	54
28.	कोषागार निरीक्षण परिणाम	2.8	55
29.	चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम	2.9	55
30.	निष्कर्ष	2.10	57
31.	संस्तुतियाँ	2.11	58

अध्याय-3: वित्तीय प्रतिवेदन			
32.	उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.1	59
33.	विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.2	60
34.	दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि	3.3	60
35.	लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अधीन बुकिंग	3.4	61
36.	मुख्य शीर्ष 8009 एवं 2049 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण आँकड़ो की प्रविष्टि	3.5	62
37.	निष्कर्ष	3.6	62
38.	संस्तुतियाँ	3.7	63

परिशिष्ट

	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट **-1**	राज्य रूपरेखा	65
परिशिष्ट **-1.1**	भाग अः सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना भाग बः वित्त लेखे का विन्यास	67 68
परिशिष्ट **-1.2**	भाग **अः** राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि भाग बः राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	69 72
परिशिष्ट **-1.3**	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	75
परिशिष्ट **-1.4**	भाग अः वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग बः 31 मार्च 2013 को उत्तराखण्ड सरकार का सारांशित वित्तीय स्थिति	78 81
परिशिष्ट **-1.5**	2012-13 के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बजट से बाहरी अन्तरित निधियों को दर्शाती विवरणी	83
परिशिष्ट **-1.6**	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक / अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण	86
परिशिष्ट **-2.1**	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ 1 करोड़ से अधिक थी या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी	87
परिशिष्ट **-2.2**	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ 1 करोड़ से अधिक था या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था	89
परिशिष्ट **-2.3**	प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	90
परिशिष्ट **-2.4**	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	92
परिशिष्ट **-2.5**	₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी)/आधिक्य में परिणत निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	93
परिशिष्ट **-2.6**	वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए भारी अभ्यर्पण	96
परिशिष्ट **-2.7**	**भाग अः** वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक) **भाग बः** अन्तिम आधिक्य के बावजूद अभ्यर्पण	99 100
परिशिष्ट **-2.8**	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ 10 करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया	101

	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट-**2.9**	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया	102
परिशिष्ट-**2.10**	30/31 मार्च 2013 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	104
परिशिष्ट-**2.11**	व्यय की तीव्रता	105
परिशिष्ट-**2.12**	वर्ष 2012-13 तक के लम्बित डी. सी. बिल	107
परिशिष्ट- **3.1**	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखो के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण	108
परिशिष्ट-**3.2**	दुर्विनियोग, चोरी/हानि आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण (वे मामले जिनमें मार्च 2013 के अन्त में अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी)	109
परिशिष्ट-**3.3**	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	110
परिशिष्ट-**4.1**	शब्दावली	111

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय-1 एवं अध्याय-2 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं।

अध्याय-3 वित्तीय प्रतिवेदन कार्य पर चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों में की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेनदेन- की लेखापरीक्षा एवं सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अभियुक्तियों को पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के सापेक्ष बजट एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निर्धारित लक्ष्यों तथा प्रभावी प्रवृत्तियों एवं सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा के आकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष पर उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध कराता है।

अध्याय 1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2013 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋणपद्धति इत्यादि की प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अन्तर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण एवं वह ढंग, जिस प्रकार सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को प्रबन्धित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय 3 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण का विवरण प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय सुधार पथ: उत्तराखण्ड, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफ आर बी एम अधिनियम), 2005 पारित करने वाले शुरुआती राज्यों में एक है। उत्तराखण्ड राज्य ने वर्ष 2006-07 से आगे राजस्व आधिक्य प्राप्त करने के लक्ष्य की उपलब्धि प्राप्त की परन्तु इस प्रवृत्ति को नहीं बनाए रख सका तथा वर्ष 2009-10 में राजस्व घाटे में परिणत हुआ। तथापि, राज्य 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक लाने में कामयाब रहा। अंततः वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटा, आधिक्य में बदल गया और वर्ष 2012-13 के दौरान बढ़कर ₹ 1,787 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा चार प्रतिशत (पुनरीक्षित) के निर्धारित लक्ष्य से नीचे जारी रहा, जैसा कि 2007-08 से एफ आर बी एम में परिकल्पित किया गया था। यह वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान तर्कसंगत सीमा (स रा घ उ का 3.5 प्रतिशत) के अन्तर्गत था। चालू वित्त वर्ष के लिए ₹ 1,600 करोड़ (स रा घ उ का 1.48 *प्रतिशत*) का राजकोषीय घाटा तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) द्वारा निर्धारित मानक से बहुत निम्न था।

पूँजीगत व्यय को उच्च प्राथमिकता: एफ आर बी एम अधिनियम में पूँजीगत व्यय की प्राथमिकता हेतु कोई विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। यद्यपि, राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 के बजट के साथ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत अपने मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रति वचनबद्धता की है जो इस बात का समर्थन करता है

कि वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 3.5 *प्रतिशत* होना चाहिए, जिसे वर्ष 2013-14 तक पुनः कम करके तीन *प्रतिशत* तक लाया जाएगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, राज्य सरकार को उधार कम लेना पड़ेगा और इससे निकट भविष्य में कम निधियाँ उपलब्ध होंगी। तथापि, चालू राजकोष में सरकार ने वर्ष 2011-12 की तुलना में 53 *प्रतिशत* अधिक निधियों के पूँजीकरण की व्यवस्था की।

यद्यपि वर्ष के दौरान राज्य राजस्व आधिक्य प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे को कम करने में कामयाब रहा, लेकिन उधारियों (₹ 1,021 करोड़) के माध्यम से, घाटे के वित्तपोषण से बचने के लिए, घाटे की स्थिति पर नियन्त्रण रखने के प्रयास किये जाने चाहिए।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल गत तीन वर्षों में लगभग नगण्य (किए गए निवेश पर 0.01 *प्रतिशत*) था जबकि सरकार ने इस निवेश के लिए उधार ली गई निधियों पर 7.89 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

सरकार को निवेशों में धन की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु ऐसी कम्पनियों/निगमों की पहचान करनी चाहिए, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफल देते हों और अपने उच्च लागत उधारियों के प्रतिस्थापन को सिद्ध करें।

ऋण वहन क्षमता: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 में उत्तराखण्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य (40.00 *प्रतिशत*) के सापेक्ष ऋण स रा घ उ[1] अनुपात ने 2008-09 से 2012-13 तक 29.05 *प्रतिशत* से 23.57 *प्रतिशत* की निम्नोनमुखी प्रवृति दर्शायी।

वित्तीय वर्ष के अन्त में जमाव से बचने के लिये उधारियों की तिथिपत्र सुस्थापित रखना तथा ऋण भुगतानों की परिपक्वता की रूपरेखा की स्पष्ट समझ, विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन में दीर्घकालिक लाभ देंगे।

भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियों की अनदेखी: यहाँ उपभोगित राशियों की निगरानी हेतु न तो कोई एकल अभिकरण है और न ही कोई तैयार आँकड़े उपलब्ध है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में किसी वित्तीय वर्ष विशेष में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली मुख्य चिन्हित योजनाओं व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, जो भारत सरकार द्वारा सीधे वित्त पोषित हैं, के अन्तर्गत वास्तव में कितना व्यय हुआ है।

इन निधियों के उचित लेखांकन को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रणाली को व्यवहार में लाना होगा और इसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु अद्यतन सूचनाओं को राज्य सरकार तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा वैधता प्रदान की जानी चाहिये।

---

[1] प्रचलित/बाजार दरों पर। हालांकि, पिछले प्रतिवेदनों में ऋण-जी एस डी पी अनुपात स्थिर मूल्यों की जी एस डी पी पर आकलित किया जाता था।

[2] जिसको निधियों के उपयोग में कमी के रूप में भी बताया जा सकता है।

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण : राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाएँ इस वर्ष के दौरान सुदृढ़ नहीं थीं जिसमें बजटीय त्रुटियाँ, निरन्तर बचत[2], आधिक्य, प्रावधान के बिना व्यय और चालू वित्त वर्ष में प्रतिपूर्ति किए बिना आकस्मिकता निधि से आहरण शामिल था। बहुत से प्रकरणों में प्रत्याशित बचत या तो अभ्यर्पित नहीं की गई या फिर साल के एकदम अन्त में, मार्च महीने में, अभ्यर्पित की गई जिससे अन्य विकास प्रयोजनों हेतु इन निधियों की उपलब्धता की कोई गुंजाइश नहीं बची। कई विभागों द्वारा आवश्यकता से अधिक आहरण, समुचित स्पष्टीकरण के बिना पुनर्विनियोग का आश्रय लेकर तथा निधियों के प्रावधान के बिना व्यय करके वित्तीय नियमों को ताक पर रख दिया गया था। वित्तीय वर्ष के अन्त में निधियों की अवमुक्ति तथा पर्याप्त निधियों का अभ्यर्पण चिन्ता का विषय है क्योंकि निधियों का सार्थक रुप से प्रयोग नहीं किया जा सका था।

वित्तीय प्रबन्धन में ऐसी कमियों से बचने के लिये बजटीय नियन्त्रण को सख्ती से निगरानी किया जाना चाहिये। वित्तीय वर्ष के अन्त में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण आदेश जारी करने से बचा जाना चाहिए। आकस्मिक बिलों के सार के नियत समयावधि के दौरान समायोजन सुनिश्चित करने हेतु नियन्त्रण-अधिकारियों द्वारा एक नजदीकी एवं कठोर अनुश्रवण तंत्र व्यवहार में लाया जाना चाहिए।

वित्तीय प्रतिवेदन: विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं तथा विनिर्देशों का राज्य सरकार द्वारा किया गया अनुपालन असन्तोषजनक था जैसा कि ऋण एवं अनुदानों के विरूद्ध विभिन्न अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब से स्पष्ट है। कुछ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखा के प्रस्तुतीकरण में भी विलम्ब पाए गए थे। हानि तथा दुर्विनियोग के प्रकरण भी थे।

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लम्बित वार्षिक लेखों के अन्तिमीकरण के लिए सरकारी विभागों को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। दुर्विनियोग के प्रकरणों में दोषियों को दण्डित करने हेतु विभागीय जाँचों में तेजी लायी जानी चाहिए।

अध्याय – 1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय- 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय समग्रों की विगत प्रवृतियों और इसकी संगठनात्मक रुपरेखा के मानदंडों के द्वारा राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है । **परिशिष्ट-1.1** राज्य सरकार के वित्त लेखे, जिस पर यह प्रतिवेदन आधारित है, के संरचना और खाके को प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.2** राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्यपद्धति की रुपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

1.1 उत्तराखण्ड की रूपरेखा

उत्तराखण्ड, भारत सरकार द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (एस सी एस) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भारत सरकार (भा स) द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसका 90 *प्रतिशत* अंश अनुदान एवं 10 *प्रतिशत* ऋण का अनुपात होता है जो अविशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें केन्द्रीय सहायता 30 *प्रतिशत* अनुदान एवं 70 *प्रतिशत* ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुयी तथा वर्ष 2003-04 से 2012-13 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद[1] (स रा घ उ) में प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक विकास दर 19.80 *प्रतिशत* रही।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता दर और जन्म पर शिशु मृत्यु दर ने दर्शाया कि राज्य में अखिल भारतीय औसत से बेहतर साक्षर और कम मृत्यु दर है। राज्य में बी पी एल जनसंख्या अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी **(परिशिष्ट- 1)**।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)

स रा घ उ एक निर्धारित समय में राज्य में सरकारी आधार पर मान्यता प्राप्त उत्पादित सामग्रियों और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के स रा घ उ की वृद्दि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन निर्वाह स्तर को दर्शाता है। भारत के स घ उ की वार्षिक वृद्धि का प्रचलित दरों पर रूख नीचे प्रदर्शित है:

प्रचलित दरों पर स घ उ और स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (त्व. आ.)*	2012-13 (अ. आ.)*
भारत का स घ उ *(₹ करोड़ में)*	53,03,566	61,08,903	72,66,967	83,53,495	94,61,013
स घ उ की वृद्धि दर *(प्रतिशतता)*	*15.76*	*15.18*	*18.96*	*14.95*	*13.26*
राज्य का स रा घ उ *(₹ करोड़ में)*	56,025	70,730	83,966	94,159	1,08,343
स रा घ उ की विकास दर *(प्रतिशतता)*	*22.18*	*26.25*	*18.71*	*12.14*	*15.06*

श्रोत : निदेशक, अर्थ एवं संख्या,उत्तराखंड

** त्व. आ. - त्वरित आगणन और अ.आ. – अग्रिम आगणन*

[1] परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

स रा घ उ की वृद्धि दर स घ उ की तुलना में 2008-09 से 2012-13 में परिवर्तनशील रही। स रा घ उ की वृद्दि दर 2008-09 और 2009-10 में स घ उ की तुलना में अधिक थी। यह वर्ष 2010-11 में लगभग समरूप थी। 2011-12 में यह कम लेकिन 2012-13 में उच्चतर दिशा में रही।

राज्य सरकार के मुख्य राजकोषीय समग्रों में मुख्य परिवर्तन, वर्ष 2009-10 के राजस्व आधिक्य का राजस्व घाटे में परिवर्तित हो जाना था, जो वर्ष 2010-11 में लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) हो गया और अंततः वर्ष 2011-12 में राजस्व आधिक्य (₹ 716 करोड़) में परिवर्तित हो गया जो चालू वर्ष में और बढ़कर ₹ 1,787 करोड़ पर पहुँच गया। चालू वर्ष में, राजकोषीय घाटा ₹ 1,600 करोड़ पर, स रा घ उ के लगभग 1.48 *प्रतिशत* के आस-पास टिका रहा, तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) द्वारा निर्धारित मानक 3.50 *प्रतिशत* से काफी नीचे है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 (ते वि आ की सिफारिश पर मार्च 2011 में संशोधित) और राज्य की मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) द्वारा, राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) का सारांश **परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)** में दिया गया है।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेन का सार

तालिका-1.1, गत वर्ष (2011-12) के सापेक्ष चालू वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेनदेन का सार प्रस्तुत करती है जबकि **परिशिष्ट-1.4** गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका-1.1

चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
					आयोजनेत्तर	आयोजनागत	कुल
भाग-अः राजस्व							
कर राजस्व	**5,615.62**	**6,414.24**	सामान्य सेवाएँ	**4,475.11**	**5,368.13**	**4.10**	**5,372.23**
करेत्तर राजस्व	**1,136.13**	**1,602.88**	सामाजिक सेवाएँ	**6,019.65**	**4,146.27**	**1,949.57**	**6,095.84**
संघीय करों/शुल्कों का अंश	**2,866.04**	**3,272.88**	आर्थिक सेवाएँ	**2,101.63**	**1,522.10**	**473.19**	**1,995.29**
भारत सरकार से अनुदान	**4,073.45**	**4,457.22**	सहायता अनुदान और अंशदान	**378.80**	**496.86**	**--**	**496.86**
राजस्व प्राप्तियाँ	**13,691.24**	**15,747.22**	**राजस्व व्यय**	**12,975.19**	**11,533.36**	**2,426.86**	**13,960.22**
भाग –बः पूँजीगत और अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूँजीगत परिव्यय	**2,316.94**	**570.41**	**2,971.68**	**3,542.09**
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**90.65**	**428.44**	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	**246.83**	--	-	**272.57**
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	**2,335.52**	**2,967.43**	लोक ऋणों की चुकौतियाँ*	**1,015.79**	--	--	**1,472.21**
--	**--**	**--**	आकस्मिकता निधि को विनियोग	**(-)400.00**	--	--	
आकस्मिकता निधि	**126.13**	**32.22**	आकस्मिकता निधि	**69.07**	--	--	**32.07**
लोक लेखा प्राप्तियाँ	**19,668.05**	**21,925.45**	लोक लेखा संवितरण	**19,832.00**	--	--	**20,961.24**
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	**1,229.41**	**1085.18**	अंतिम रोकड़ शेष	**1,085.18**	--	--	**1,945.54**
योग	**37,141.00**	**42,185.94**	**योग**	**37,141.00**	**--**	**--**	**42,185.94**

* *इसमें अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेनदेन शामिल नहीं हैं।*

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैः

- राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष के सापेक्ष ₹ 2,056 करोड़ (15.02 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 799 करोड़), करेत्तर राजस्व (₹ 467 करोड़), संघ के करों / शुल्कों मे राज्य के अंश (₹ 407 करोड़) और भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों (₹ 384 करोड़) में बढ़ोत्तरी के कारण थी।
- पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 985 करोड़ (7.59 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, जैसा कि अनुवर्ती **प्रस्तर-1.6.1** में वर्णित है।
- पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में गत वर्ष से ₹ 1,225 करोड़ (52.88 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जैसा कि अनुवर्ती **प्रस्तर 1.6.1** में वर्णित है।
- ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 91 करोड़ (2011-12) से बढ़कर ₹ 428 करोड़ (370 *प्रतिशत*) हो गयी। यह मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्अदायगी (₹ 422 करोड़) के कारण था। वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण ₹ 26 करोड़ बढ़े (₹ 247 करोड़ से ₹ 273 करोड़)। वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्य प्राप्तिकर्ता कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप (₹ 159 करोड़) और ऊर्जा खण्ड (₹ 84 करोड़) थे।
- वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण में वृद्धि (₹ 644 करोड़) के कारण केन्द्र सरकार से लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 632 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई। तथापि, केन्द्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों की प्राप्तियों में गिरावट थी (₹ 12 करोड़)।
- उचन्त एवं विविध (₹ 2,644 करोड़), प्रेषण (₹ 67 करोड़) एवं जमाओं और अग्रिमों (₹ 29 करोड़) में वृद्धि के कारण लोक लेखा प्राप्तियाँ ₹ 2,257 करोड़ से बढ़ गई। यह आंशिक रूप से आरक्षित निधियों (₹ 369 करोड़) और लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि में कमी (₹ 113 करोड़) से प्रतिसंतुलित हुयी। लोक लेखा संवितरण भी उचन्त एवं विविध (₹ 1,752 करोड़) और लघु बचतों एवं भविष्य निधियों इत्यादि (₹ 242 करोड़) में वृद्धि जो आंशिक रूप से आरक्षित निधियों (₹ 410 करोड़), प्रेषण (₹ 297 करोड़) और जमाओं एवं अग्रिमों (₹ 157 करोड़) में कमी के कारण प्रतिसंतुलित हुई, के कारण ₹ 1,129 करोड़ से बढ़ गया **(परिशिष्ट 1.4)**।
- वर्ष 2011-12 के अन्तिम अवशेष की तुलना में वर्ष के अन्त में राज्य का रोकड़ शेष ₹ 860 करोड़ बढ़ गया।

वर्ष 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे लाने के पश्चात सरकार वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त करने में सफल हुई। चालू वर्ष 2012-13 में राजस्व अधिक्य ने पुनः 1,071 करोड़ की वृद्धि दर्शाई और ₹ 1,787 करोड़ पर रहा जो कि मुख्यतः राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 1,265 करोड़) के कारण था । राजकोषीय घाटा, जो वर्ष 2011-12 में ₹ 1,757 करोड़ था, घटकर ₹ 1,600 करोड़ (स रा घ उ का 1.48 *प्रतिशत*) तक नीचे आ गया, जिससे राज्य की राजकोषीय दशा में और सुधार हुआ।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बजट में प्रावधानित मुख्य राजकोषीय चर जो कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों और राज्य के एफ आर बी एम अधिनियम में लक्षित थे **तालिका 1.2** में दिए गये हैं:

तालिका - 1.2

राजकोषीय चर	2012-13						
	एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	एम टी एफ पी में प्रक्षेपण	वास्तविक	वास्तविक के विरूद्ध प्रतिशत भिन्नता		
					एफ आर बी एम अधिनियम का लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	एम टी एफ पी प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+) *(₹ करोड़ में)*	मार्च 2015 तक शून्य तक नीचे लाना	(+) 442	(+)1226	(+) 1787	प्राप्त किया	(+) 304	(+) 46
राजकोषीय घाटा/स रा घ उ (*प्रतिशत* में)	3.50	3.12	3.09	1.48	58	53	52
सरकार के कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (*प्रतिशत* में)	40.00	23.27	23.19	23.57	41	1.29	1.64

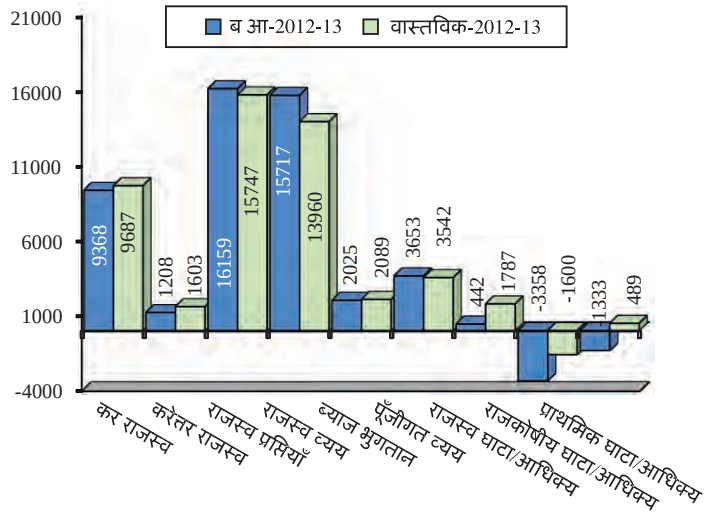
उत्तराखण्ड में, एफ आर बी एम अधिनियम अक्टूबर 2005 में अधिनियमित हुआ तथा राज्य सरकार को राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण हेतु कदम उठाने हेतु मार्ग प्रशस्त हो गया। तत्पश्चात्, प्रथम राजकोषीय सुधार पथ (रा सु प) मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण के रूप में वर्ष 2004-05 में वार्षिक बजट के साथ राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया गया।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित होने के समय से राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार, वर्ष 2009-10 को छोड़कर राजस्व आधिक्य बनाये रखने में वर्षवार सफल रहा। राज्य का राजकोषीय घाटा भी XII और XIII वित्त आयोगों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रहा।

1.1.3 बजट आकलन एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज विशेष राजकोषीय वर्ष के राजस्व और व्यय के प्रक्षेपों या आकलनों का विवरण उपलब्ध कराता है। राजस्व और व्यय के प्राक्कलनों की परिशुद्धता की महत्ता राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में सर्वमान्य है। बजट आकलनों से भिन्नता विविध कारणों से, जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में है, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों के न पाने और अनुकूलतम स्तर न पाने का संकेतक है। वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न संघटकों के सन्दर्भ में वास्तविकों की तुलना में बजट आकलन ने मिश्रित रूझान प्रदर्शित किए:

चार्ट -1.1 चयनित राजकोषीय मापदण्डः वास्तविक की तुलना में बजट आकलन (*₹ करोड़ में*)



- सहायता अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति ₹ 1,125 करोड़ (20.15 *प्रतिशत*) के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 412 करोड़ से कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व ने तीव्र बढ़ोत्तरी दर्शायी तथा वह चालू वर्ष के ब आ के सापेक्ष ₹ 395 करोड़ (32.69 *प्रतिशत*) अधिक था। राज्य का कर राजस्व भी ब आ के मुकाबले ₹ 319 करोड़ (3.41 *प्रतिशत*) अधिक था।
- राजस्व व्यय, वर्ष के बजट आकलनों से ₹ 1,757 करोड़ (11.18 *प्रतिशत*) कम था।
- मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास के अन्तर्गत कम संवितरण के कारण पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत व्यय ₹ 111 करोड़ (3.04 *प्रतिशत*) तक अप्रयुक्त रहा।
- राजस्व, राजकोषीय तथा प्रारम्भिक घाटों के लिये वर्ष 2012-13 के बजटीय पूर्वानुमान, एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 (वर्ष 2011 के उत्तराखण्ड अधिनियम सं. 72 द्वारा संशोधित) तथा ते वि आयोग की संस्तुतियों के अनुसार थे **(चार्ट-1.1)**। वर्ष 2012-13 हेतु वास्तविक, प्रक्षेपों के अन्तर्गत थे।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्णतया या अंशतया लाभ पहुँचाने की दृष्टि से सम्पूर्ण बजट में से प्रस्तावित व्यय को दर्शाता है। इस हेतु राज्य बजट में प्राविधान वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ किए गए। जेण्डर बजट प्रलेख में वर्षवार प्राविधान **तालिका 1.3** में वर्णित है:

तालिका 1.3

वर्ष 2008-13 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	परिव्यय			व्यय			
	श्रेणी I	श्रेणी II	योग	श्रेणी I	श्रेणी II	योग	आच्छादित विभाग
2008-09	165.36	310.42	475.78	119.63	741.64	861.27	20
2009-10	170.94	1,160.74	1,331.68	158.05	1,219.98	1,378.03	24
2010-11	255.19	1,274.24	1,529.43	177.31	1,324.59	1,501.90	26
2011-12	215.63	1,614.37	1,830.00	201.30	1,104.59	1,305.89	26
2012-13	316.41	1,921.49	2,237.90	280.26	*	280.26	29
योग	**1,123.53**	**6,281.26**	**7,404.79**	**936.55**	**4,390.80**	**5327.35**	

स्रोतः बजट प्रलेखों और विनियोग लेखे

* राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

जेण्डर बजटिंग के लिए बजट प्राविधान श्रेणी I और श्रेणी II में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी I के अन्तर्गत प्राविधान शत-प्रतिशत महिलाओं के कल्याण हेतु होता है। श्रेणी II में कुल बजट प्राविधानों में से 30 *प्रतिशत* प्राविधान अनन्य रूप से महिलाओं के विकास हेतु प्रावधानित होता है। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान दोनों श्रेणियों में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए प्राविधानों ने वर्ष 2008-09 में ₹ 475.78 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 2,237.90 करोड़ की अभूतपूर्व वृद्धि दर्शायी।

तथापि, जेण्डर बजटिंग के अधीन कार्यान्वित योजनाओं के सही क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार राज्य स्तर पर कोई समर्पित जेण्डर बजटिंग प्रकोष्ठ नहीं गठित किया गया। राज्य सरकार उन लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध कराने की स्थिति में भी नहीं था जो जेण्डर बजटिंग से लाभान्वित हुए। मूल्यांकन अध्ययन के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में जेण्डर बजटिंग का उपयोग महिलाओं के उत्थान हेतु एक उपकरण की भाँति हो रहा था।

श्रेणी I के अन्तर्गत परिवहन और अनुसूचित जाति कल्याण विभागों में जेण्डर बजट प्रलेख 2012-13 के विश्लेषण ने निम्नलिखित दर्शाया:

परिवहनः

जेण्डर बजट प्रलेख 2012-13 श्रेणी I के अन्तर्गत परिवहन विभाग की केवल एक योजना दर्शाता है। इसका विवरण **तालिका 1.3 अ** में प्रदर्शित है:

तालिका 1.3 अ

परिवहन विभाग के श्रेणी I के अन्तर्गत योजना

(₹ करोड़ में)

योजना	आवंटन	व्यय*	बचत	बचत का प्रतिशत
उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में छात्राओं के निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति	5.00	0.80	4.20	84

** विनियोग लेखे*

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान महिला सशक्तिकरण हेतु एक मात्र अभिकल्पित योजना के ₹ 5.00 करोड़ आवंटन के सापेक्ष केवल ₹ 0.80 करोड़ (16 *प्रतिशत*) का ही उपयोग किया जा सका।

अनुसूचित जातियों का कल्याणः

जेण्डर बजट प्रलेख 2012-13, अनुसूचित जाति विभाग की श्रेणी । की चार योजनाओं को दर्शाती है। इसका विवरण **तालिका 1.3 ब** में प्रदर्शित हैः

तालिका 1.3 ब

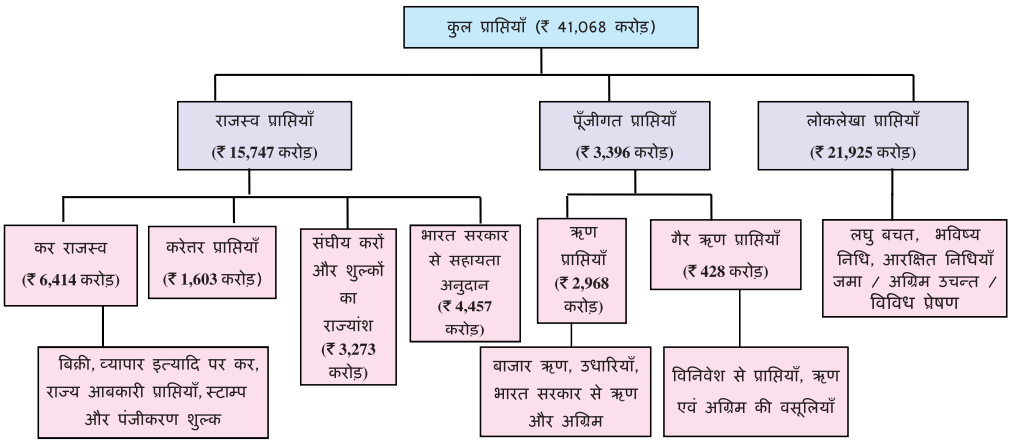
अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की श्रेणी । के अन्तर्गत योजना *(₹ करोड़ में)*

योजना	आवंटन	व्यय*	बचत	व्यय का प्रतिशत
अनुसूचित जाति की बालिकाओं के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्याधन योजना	6.00	6.00	0.00	*0.00*
विधवा के साथ विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार	0.007	0.004	0.003	*42.86*
आवास विहीन विधवाओं के भरणपोषण तथा उनके बच्चों की व्यवस्थापन हेतु अनुदान	11.70	11.64	0.06	*0.51*
बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण	3.00	0.50	2.50	*83.33*

** विनियोग लेखे*

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि महिलाओं के उत्थान हेतु अभिकल्पित चार योजनाओं में से केवल एक योजना ही सम्बन्धित विभाग द्वारा पूर्णरूपेण क्रियान्वित की जा सकी। एक योजना 80 *प्रतिशत* से अधिक पिछड़ी रही क्योंकि उसमें 83.33 *प्रतिशत* की बचत थी। अन्य दो योजनाओं की प्रगति भी स्तरोनुकूल नहीं थी।

1.2 राज्य के संसाधन

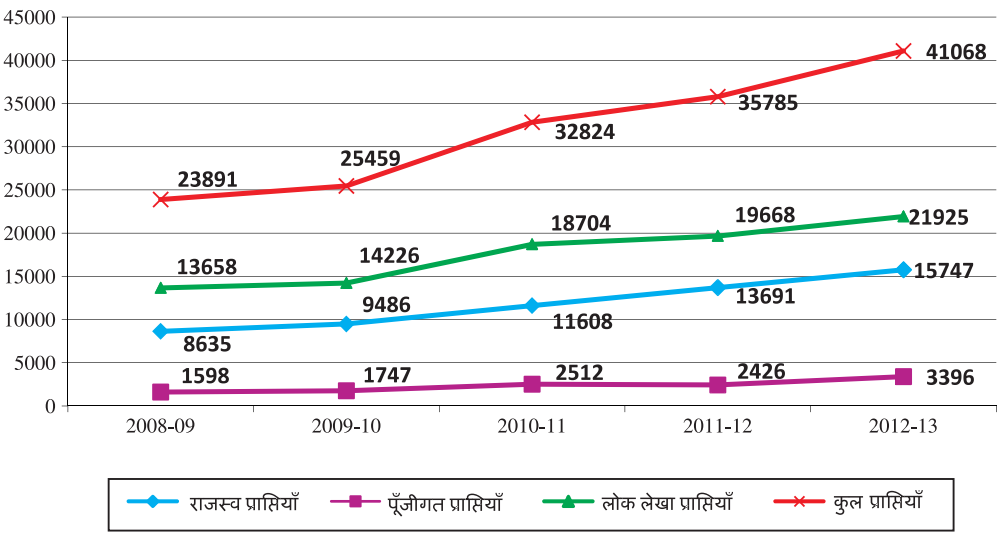


1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

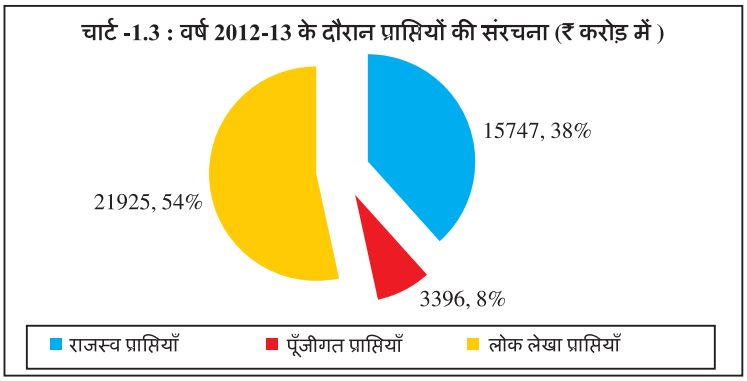
राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत राजस्व प्राप्तियाँ- जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार

ऋण, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में उपलब्ध निधियों के वितरण के बाद बची निधियों को सरकार द्वारा अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। **तालिका 1.1** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है, जैसा इसके वार्षिक वित्तीय लेखों **(परिशिष्ट-1.1)** में दर्ज है; जबकि **चार्ट 1.2**, वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों का चित्रण करता है। **चार्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटकों को चित्रित करता है।

चार्ट-1.2: प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



चार्ट -1.3 : वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्तियों की संरचना (₹ करोड़ में)



वर्ष 2008-09 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) ₹ 23,891 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 41,068 करोड़ (71.90 *प्रतिशत*) हो गयी। वर्ष 2012-13 की ₹ 41,068 करोड़ की प्राप्तियों में से 54 *प्रतिशत* प्राप्तियाँ (₹ 21,925 करोड़) लोक लेखे से थी जबकि कुल प्राप्तियों का 38 *प्रतिशत* (₹ 15,747 करोड़) व आठ *प्रतिशत* (₹ 3,396 करोड़) भाग राजस्व प्राप्तियों व उधारियों आदि से आया।

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 15.02 *प्रतिशत* बढ़ गईं। यद्यपि, वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों के अंश में कोई बदलाव नहीं देखा गया। वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों मे पूँजीगत प्राप्तियों के अंश की बढ़ोत्तरी देखी गयी जिसका कारण ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में बढ़ोत्तरी का होना था। **(तालिका-1.1 का संदर्भ लें)।**

लोक लेखा प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

- लघु बचत, भविष्य निधि आदि और आरक्षित निधियों की प्राप्तियाँ, गत वर्ष की तुलना में क्रमश: ₹ 113 करोड़ और ₹ 369 करोड़ कम हो गई।
- वर्ष के दौरान उचन्त एवं विविध प्राप्तियों में ₹ 2,644 करोड़ (21.38 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो कि मुख्यतः चेकों एवं देयकों के उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत हुई वृद्धि (₹ 2,411 करोड) के कारण थी। यह उचन्त शीर्ष चेक जारी करते समय क्रेडिट किया जाता है और बैंक द्वारा चेक के भुगतान की सूचना प्राप्त होने पर खारिज किया जाता है।

1.2.2 राज्य के बजट से इतर राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माने गये विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों[2] को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की जाती हैं। ये निधियाँ, राज्य बजट/राज्य कोषागार तन्त्र के माध्यम से नहीं आती हैं। अतः राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय तथा इसके साथ-साथ उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय आँकड़े/मापदण्ड अधो-आकलित रहे। समुच्चय संसाधनों की उपलब्धता पर एक निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने के लिए, राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर अन्तरित निधियाँ **परिशिष्ट-1.5** में दर्शायी गयी हैं। मुख्य कार्यक्रमों/योजनाओं को अन्तरित उल्लेखनीय धनराशि **तालिका 1.4** में दर्शायी गई है:

तालिका-1.4

राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ *(₹ करोड़ में)*

क्रम. सं.	कार्यक्रम/योजना	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राशि
1	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड, मक्कावाला, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	25.42
2	वन एवं वन्य जीव संस्थानों को सहायता अनुदान	वन अनुसंधान संस्थान (भारतीय वनीकरण अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद), पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹109.76 करोड़) और डब्लू आई आई (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 12.21 करोड़)	121.97
3	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	विभिन्न जिलों के डी आर डी ए, पंजीकृत समितियों (सरकारी स्वायत्त निकाय)	268.27
4	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	एस डब्लू एस एम उत्तराखण्ड देहरादून, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	74.28

[2] परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

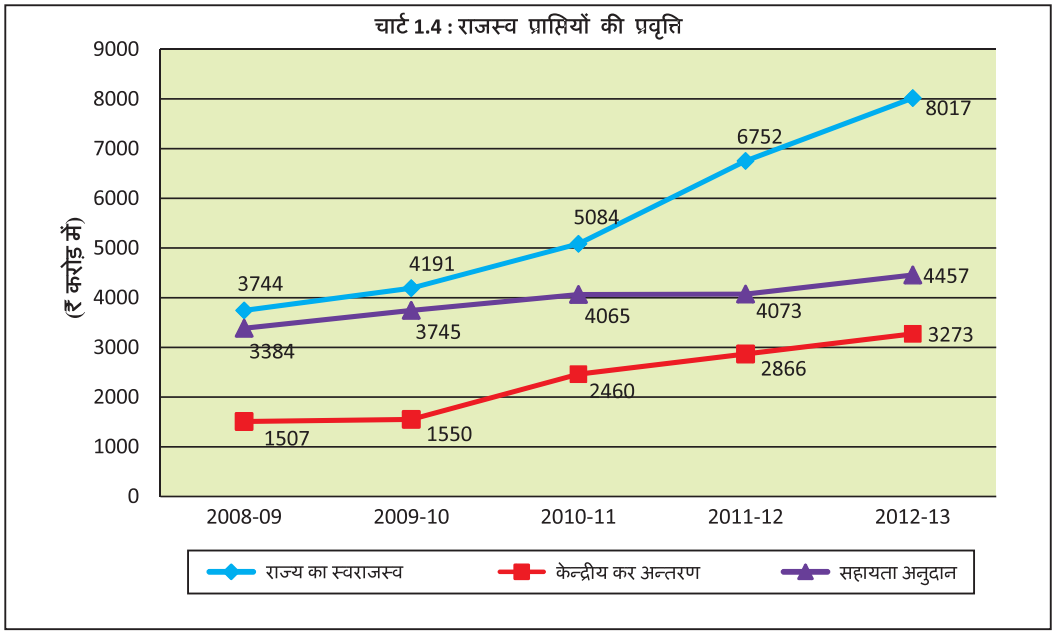
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एन आर एच एम और जे आई आई टी) केन्द्र प्रायोजित	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 110.34 करोड़) और एस पी ओ उत्तराखण्ड, देहरादून (राज्य सरकार पी एस यू) (₹ 3.04 करोड़)	113.38
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)	उत्तराखण्ड ग्राम सड़क विकास समिति देहरादून, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	151.24
7	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद, पंजीकृत संस्थायें (सरकारी स्वायत्त निकाय)	96.64
8	ग्रामीण आवास आई ए वाई	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	40.81
9	सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	180.45
10	भारतीय तकनीकी संस्थान को सहायता	आई आई टी रूड़की, उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	146.20
योग			**1218.66**

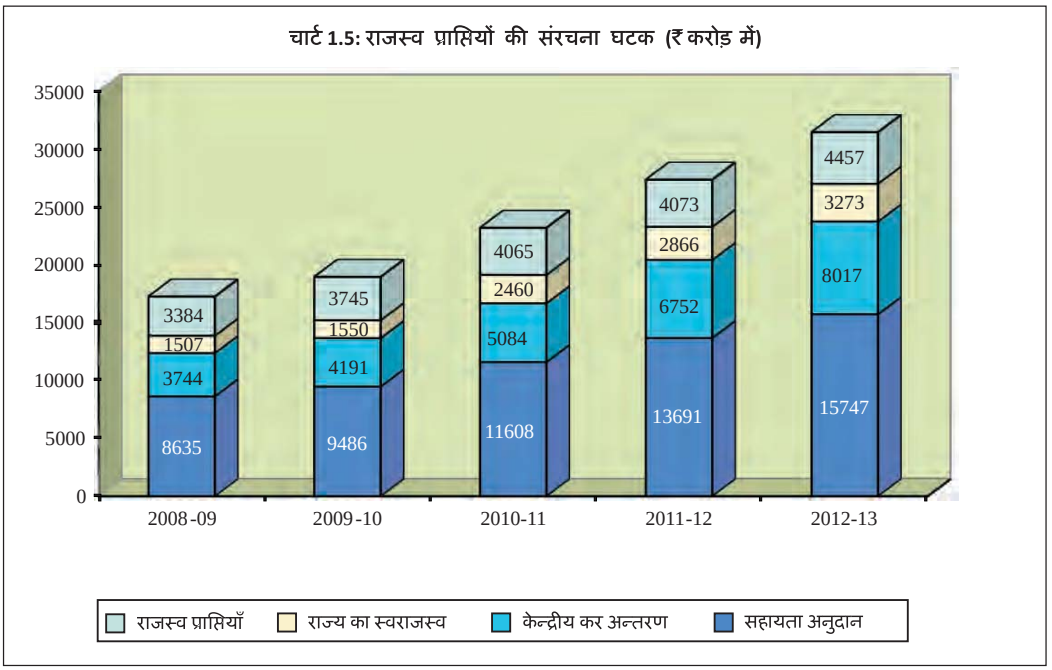
स्रोतः कन्ट्रोलर जनरल ऑफ एकाउन्ट्स वैबसाइट का सेण्ट्रल प्लान स्कीम मानिटिरिंग सिस्टम

तालिका 1.4 सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अधीन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के विविध मंत्रालयों से उत्तराखण्ड में विभिन्न अभिकरणों द्वारा सीधे प्राप्त उल्लेखनीय धनराशियों को दर्शाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान इन निधियों का अधिकाई अंश प्राप्त करने वाले कार्यक्रम (i) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना- ₹ 268.27 करोड़ (17.11 *प्रतिशत*), (ii) सर्व शिक्षा अभियान- ₹ 180.45 करोड़ (11.51 *प्रतिशत*), (iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ₹ 151.24 करोड़ (9.65 *प्रतिशत*) (iv) भारतीय तकनीकी संस्थान को सहायता ₹ 146.20 करोड़ (9.32 *प्रतिशत*) (v) वन व वन्य जीव संस्थानों को सहायता अनुदान ₹ 121.97 करोड़ (7.78 *प्रतिशत*), (vi) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ₹ 113.38 करोड़ (7.23 *प्रतिशत*), (vii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ₹ 96.64 करोड़ (6.16 *प्रतिशत*) और (viii) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ₹ 74.28 करोड़ (4.74 *प्रतिशत*) थे। इस प्रकार, वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 1,568 करोड़ **(परिशिष्ट-1.5)** के अन्तरण से, राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 41,068 करोड़ से बढ़कर ₹ 42,636 करोड़ हो गयी। यह भी स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा सीधे क्रियान्वयन अभिकरणों को स्थानान्तरित निधियों के अनुश्रवण हेतु कोई एकल अभिकरण नहीं है। इस प्रकार तत्काल रूप से कोई आँकडे उपलब्ध नहीं हैं जिससे ज्ञात हो कि किसी विशेष वर्ष में मुख्य चिन्हित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, जिन्हें राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, पर वास्तविक रूप से व्यय की गयी निधि कितनी है।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का **विवरण-11**, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों के संघटक और प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3** में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः **चार्ट 1.4** तथा **1.5** में भी चित्रित किया गया है:





राजस्व प्राप्तियों ने 2008-09 से 2012-13 की अवधि में निरंतर वृद्धि दर्शाई। यह 14.92 *प्रतिशत* की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2008-09 में ₹ 8,635 करोड़ से वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 15,747 करोड़ हो गयी।

जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 50.91 *प्रतिशत* राज्य के निजी कर एवं करेत्तर राजस्व से आया, केन्द्रीय कर अन्तरणों एवं सहायता अनुदान के समुच्चयों ने शेष 49.09 *प्रतिशत* का योगदान किया।

औसतन, वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 46.31 *प्रतिशत* योगदान स्वयं राज्य की कर प्राप्तियों का रहा **(चार्ट 1.5)**। इससे भारत सरकार से सहायता अनुदान पर राज्य की निरन्तर निर्भरता प्रदर्शित हुई, क्योंकि राज्य अपने कर-आधार को विस्तृत करने में अक्षम रहा।

स रा घा उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को निम्न **तालिका-1.5** में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका-1.5

स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) *(₹ करोड़ में)*	**8,635**	**9,486**	**11,608**	**13,691**	**15,747**
रा प्रा की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	9.43	9.86	22.37	17.94	15.02
रा प्रा / स रा घ उ (*प्रतिशत*)	15.41	13.32	14.08	14.38	14.53
उत्प्लावकता अनुपात[3]					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	0.43	0.38	1.20	1.48	1.00
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	0.50	0.64	1.27	2.26	0.94

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई। वृद्धि दर वर्ष 2010-11 में 22.37 *प्रतिशत* बढ़ गयी और इसके पश्चात वृद्धि दर घटने लगी और वर्ष 2012-13 में 15.02 *प्रतिशत* पर आ गई। वर्ष 2012-13 की वृद्धि दर विगत वर्ष की अपेक्षा 2.92 *प्रतिशत* घट गई। स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के निजी करों का उत्प्लावकता अनुपात वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान एक से भी नीचे था और 2010-11 और 2011-12 में वृद्धि दर्शाई। गत वर्ष के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कम उतप्लावकता देखी गई जो यह दर्शाता है कि स रा घ उ की वृद्धि के अनुपात में कर संचय कम हुआ था। वर्ष 2012-13 में, स रा घ उ में प्रत्येक एक *प्रतिशत* के वृद्धि के लिए राज्य के निजी कर में 0.94 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होती हैं, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं। राज्य के अपने संसाधनों के सन्दर्भ में तेरहवें वित्त आयोग अनुमानों, बजट अनुमानों और एम टी एफ पी अनुमानों के सापेक्ष वास्तविकों को **तालिका-1.6** में दर्शाया गया है:

[3] परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.6

राज्य के अपने संसाधनः अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

	तेरहवाँ वित्त आयोग अनुमान	बजट अनुमान	ए टी एफ पी अनुमान	वास्तविक	वास्तविक में प्रतिशत का अन्तर		
					तेरहवाँ वित्त आयोग अनुमान	बजट अनुमान	एमटीएफपी अनुमान
कर राजस्व	5,459	5,980	6,050	6,414	*17.49*	*7.26*	*6.02*
करेत्तर राजस्व	991	1,208	1,517	1,603	*61.76*	*32.70*	*5.67*

जैसा कि **तालिका-1.6** में प्रदर्शित है, तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) के अनुमानों के सापेक्ष राज्य का राजस्व, जो कि वर्ष 2012-13 में 6,414 करोड़ रहा, तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारित मानक ₹ 5,459 करोड़ से अधिक था।

इसी प्रकार, वर्ष के दौरान राज्य का स्व कर राजस्व सरकार के बजट प्रावधानों से ₹ 434 करोड़ अधिक रहा। यह घटक मध्यकालीन राजकोषीय पथ विवरण (म रा प वि) के निर्धारित लक्ष्य ₹ 6,050 करोड़ से भी अधिक रहा।

₹ 1,603 करोड़ पर करेत्तर राजस्व (करे रा), तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारित मानकों से ₹ 612 करोड़ अधिक था। करेत्तर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ, बजट अनुमान एवं म रा प वि में निर्धारित लक्ष्य (₹ 1,517 करोड़) से क्रमशः ₹ 395 करोड़ एवं ₹ 86 करोड़ अधिक थीं।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सन्दर्भ में सकल संग्रह **तालिका 1.7** में दी गई है:

तालिका - 1.7

राज्य के अपने संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,911(*17*)	2,247(*18*)	2,940 (*31*)	3,644(*24*)	4,289 (*18*)
राज्य आबकारी	528 (*19*)	705 (*34*)	756 (*7*)	844 (*12*)	1,118 (*32*)
वाहनों पर कर	167 (*8*)	184 (*10*)	227 (*23*)	335 (*48*)	304 (-*9*)
स्टांप प्रभार और पंजीकरण शुल्क	357 (-*16*)	399 (*12*)	440 (*10*)	524 (*19*)	648 (*24*)
माल एवं यात्रियों पर कर	06	--	--	--	--
अन्य कर	76 (-16)	24 (-68)	42 (75)	269 (540)	55 (-80)
योग	**3,045** (*11*)	**3,559** (*17*)	**4,405** (*24*)	**5,616** (*27*)	**6,414** (*14*)

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

राज्य का निजी कर राजस्व, 2011-12 में 14.21 *प्रतिशत* वृद्धि के साथ 5,616 करोड़ से 2012-13 में ₹ 6,414 करोड़ हो गया, हालांकि, वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में 27 *प्रतिशत* से 14 *प्रतिशत* गिरी। बिक्री, व्यापार आदि पर कर न केवल कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा (66.87 *प्रतिशत*) रहा बल्कि उसमें पिछले वर्ष के सापेक्ष 17.70 *प्रतिशत* वृद्धि भी दर्ज की गई। राज्य के कर राजस्व का दूसरा मुख्य अंशदाता राज्य आबकारी था, जिसकी वृद्धि दर ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान मिश्रित रूझान दिखाए है।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर **तालिका - 1.8** में दी गई है:

तालिका - 1.8

करेत्तर राजस्व के प्राप्ति के रूझान

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज प्राप्तियाँ	68	54	54	51	115
लाभांश एवं लाभ	0.23	0.07	0.21	0.05	0.19
अन्य करेत्तर राजस्व	630.77	577.93	623.79	1048.95	1487.81
योग	699	632	678	1136	1603
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	*4.64*	*(-) 9.59*	*7.28*	*67.55*	*41.11*

करेत्तर राजस्व, वर्ष 2008-09 में थोड़ा सुधार दिखाने के उपरान्त, वर्ष 2009-10 में 10 *प्रतिशत* घटा। हालांकि, वर्ष 2010-11 में करे रा पुनः 7.28 *प्रतिशत* बढ़ा। वर्ष 2011-12 में यह प्रभावी तौर पर 67.56 *प्रतिशत* बढ़ गया। चालू वर्ष 2012-13 में भी इसने पुनः पिछले वर्ष की तुलना में 41.11 *प्रतिशत* का मात्रात्मक उछाल मुख्यत: पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभों के अंशदान एवं वसूलियों (₹ 301 करोड़) एवं ऊर्जा (₹ 108.80 करोड़) में वृद्धि के कारण दर्शाया।

करे रा में महत्वपूर्ण बढ़त पूर्ववर्ती समेकित राज्य उत्तर प्रदेश के पेंशन देयताओं का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के मध्य प्रभाजन के कारण था। परिणामत:, उत्तराखण्ड राज्य को, उत्तर प्रदेश से ₹ 703 करोड़ प्रभाजन के रूप में वर्ष के दौरान प्राप्त हुए।

वर्ष 2012-13 के दौरान करेत्तर राजस्व के प्रमुख अंशदाताओं में वानिकी एवं वन्य जीव (₹ 238 करोड़), ऊर्जा (₹ 150 करोड़), ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 115 करोड़) और अलौह एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 110 करोड़) थे। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि में करे रा में ब्याज प्राप्तियों का औसत योगदान 7.58 *प्रतिशत* था।

1.3.2 सहायता अनुदान

भारत सरकार से वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका - 1.9** में प्रदर्शित है:

तालिका - 1.9

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजनेत्तर अनुदान	1,270	1,183	1,435	762	869
राज्य योजना के लिए अनुदान	1,906	2,334	2,253	2,840	3,040
केन्द्रीय योजना के लिए अनुदान	08	11	21	10	8
केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए अनुदान	200	217	356	462	540
योग	**3,384**	**3,745**	**4,065**	**4,074**	**4,457**
विगत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	*11*	*11*	*9*	*00*	*9*
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	*39*	*39*	*35*	*30*	*28*

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि में भारत सरकार से सहायता अनुदान ने वृद्धि दर्शायी। यह वर्ष 2008-09 से ₹ 3,384 करोड़ से बढकर वर्ष 2012-13 में ₹ 4,457 करोड़ हो गयी। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि ₹ 383 करोड़ (9.40 *प्रतिशत*) मुख्य रूप में राज्य की आयोजनागत योजनाओं (₹ 200 करोड़), विभिन्न आयोजनेत्तर अनुदानों (₹ 107 करोड़) और केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदानों (₹ 78 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

1.3.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

संघीय करों तथा शुल्कों के राज्यांश के रूप में प्राप्तियाँ, 2011-12 के ₹ 2,866 करोड़ से ₹ 407 करोड़ (14.20 *प्रतिशत*) बढ़कर 2012-13 में ₹ 3,273 करोड़ हो गयी थीं। केन्द्रीय कर अन्तरण में समग्र वृद्धि (₹ 407 करोड़) मुख्यतः सेवा कर (₹ 136 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 131 करोड़), सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद कर (₹ 95 करोड़) और निगम कर (₹ 48 करोड़) में हुई वृद्धि के कारण थी जो कि सम्पत्ति कर में ₹ 3.00 करोड़ की कमी से प्रतिसंतुलित हुई।

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 3,063 करोड़ के अन्तरण की संस्तुति की थी उसमें 31 मार्च 2013 तक ₹ 950.13 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई। संस्तुतियों, वास्तविक अवमुक्ति और इसके उपयोग का विवरण **तालिका 1.10** में दिया गया है:

तालिका 1.10
सहायता अनुदान संस्तुत अन्तरण और वास्तविक अवमुक्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	अन्तरण	वि.आ. की संस्तुति	वास्तविक अवमुक्ति	प्रयुक्त धनराशि
1.	**स्थानीय निकाय**			
	(अ) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	386.42	166.64	124.02
	(ब) पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य दक्षता अनुदान	204.56		3.43
	(स) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	124.38	56.49	33.44
	(द) शहरी स्थानीय निकायों को सामान्य दक्षता अनुदान	65.84		
2.	**देवीय आपदा राहत**			
	(i) देवीय आपदा राहत निधि	585.14	211.48	105.89
	(ii) क्षमता निर्माण	20.00	12.00	8.00
3.	**परिणामी अनुदानों का सुधार**			
	(i) न्याय प्रदान में सुधार	102.22	30.66	20.41
	(ii) यू आई डी के निर्गमन हेतु प्रोत्साहन	36.00	3.60	00
	(iii) सांख्यिकीय प्रणाली सुधार	13.00	2.60	2.58
	(iv) कर्मचारी एवं पेंशन डाटाबेस	5.00	2.50	5.18
	(v) जिला इनोवेशन निधि	13.00	6.50	00.00
4.	**पर्यावरण सम्बन्धी अनुदान**			
	(i) वन	205.44	89.88	88.48
	(ii) जल क्षेत्र प्रबन्ध	76.00	19.00	00.00
5.	**प्राथमिक शिक्षा**	197.00	106.00	106.00
6.	**सड़कें एवं पुल**	329.00	149.00	149.00
7.	**राज्य हेतु विशिष्ट अनुदान**			
	(i) देहरादून हेतु मल निकास योजना	150.00	15.55	00.00
	(ii) पुलिस प्रशिक्षण और पुलिस अवसंरचना का उन्नयन	70.00	21.00	17.06

	(iii) पर्यटन विकास	100.00	14.78	11.15
	(iv) पाँच नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना	100.00	00.00	00.00
	(v) नये विधानसभा भवन का निर्माण	88.00	00.00	00.00
	(vi) संस्कृति विकास	45.00	11.25	00.00
	(vii) हल्द्वानी (नैनीताल) में अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय क्रीड़ा परिसर का निर्माण	25.00	00.00	00.00
	(viii) उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा परिषद, रूड़की का उन्नयन	17.00	00.00	00.00
	(ix) सीमा क्षेत्र विकास	105.00	31.20	00.00
	योग	**3063.00**	**950.13**	**674.64**

स्रोतः राज्य सरकार

भारत सरकार द्वारा ते वि आ की अनुशंसाओं के अनुसरण में वर्ष 2012-13 तक की गई अवमुक्ति और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/अभिकरणों द्वारा उपयोग की सूचना/आँकड़ों के विश्लेषण ने दर्शाया किः

- ₹ 950 करोड़ की अवमुक्त धनराशि में से राज्य सरकार मार्च 2013 तक केवल ₹ 675 करोड़ (71 *प्रतिशत*) ही उपयोग कर सकी।
- राज्य विशिष्ट अनुदानों में निधियों का कम उपयोग (70 *प्रतिशत*) देखा गया।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ या तो ऋणेत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे सरकारी कंपनियों / निगमों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियाँ और ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ अथवा ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं, जो कि समेकित निधि के लोक ऋण भाग में क्रेडिट की जाती है। लोक ऋण प्राप्तियाँ विस्तृत रूप मे दो श्रेणियों; (अ) संघ सरकार से ऋण/ अग्रिम (ब) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से नेगोसियेटेड ऋण या राज्य विकास ऋण निर्गमों के माध्यम से खुले बाजार की उधारियों, में विभाजित है । संघ सरकार से ऋणेत्तर पूँजीगत प्राप्तियों एवं ऋणों/ अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है और पूँजीगत प्राप्तियाँ मुख्यतः बैकों, वित्तीय संस्थानों एवं खुले बाजार से उधारियाँ हैं जैसा कि **तालिका 1.11** में वर्णित है:

तालिका 1.11
राजस्व संरचना एवं वृद्धि का रूझान

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों का स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ प्रा)	***1,598***	***1,748***	***2,512***	***2,427***	***3,396***
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	54	65	85	91	428
लोक ऋण प्राप्तियाँ	1,544	1,683	2,427	2,336	2,968
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	*11*	*9*	*44*	*(-)4*	*27*
ऋणेत्तर पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	*(-)21*	*20*	*31*	*7*	*370*
स रा घ उ की वृद्धि दर	*22.18*	*26.25*	*18.71*	*12.14*	*15.06*
पूँजीगत प्राप्तियाँ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*9*	*9*	*44*	*(-) 3*	*40*

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों की वृद्धि दर ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान बढ़ोत्तरी की प्रवृति दिखायी। यह 2009-10 से 2011-12 के दौरान लगातार 19 *प्रतिशत* की औसत दर से बढ़ी। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान वसूलियाँ मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र द्वारा पुनर्भुगतान (₹ 422 करोड़) के कारण थी।

1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

2008-09 से 2012-13 की अवधि में सरकारी प्राप्तियों के स्रोत बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों इत्यादि से ऋण प्राप्तियाँ बने रहे। राजस्व आधिक्य के साथ- साथ पर्याप्त रोकड़ शेष के बावजूद भी सरकार ने आंतरिक उधारियों द्वारा निधि का संचय किया।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

उत्तराखण्ड राज्य विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋण 90:10 के अनुपात में प्राप्त करता है। इसलिए भारत सरकार से ऋण के सन्दर्भ में राज्य सरकार के बकाया दायित्व, कुल लोक ऋण का केवल 2.52 *प्रतिशत* है।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ एवं वितरण के कतिपय लेनदेनों के सन्दर्भ में यथा लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तों, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है एवं ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। वितरणों के पश्चात शेष राशि सरकार के उपयोग के लिए है। **तालिका 1.12,** 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान सरकार की लोक लेखा प्राप्तियों को दर्शाती है:

तालिका 1.12

लोक लेखा प्राप्तियों के रूझान

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अधीन संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखा प्राप्तियाँ					
अ. लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	868	1,422	1,373	1,272	1,159
ब. आरक्षित निधियाँ	169	52	153	649	280
स. जमा एवं अग्रिम	1,748	2,223	2,464	2,331	2,359
द. उचन्त एवं विविध	7,846	9,387	11,460	12,366	15,010
य. प्रेषण	3,027	1,142	3,254	3,050	3,117
योग	**13,658**	**14,226**	**18,704**	**19,668**	**21,925**

तालिका 1.12 दर्शाती है कि लोक लेखा प्राप्तियाँ 2008-09 से 2012-13 तक ₹ 8,267 करोड़ (61 *प्रतिशत*) बढ़ गयी जो कि मुख्यतः उचन्त एवं विविध मे ₹ 7,164 करोड़ (91 *प्रतिशत*) वृद्धि के कारण थी।

1.6 संसाधनों का उपयोग

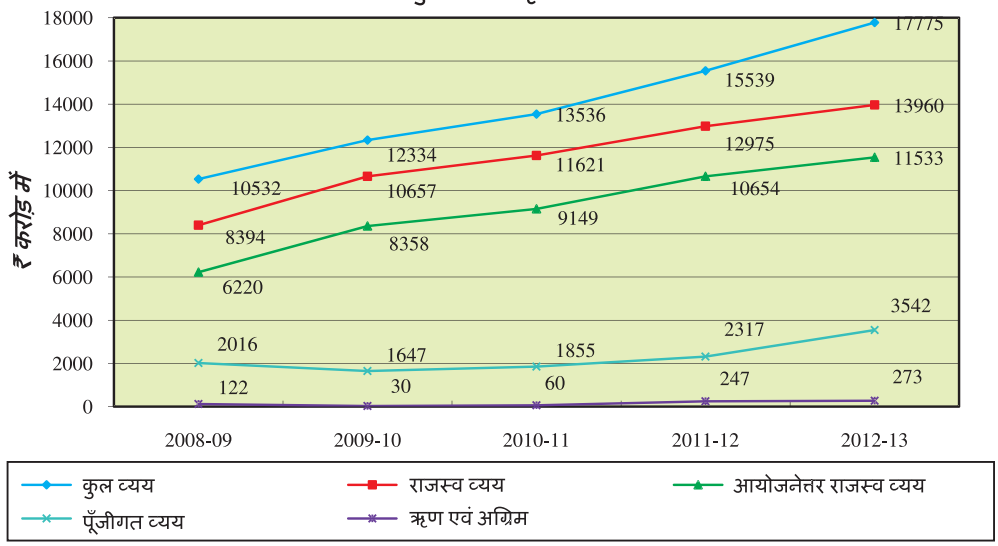
राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आबंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रमुख व्यय दायित्व राज्य सरकार के सुपुर्द होते हैं। राजकोषीय दायित्व विधायन के ढाँचे के अन्तर्गत, घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय अवरोध होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया विशेषकर

विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। राज्य में व्यय के आबंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 पाँच वर्षों (2008-09 से 2012-13) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है तथा इनकी संरचनाओं को 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'क्रियाकलापबद्ध व्यय' दोनों के सन्दर्भ में क्रमशः **चार्ट 1.7** एवं **1.8** में चित्रित किया गया है।

चार्ट 1.6: कुल व्यय: प्रवृत्तियाँ एवं संरचना



राज्य का कुल व्यय (टी ई): वर्ष 2008-13 के दौरान 12.92 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की औसत दर पर बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान कुल व्यय में ₹ 2,236 करोड़ (14.39 *प्रतिशत*) की बढ़ोतरी राजस्व व्यय व पूँजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 985 करोड़ व ₹ 1,225 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। ऋण व अग्रिमों का संवितरण भी ₹ 26 करोड बढ़ा।

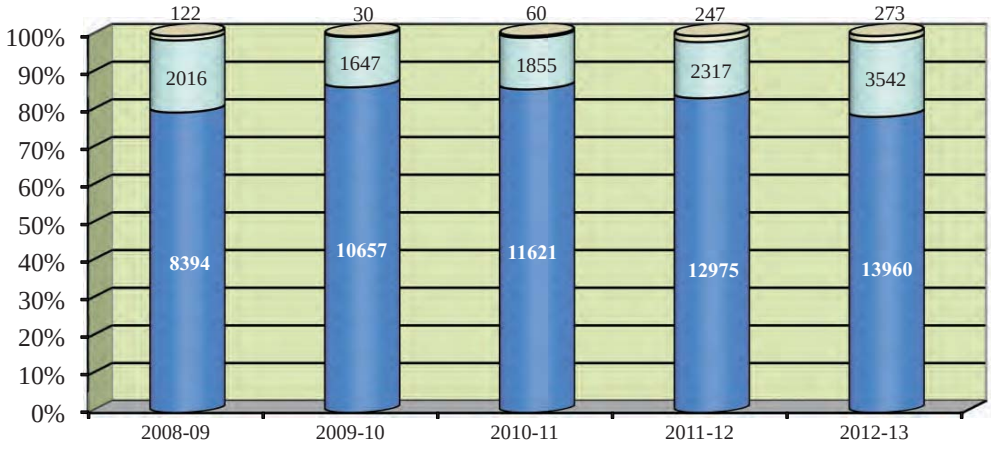
राजस्व व्यय (आर ई): चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि (₹ 985 करोड़) (i) सामान्य सेवाओं (₹ 897 करोड़), (ii) सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 118 करोड़) एवं (iii) सामाजिक सेवाओं (₹ 76 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। यह वृद्धि आर्थिक सेवाओं में व्यय (₹ 106 करोड़) में कमी से प्रतिसंतुलित हुई।

पूँजीगत व्यय (सी ई): पूँजीगत व्यय में वर्ष के दौरान वृद्धि (₹ 1,225 करोड़) (i) सामाजिक सेवाओं (₹ 346 करोड़), (ii) आर्थिक सेवाओं (₹ 827 करोड़) तथा (iii) सामान्य सेवाओं (₹ 52 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में इसने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान विचलन-शील प्रवृत्ति दर्शाई जो वर्ष 2008-09 में 19.14 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2012-13 में 19.93 *प्रतिशत* था। पूँजीगत व्यय में 2009-10 में 2008-09 के मुकाबले कमी हुई लेकिन पिछले तीन वर्षों में बढ़ती हुई

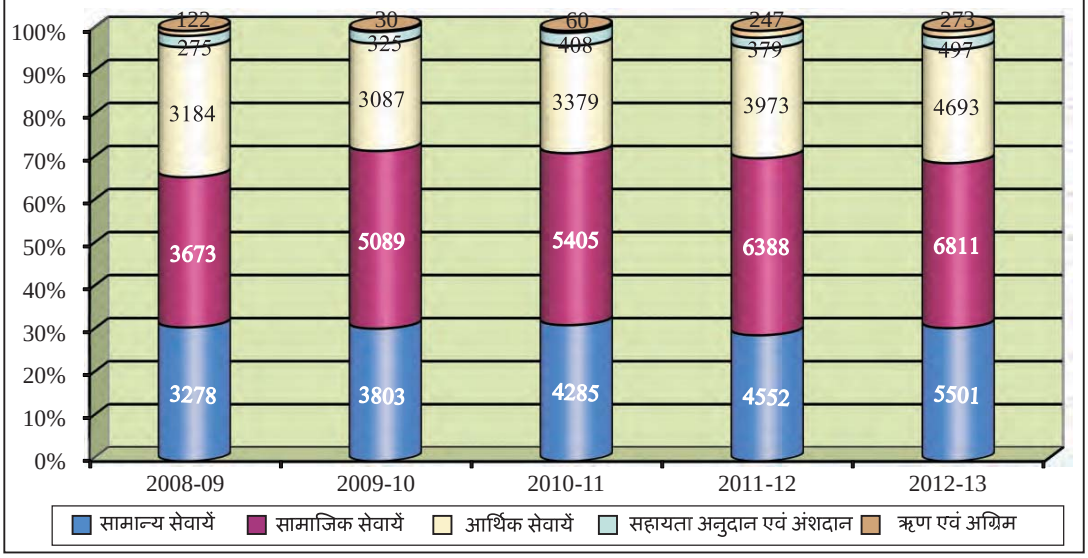
प्रवृत्ति दर्शाई और चालू वर्ष में ₹ 3,542 करोड़ रही। तथापि, वास्तविक व्यय, राज्य सरकार द्वारा उनके बजट (₹ 3,653 करोड़) तथा एम टी एफ पी एस (₹ 4,547 करोड़) में परिकल्पित लक्ष्य के नीचे था।

व्यय के इन घटकों का सापेक्ष अंश जो विगत (2009-12) में लगभग अपरिवर्तित रहा। वर्तमान वर्ष में पूँजीगत व्यय के अंश के सन्दर्भ में बढ़ोत्तरी होते हुए पूरा अभाव दर्शाया। गैर विकासात्मक समझे जाने वाले ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय का अंश वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान लगभग अपरिवर्तित रहा। सामाजिक सेवाओं का व्यय वर्ष 2011-12 के 41 *प्रतिशत* से थोड़ा घटकर वर्ष 2012-13 में 38 *प्रतिशत* हो गया। आर्थिक सेवाओं ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 की अवधि में घटने की प्रवृत्ति दर्शाई और 2011-12 एवं 2012-13 में लगभग अपरिवर्तित बनी रही।

चार्ट -1.7: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश में प्रवृत्तियाँ *(₹ करोड़ में)*



चार्ट -1.8: कुल व्यय: क्रियाकलापों की प्रवृत्तियाँ *(₹ करोड़ में)*



राज्य का **राजस्व व्यय,** 14.19 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक दर से 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 5,566 करोड़ (66.31 *प्रतिशत)* बढ़कर ₹ 8,394 करोड़ से ₹ 13,960 करोड़ हो गया।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य का **आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एन पी आर ई)** ₹ 5,313 करोड़ (85.42 *प्रतिशत*) बढ़कर ₹ 6,220 करोड़ से ₹ 11,533 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, एन पी आर ई में वृद्धि (₹ 879 करोड़) मुख्यतः वेतन (₹ 480 करोड़) और ब्याज अदायगियों (₹ 320 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

राज्यों के राजस्व व्यय में आयोजनागत राजस्व व्यय (पी आर ई) के अंश में 2008-11 के दौरान वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2011-12 के दौरान इसने ₹ 151 करोड़ (6.11 *प्रतिशत*) की कमी दर्शायी। चालू वर्ष के दौरान इसमें पुनः पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 106 करोड़ (4.57 *प्रतिशत*) की बढ़ोतरी हुयी जो मुख्यतः शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति (₹ 143 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 57 करोड़), समाज कल्याण (₹ 39 करोड़) और परिवहन (₹ 11 करोड़) में वृद्धि के फलस्वरूप थी। यह अंशतः कृषि (₹ 151 करोड़) और ग्राम्यविकास (₹ 57 करोड़) की कमी के फलस्वरूप प्रतिसंतुलित हुयी।

पुनः वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए नीचे **तालिका 1.13** वास्तविक एन पी आर ई का राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर किये गये अनुमानों के संदर्भ में ब्यौरा देती है:

तालिका-1.13

वर्ष 2012-13 के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

आयोजनेत्तर व्यय (एन पी आर ई)	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारण	राज्य सरकार द्वारा निर्धारण		
		बजट	एम टी एफ पी एस	वास्तविक
	9,390	14,883	15,017	11,533

स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे

चालू वर्ष के दौरान एन पी आर ई, (₹ 11,533 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग (₹ 9,390 करोड़) द्वारा निर्धारित मानकीय निर्धारण से ₹ 2,143 करोड़ (22.82 *प्रतिशत)* अधिक हो गया किन्तु यह क्रमशः राजकोषीय सुधार पथ (₹ 14,883 करोड़) और मध्यकालिक राजकोषीय नीति (₹ 15,017 करोड़) में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित प्रक्षेपण से कम था।

1.6.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। **तालिका 1.14** और **चार्ट 1.9** वर्ष 2008-13 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका-1.14

वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13		
					बी ई	वास्तविक	भिन्नता का प्रतिशत
वेतन और पारिश्रमिक, *जिसमें*	3,045 (*35*)	4,388 (46)	4,721 (41)	5,244 (40)	6,513 (41)	5,724 (41)	(-) 12.11
आयोजनेत्तर शीर्ष	2,728	4,114	4,464	4,971		5,423	
योजनागत शीर्ष*	317	274	257	273		301	

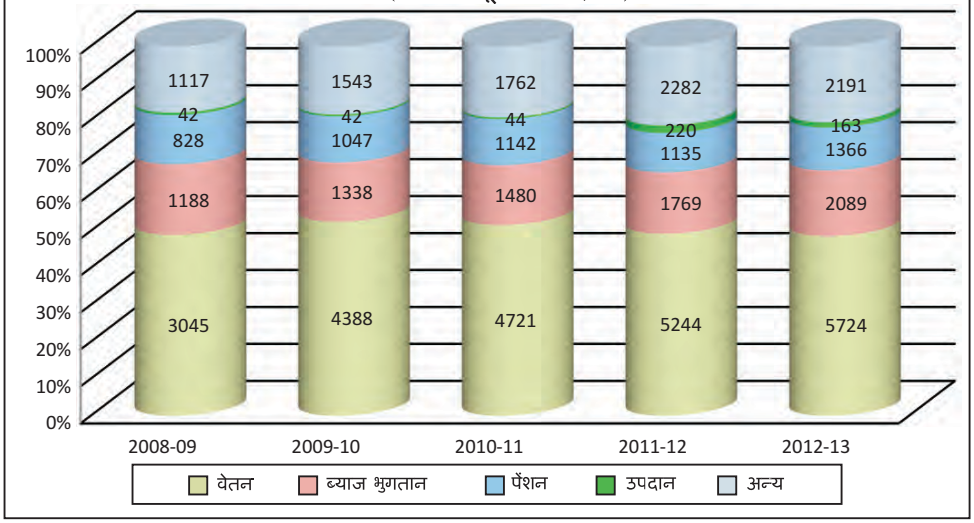
ब्याज भुगतान	1,188 (*14*)	1,338 (14)	1,480 (13)	1,769 (14)	2,025 (13)	2,089 (15)	(+) 3.16
पेंशन पर व्यय	828 (*10*)	1,047 (11)	1,142 (10)	1,135 (9)	1440 (9)	1,366 (10)	(-) 5.14
उपदान	42 (*0.50*)	42 (0.44)	44	220 (2)	397 (3)	163 (1)	(-) 58.94
कुल वचनबद्ध व्यय	**5,103**	**6,815**	**7,387**	**8,368 (64)**	**10,375 (66)**	**9,342 (67)**	(-) 9.96
अन्य घटक	1,117	1,543	1,762	2,286	4508	2191	(-) 51.40
कुल एन पी आर ई	**6,220**	**8,358**	**9,149**	**10,654**	**14,883**	**11,533**	(-) 22.51
कुल राजस्व व्यय	**8,394**	**10,657**	**11,621**	**12,975**	**15,717**	**13,960**	**(-) 11.18**
राजस्व प्राप्तियाँ	**8,635**	**9,486**	**11,608**	**13,691**	**16,159**	**15,747**	**(-) 2.55**

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं।

*केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान भी आयोजनागत शीर्ष में शामिल हैं।

चार्ट 1.9 2008-2013 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश

(लेबल में मूल्य ₹ करोड़ में)



2008-09 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्तियों के 59.10 *प्रतिशत* था, चालू वर्ष के दौरान कमोबेस बराबर (59.33 *प्रतिशत)* या अधिक रहा तथापि 2008-13 को अवधि के दौरान यह ₹ 4,239 करोड़ बढ़ा। राज्य सरकार को चाहिए कि वचनबद्ध व्यय को सन्निहित करने हेतु कदम उठायें क्योंकि विकासपरक कार्यकलापों के लिए व्यय करने हेतु सरकार के लिए यह कोइ गुंजाइश नहीं छोड़ता है।

वेतन एवं पारिश्रमिक

वेतन पर व्यय, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियानव्यन के कारण वर्ष 2008-09 में ₹ 3,045 करोड़ से 44 *प्रतिशत* (₹ 1,343 करोड़) बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 4,388 करोड़ हो गया था। यद्यपि, वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान वेतन पर व्यय क्रमश: 7.59 *प्रतिशत,* 11.08 *प्रतिशत* और 9.15 *प्रतिशत* ही बढ़ा। इन तीन वर्षों में वेतन व्यय ते वि आ के अनुमानों से अधिक था। तथापि चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट लक्ष्य (₹ 6,513 करोड़) और एम टी एफ पी एस (₹ 6,505 करोड़) में काफी नीचे थे।

ते वि आ के मानकों में नियत है कि वेतन मद के अन्तर्गत व्यय, राजस्व व्यय के ब्याज भुगतानों व पेंशन का शुद्ध 35 *प्रतिशत* होना चाहिए, जबकि चालू वर्ष में वेतन पर वास्तविक व्यय 50 *प्रतिशत* के आसपास था।

पेंशन भुगतान

राज्य सरकार ने पेंशन दायित्वों का अनुमान ऐतिहासिक वृद्धि दर के आधार पर लगाया था न कि वास्तविकता के आधार पर। वर्ष 2012-13 में पेंशन पर व्यय ₹ 1,366 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 8.67 *प्रतिशत* था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान पेंशन भुगतान लगभग स्थिर बना रहा लेकिन चालू वर्ष के दौरान पेंशन भुगतान, विगत वर्ष की अपेक्षा 20.35 *प्रतिशत* बढ़ा। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा, चालू वर्ष के लिए निर्धारित मानक (₹ 1,329 करोड़) से थोडा सा अधिक (₹ 37 करोड़) था (ते वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7)।

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 01 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है।

ब्याज भुगतान

जैसा कि **तालिका 1.14** में दर्शित है, वर्ष 2008-13 की अवधि में ब्याज भुगतान प्रारम्भिक तौर पर पिछले ऋणों के कारण 75.84 *प्रतिशत* बढ़ गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान ब्याज भुगतान में आन्तरिक ऋणों[4] पर ब्याज (₹ 1,486 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 402 करोड़), अन्य देयताएँ (₹ 162 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋण एवं अग्रिम (₹ 39 करोड़) शामिल थे। चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 2,089 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 13.27 *प्रतिशत* था, जो कि चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार के बजट द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 2,025 करोड़ से उच्च था और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा चालू वर्ष हेतु निर्धारित मानक (₹ 1,757 करोड़) से ₹ 332 करोड़ से भी अधिक था। यद्यपि, राज्य की एम टी एफ पी एस में ब्याज भुगतान लक्ष्य ₹ 2,119 करोड़ से ₹ 30 करोड़ कम था।

उपदान

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के सुविधाविहीन भाग को उपदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य नहीं है। उपदान न केवल स्पष्ट रूप से अपितु अनुमानित उपदानित लोक सेवा प्रदान करते हुये लोगों को बाँटा जाता है। अनुमानित उपदानों में वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहयोग, निवेशों पर अपर्याप्त प्राप्ति और सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं प्रदान करने पर उपभोगित कीमत की कम वसूली आते हैं।

वित्तीय लेखों (परिशिष्ट III) ने पिछले पाँच सालों में सीधे तौर पर दिये गये उपदान ₹ 41.94 करोड़ (2008-09), ₹ 42.45 करोड़ (2009-10), ₹ 43.49 करोड़ (2010-11), ₹ 219.67 करोड़ (2011-12) तथा ₹ 163.23 करोड़ (2012-13) को प्रदर्शित किया।

वर्ष के दौरान विगत वर्ष की तुलना में उपदान में ₹ 56.44 करोड़ (25.69 *प्रतिशत*) की कमी पाई गई। कमी का मुख्य कारण खाद्य को उपदान की कम राशि (₹ 53.36 करोड़) देना था।

[4] परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता राशि **तालिका-1.15** में प्रस्तुत है:

तालिका -1.15: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता *(₹ करोड़ में)*

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					ब आ	वास्तविक
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	198.99	267.99	488.49	403.45	526.25	501.83
नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	106.20	122.47	154.72	175.76	352.24	306.28
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	168.57	202.25	252.96	203.04	495.68	190.59
विकास अभिकरण	588.44	571.47	526.00	409.35	572.43	480.80
चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	38.89	44.52	71.23	86.98	137.05	134.78
ऊर्जा (ऊर्जा का गैर-परम्परागत स्रोत)	69.79	24.39	7.50	6.32	12.57	12.89
कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	217.73	98.62	151.15	205.54	203.18	79.71
सहकारिता	3.49	13.22	9.56	7.30	12.32	9.75
पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	31.51	14.79	13.16	8.65	9.85	8.75
सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	27.51	11.43	18.43	29.34	69.10	36.28
सामाजिक सुरक्षा एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	122.77	133.65	97.46	211.10	271.71	254.31
अन्य संस्थाएँ	85.46	371.24	131.61	31.12	136.37	115.75
योग	**1,659.35**	**1,876.04**	**1,922.27**	**1,777.95**	**2,798.75**	**2,131.72**
राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में सहायता	*19.77*	*17.60*	*16.54*	*13.70*	*17.80*	*15.27*

स्रोतः वी एल सी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को प्रदत्त कुल सहायता ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में इन निकायों की सहायता में ₹ 144 करोड़ (7.51 *प्रतिशत*) उतार देखा गया, जबकि यह सहायता वर्ष के दौरान ₹ 354 करोड़ (19.90 *प्रतिशत*) बढ़ गया। विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाओं, विकास अभिकरणों को प्रदत्त सहायता राशि कुल वित्तीय सहायता का 46 *प्रतिशत* थी।

इस वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि, मुख्यतः शैक्षिक संस्थाओं (₹ 98 करोड़) शहरी निकाय एवं पी आर आई (₹ 118 करोड़) और विकास अभिकरणों (₹ 71 करोड़) चिकित्सालय एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 48 करोड़) के अन्तर्गत थी जो कि कृषि सहायता (126 करोड़) की कमी से कुछ हद तक प्रतिसंतुलित हुयी।

1.6.4 स्थानीय निकाय: परिचय, कार्यों का अवक्रमण, निधि और लेखाकरण, लेखापरीक्षा कार्य और प्रतिवेदन कार्य की व्यवस्था

उत्तराखण्ड राज्य नवम्बर 2000 में अस्तित्व में आया। प्रधान महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रशासनिक नियंत्रण में वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून का कार्यालय 2004 में स्थापित हुआ। भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में वर्ष 2012 में, लेखा प्रकार्यों की पुन:संरचना के पश्चात, वरिष्ठ उप महालेखाकार (एल बी ए और ए), उत्तराखण्ड के कार्यालय को, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून के सामाजिक एवं एल बी सेक्टर के साथ मिला दिया गया है।

उत्तराखण्ड में पी आर आई की 7,663 लेखापरीक्षित इकाईयाँ हैं जिनकी तीन श्रेणियाँ हैं-ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत तथा यू एल बी की 72 लेखापरीक्षित इकाईयाँ जैसे – नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक और एल बी के लेखा अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

पी आर आई और यू एल बी के कार्य:

73वें संविधान संशोधन 1993 में वर्णित और 11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 जी) में सूचीबद्ध कार्यों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्य हैं और 74वें संविधान संशोधन 1993 और 12वीं अनुसूची में (अनुच्छेद 243 डब्ल्यू) सूचीबद्ध कार्यों के अनुसार यू एल बी के लिए 18 कार्य हैं। उपरोक्त परिकल्पित कार्यों में क्रमशः 2006 एवं 2009 में उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के तीन सोपानों को केवल 14 कार्य तथा नगरीय स्थानीय संस्थाओं को 13 कार्य हस्तान्तरित किए।

कार्यकर्ताएँ:

पी आर आई और यू एल बी को प्रदत्त प्रकार्यों से संबंधित कार्यकर्ताओं को अभी तक उत्तराखण्ड की पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के तीनों सोपानों को हस्तान्तरित नहीं किया गया था। तथापि, इन कार्यों से संबंधित सरकारी आदेशों को पहले ही, राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा निर्गमित किया जा चुका है।

लेखाकरण, लेखापरीक्षा कार्य और प्रतिवेदन कार्य की व्यवस्था:

स्थानीय निकायों द्वारा बजट एवं लेखाओं के रखरखाव तैयार करने के लिए, पूरे भारत में एकरूपेण, बजट तथा लेखाकरण फार्मेट भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि म ले प) द्वारा निर्धारित किया गया है इसका उद्देश्य पूरे भारत में स्थानीय निकाय लेखाओं को एकरूपता प्रदान करना है। वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने इन सभी फार्मेटों को पी आर आई-ओं तथा यू एल बी-यों के लिए अपना लिया है। पी आर आई-यों तथा यू एल बी-यों जो मुख्यत: संघ या राज्य सरकारों की समेकित निधियों से वित्तीयित हैं, की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 जहाँ भी लागू हो, की *धारा 14* के अन्तर्गत, नि म ले प द्वारा संपादित है। राज्य सरकार ने भी पी आर आई-यों तथा यू एल बी-यों की लेखापरीक्षा, नि म ले प (क श से) अधिनियम, 1971 की *धारा 20(1)* के अधीन तकनीकी निर्देशन व आधार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नि म ले प को सौंपा है। तदनुसार, जो पी आर आई-यां तथा यू एल बी-यां नि म ले प के (क श से)

अधिनियम, 1971 की *धारा 14* के कार्यक्षेत्र में नही आते उनकी लेखापरीक्षा, नि म ले प (क श से) अधिनियम, 1971 की *धारा 20(1)* के अधीन की जाती है। इस प्रकार की लेखापरीक्षा सम्पादन से उत्पन्न लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के नियम 155 के अधीन वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में राज्य सरकार को सूचित किया जाता है।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करता है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

तालिका 1.16 चालू वर्ष के दौरान विकासपरक व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के सापेक्ष राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करती है।

तालिका-1.16

2008-09 और 2012-13 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/स रा घ उ	वि व्य #/स व्य	सा क्षे व्य/स व्य	पूं व्य/स व्य
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2008-09	18.80	66.21	34.87	19.14
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2012-13	16.41	66.25	38.32	19.93

स व्य : सकल व्यय, वि व्य : विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य : सामाजिक क्षेत्र में व्यय
विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।
स्रोतः (1) स रा घ उ के लिए सूचना राज्य के अर्थ एवं संख्या निदेशालय से एकत्र की गयी थी। **(परिशिष्ट-1.2 भाग अ)**

राजकोषीय प्राथमिकता राज्य द्वारा श्रेणी विशेष के व्यय को दी गई प्राथमिकता को इंगित करती है। 2008-09 के सापेक्ष 2012-13 में व्यय पद्धति के तुलनात्मक अध्ययन पर पाया गया कि:

- सरकार का सकल व्यय स रा घ उ के अनुपात के रूप में 2008-09 से 2012-13 में 2.39 *प्रतिशत* निम्नतर था।
- सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकासपरक व्यय (वि व्य) वर्ष 2008-09 एवं 2012-13 के दौरान समान था।
- सकल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय लगभग 3.45 *प्रतिशत* उच्च था।
- यद्यपि पूँजीगत व्यय चालू वर्ष के दौरान 52.87 *प्रतिशत* बढ़ा, लेकिन पूँजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात अपरिवर्तित रहा।

1.7.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मदों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स[5] के

[5] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।

प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण है। विकासपरक व्यय[6] हेतु आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, आसन्न वर्षों में विशेषकर ऋण सेवाओं में गिरावट के कारण उत्पन्न राजकोषीय अन्तराल के मद्देनजर, किये हुए व्यय की दक्षता पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा स रा घ उ) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/अथवा स रा घ उ) में इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर करेगा। जहाँ, एक ओर **तालिका 1.17** चालू वर्ष व गत वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन की तुलना में राज्य के समग्र व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं **तालिका 1.18,** चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

कुल व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय के अंश ने वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान 50 *प्रतिशत* की औसत दर पर अन्तर्वर्षीय विविधता दर्शायी। वर्ष 2012-13 के दौरान यह विगत वर्ष की तुलना में मामूली 0.37 *प्रतिशत* कम रहा। विकासपरक पूँजीगत व्यय की अंश ने भी अन्तर्वर्षीय विविधता प्रदर्शित की लेकिन 2009-10 से आगे तक बढ़ोतरी का रूझान लगातार दर्शाया। यह 2011-12 की तुलना में 2012-13 में 52 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। 2008-09 से 2012-13 तक विकासपरक व्यय में समग्र वद्धि 69 *प्रतिशत* थी।

तालिका-1.17

विकासपरक व्यय *(₹ करोड़ में)*

विकासपरक व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					ब आ	वास्तविक
विकासपरक व्यय (अ से स)	6,973 (66)	8,205 (66)	8,842 (65)	10,607 (68)	13,201 (67)	11,776 (66)
अ. विकासपरक राजस्व व्यय	5,015 (48)	6,638 (54)	7,033 (52)	8,121 (52)	9,425 (48)	8,091 (45)
ब. विकासपरक पूँजीगत व्यय	1,842 (17)	1,538 (12)	1,750 (13)	2,240 (14)	3,514 (18)	3,413 (19)
स. विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	116 (1)	29 (0.23)	59 (0.44)	246 (2)	262 (1)	272 (2)

कोष्ठक के आँकड़े समग्र व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका-1.18

चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता *(प्रतिशत में)*

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2011-12			2012-13		
	कु व्य पर पूँ व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पूँ व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय						
सामान्य शिक्षा	0.73	19.99	0.003	1.04	19.19	0.004
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.60	3.91	0.027	0.78	4.02	0.039
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	0.76	0.04	0.010	1.51	0.045	0.012
सा से पर कुल व्यय	2.37	25.00	0.06	4.02	24.42	0.066

[6] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।

आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	1.67	3.37	0.13	3.05	3.58	0.230
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2.93	1.54	0.19	2.18	1.53	0.244
विद्युत एवं ऊर्जा	0.27	--	--	2.90	--	--
परिवहन	5.52	0.10	0.55	5.45	0.099	0.541
आ से पर कुल व्यय	**12.03**	**6.41**	**0.89**	**15.18**	**6.56**	**1.015**
सा से + आ से पर कुल व्यय	**14.41**	**31.41**	**0.94**	**19.20**	**30.98**	**1.081**

कु व्यः कुल व्यय, पूँ व्यः पूँजीगत व्यय, रा व्यः राजस्व व्यय, वे एवं पाः वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मरः परिचालन एवं मरम्मत।

यद्यपि, पूँजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण से सम्बन्धित कोई विशेष मापदण्ड एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित नहीं किये गये हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 के बजट के साथ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत अपने एम टी एफ पी एस में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रति वचनबद्धता दर्शायी है जिनमें स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 3.5 *प्रतिशत* होगा और वर्ष 2013-14 तक इसे कम करके तीन *प्रतिशत* लाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार उधार कम लेगी तथा निकट भविष्य में पूँजीकरण हेतु निधियाँ कम होंगीं। तथापि चालू वित्त वर्ष में सरकार ने वर्ष 2011-12 की तुलना में 53 *प्रतिशत* अधिक निधियों के पूँजीकरण की व्यवस्था की।

वर्ष 2012-13 के दौरान, राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में वेतन तथा पारिश्रमिक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर लगभग स्थिर बना रहा। राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में परिचालन एवं मरम्मत व्यय चालू वर्षों के दौरान आर्थिक सेवाओं में मूल्यवर्द्धित हुआ।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने वरन् अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भर होने के क्रम में, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2013 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना **तालिका 1.19** में दी गयी है।

तालिका-1.19
अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	*परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31 मार्च 2013 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	188	500.03	503.54	3.51	86.55
ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएँ	04	17.47	--	--	8.39
योग	**192**	**517.50**	**503.54**	**3.51**	**94.94**

** राज्य सरकार द्वारा 31.03.2013 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।*

स्रोतः वित्त लेखे

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2013 को, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं (**तालिका 1.20**) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था अर्थात पिछले 3 सालों के निवेश के एक *प्रतिशत* से भी कम, जबकि सरकार ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान ऋणों पर 7.81 *प्रतिशत* औसत दर पर ब्याज दिया।

तालिका-1.20

निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अन्त तक निवेश *(₹ करोड़ में)*	1,071	1,240	1,296	1,338	1,858
प्रतिफल लाभांश/व्यय *(₹ करोड़ में)*	0.23	0.07	0.21	0.05	0.19
प्रतिफल (*प्रतिशत*)	*0.02*	*0.01*	*0.02*	*[7]	*0.01*
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत*)	*7.75*	*7.64*	*7.34*	*7.83*	*8.50*
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (*प्रतिशत*)	*7.73*	*7.63*	*7.32*	*7.83*	*8.49*

स्रोतः वित्त लेखे

निवेश एवं प्रतिफल पर इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार, मानक तैयार करने तथा कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभ से जुड़ी परियोजनाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है।

मुख्य लाभार्थी - (i) उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 967 करोड़) और (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 600 करोड़) थे। उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ₹ 1,948 करोड़ की हानि तथा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने ₹ 226 करोड़ का लाभ वर्ष 2011-12 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार संचित किया था।

1.8.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा भी निष्पादित किये जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा लेखे तैयार कर लिए गए हैं, विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेशित पूँजी का प्रतिफल **परिशिष्ट-1.6** में दिया गया है। तीन कम्पनियों के अन्तिम लेखाओं की जाँच में यह पाया गया था किः

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी सिंचाई कार्यशाला, रूड़की में ₹ 1.89 करोड़ का निवेश, उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक किया गया था, जब तक उसके लेखे तैयार (2009-10) कर लिए गये थे ।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात सिंचाई कार्यशाला, रूड़की, आर एफ सी, हल्द्वानी तथा आर एफ सी, देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला के 2009-10 तक के लेखे तैयार थे। वर्ष 2007-08 तक यह लाभार्जन का उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात शुद्ध हानि दर्ज की गयी। अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार, इन तीन विभागीय उपक्रमों की कुल संचित हानि ₹ 36 करोड़ थी।
- वर्ष 2012-13 के दौरान इन विभागीय उपक्रमों द्वारा कोई भी लेखा अन्तिम नहीं किया गया।

[7] गणना योग्य नहीं।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। **तालिका-1.21** 31 मार्च 2013 को, बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.21

राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियाँ/ऋण की लागत की मात्रा	2010-11	2011-12	2012-13	
			ब आ	वास्तविक आँकड़े
प्रारम्भिक शेष	743.09	717.90	--	874.08
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	59.68	246.83	264.05	272.57
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	84.87	90.65	118.18	428.44
अंतिम शेष	717.90	874.08		718.21
निवल वृद्धि	(-) 25.19	(+) 156.18		(-)155.87
ब्याज प्राप्तियाँ	7.98	0.62		1.61
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियाँ *प्रतिशत* के रूप में	1.11	0.07		0.22
राज्य सरकार के अदत्त राजकोषीय दायित्वों के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज भुगतान	6.85	7.49		8.18
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर (*प्रतिशत*)	5.74	7.42		7.96
अदत्त बकाया, जिनकी शर्तें नियत की जा चुकी हैं	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई			

स्रोतः वित्त लेखे व वार्षिक वित्त विवरण (उत्तराखण्ड सरकार)

सरकार ने वर्ष 2011-12 के ₹ 247 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 273 करोड़ ऋण दिये, जो कि पिछले वर्ष से ₹ 26 करोड़ अधिक थे। मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्भुगतान (₹ 422 करोड़) के कारण ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 338 करोड़ की बढ़ोत्तरी दिखाई दी।

बकाया ऋणों एवं अग्रिम ब्याज के रूप में ब्याज प्राप्तियों ने चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी सी वृद्धि दर्शायी। वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाये गये बाजार ऋणों की औसत ब्याज दर 8.87 *प्रतिशत* थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं, निगमों/सरकारी कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर केवल 0.22 *प्रतिशत* थी, जो कि वर्ष 2009-10 में बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात *प्रतिशत* के लक्ष्य के सापेक्ष थी।

बारहवें वित्त आयोग ने संस्तुति दी कि बकाया पड़े ऋणों एवं अग्रिमों पर कम से कम सात *प्रतिशत* प्रतिफल पूर्वानुमानित अवधि के अन्तिम वर्ष (2009-10) तक श्रेणीबद्ध ढ़ंग से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिस लक्ष्य को राज्य सरकार वर्ष 2012-13 में भी प्राप्त नहीं कर पायी। 31 मार्च 2013 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 718 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी कृषि (₹ 451 करोड़), परिवहन (₹ 125 करोड़) एवं ऊर्जा (₹ 77 करोड़) क्षेत्र थे।

1.8.5 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.22 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका-1.22

रोकड़ शेष और रोकड़ शेष से किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2012 को	31 मार्च 2013 को
सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	(-) 5.38	00
रिजर्व बैंक में जमा	116.01	(-) 5.21
अन्य बैंकों में जमा (ब)	00	00
योग	**110.63**	**(-) 5.21**
रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखा निवेश	50.21	875.15
योग (अ)	160.84	869.94
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास रोकड़	(-) 2.15	(-) 2.15
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम	(-) 0.87	(-) 0.87
उद्दिष्ट निधियों का निवेश	927.36	1,078.62
योग (ब)	**924.34**	**1,075.60**
महायोग (अ) + (ब)	**1,085.18**	**1,945.54**

स्रोतः वित्त लेखे

अन्तिम रोकड़ शेष गत वर्ष (₹ 1,085.18 करोड़) की अपेक्षा चालू वर्ष (₹ 1,945.54 करोड़) के अन्त में ₹ 860.36 करोड़ बढ़ गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 1,078.62 करोड़ की नैमित्तिक निधि सृजित की। यही राशि नैमित्तिक निधि से भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित की गई तथा वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 32.15 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। वर्ष 2012-13 के दौरान रोकड़ शेष पर प्राप्त ब्याज 1.65 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधार राशियों पर 8.18 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार ने ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं लिया और वर्ष 2012-13 के दौरान अधिकतम दिनों के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष बनाये रखने में समर्थ थी। तथापि, वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी शेष ने सरकार को दो (साधारण और विशेष) अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने के लिए मजबूर किया। वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य को ₹ 0.01 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत में मुख्य शीर्ष 'चैको और बिलों' के नीचे लघुशीर्ष 'कोषालय चैक' के अधीन ₹ 44.27 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था।

पर्याप्त रोकड़ शेष, ₹ 1,787 करोड़ के राजस्व आधिक्य और निम्न राजकोषीय घाटे, जो स रा घ उ का 1.48 *प्रतिशत* था, के फलस्वरूप खुले बाजार की उधारियों को बजट के ₹ 2,400 करोड़ के लक्ष्य को ₹ 1,750 करोड़ तक रोका जा सका ।

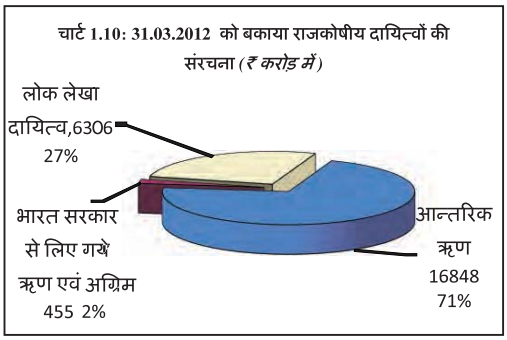
1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

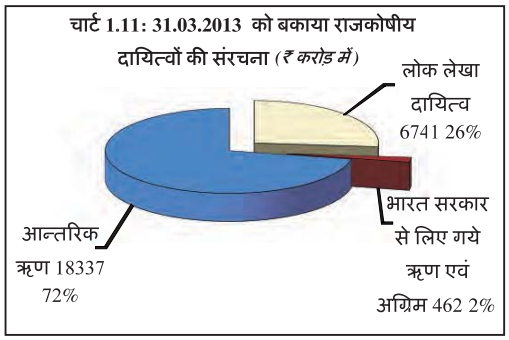
1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्व की संरचना एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखापद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4 (भाग-ब)** में 31 मार्च 2012 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2013 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया पड़े राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3**, **परिशिष्ट-1.4** व राज्य वित्त लेखे के **विवरण 6** में प्रस्तुत किया गया है तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट 1.10 और 1.11** में प्रस्तुत की गई है।





वर्ष 2012-13 का ऋण- स रा घ उ अनुपात (23.57 *प्रतिशत*), पिछले वर्ष की तुलना में (25.07 *प्रतिशत*) 1.5 *प्रतिशत* सुधरा। यह अनुपात तेरहवें वित्त आयोग के उस वर्ष के लिए, निर्धारित मापदण्ड (40.00 *प्रतिशत*) से नीचे था। समग्र राजकोषीय दायित्व वर्ष 2008-09 के ₹ 16,276 करोड़ से 56.92 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 25,540 करोड़ हो गये थे। राज्य की देयताएँ जो वर्ष 2012-13 के अन्त में ₹ 25,540 करोड़ की थी, में मुख्य रूप से लोक ऋण (₹ 18,799 करोड़), लघु बचत एवं भविष्य निधि (₹ 4,720 करोड़) और अन्य दायित्व (₹ 2,021 करोड़) शामिल थे। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक ऋण तथा लघु बचत एवं भविष्य निधि आदि के कारण थी, जो क्रमशः ₹ 1,489 करोड़ एवं ₹ 271 करोड़ तक बढ़ गये थे। राजकोषीय देयताओं में वृद्धि विभिन्न वर्षों में कम बढ़ी, पिछले वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में यह 8.18 *प्रतिशत* बढ़ी। वर्ष के दौरान स रा घ उ के सापेक्ष इन दायित्वों में

उत्प्लावकता 0.54 थी, जो यह इंगित करती थी कि स रा घ उ में प्रत्येक *प्रतिशत* बिन्दु के लिए राजकोषीय दायित्व 0.54 *प्रतिशत* बढ़ गये थे। ये दायित्व राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 1.62 गुना एवं अपने संसाधनों का 3.19 गुना थे। राज्य में प्रारम्भ से ही खुले बाजार ऋणों की भुगतान वापसी के लिए सिंकिग फण्ड चलन में है (सितम्बर 2006 में पुनरीक्षित) और राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बकाया पड़े बाजार ऋणों के 0.50 *प्रतिशत* की दर से अंशदान करना है। राज्य सरकार ने इस निधि में ₹ 150 करोड़ का योगदान वर्ष के दौरान किया।

1.9.3 आरक्षित निधियों के अधीन लेन-देन

31 मार्च 2013 को आरक्षित निधियों में अंन्तिम शेष के रूप में ₹ 1,228.09 करोड़ (जमा) थे। इसमें से बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों में ₹ 1,191.23 करोड़ (जमा) तथा ब्याज वाली आरक्षित निधियों में ₹ 36.86 करोड़ (जमा) थे। इसमें, संचालित होने वाले लेखो के मुख्य शीर्ष 8115-मूल्य ह्रास/ नवीनीकरण आरक्षित निधि (₹ 0.01 करोड़) और 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ (₹ 36.85 करोड़) थे जिसके अन्तर्गत राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया गया। बिना ब्याज वाली (₹ 1191.23 करोड़) (जमा), आरक्षित निधियो के अन्तर्गत लेखाशीर्षो 8222-सिंकिंग फण्ड (₹ 1128 करोड़), 8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ (₹ 38.23 करोड़) और 8235- सामान्य एवं आरक्षित निधियों (25 करोड़) का संचालन किया गया था।

समेकित सिंकिंग फंड: बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कुल बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण और राज्य सरकार के लोक लेखा दायित्वों) का बोझ कम करने के लिये राज्य सरकार ने सिंकिंग फण्ड 2006 के सृजन एवं प्रशासन के लिए एक पुनरीक्षित योजना बनाई। आर बी आई द्वारा मार्गदर्शन/निर्देशों के अधीन, जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाये, निधियों का संचालन किया जाता है। सरकार द्वारा आर आई बी को इन निधियों पर अर्जित लाभांश के एक प्रतिशत का 1/8 *प्रतिशत* या परस्पर सहमति के आधार पर तय कमीशन के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2012-13 में ₹ 150 करोड़ राज्य की समेकित निधि से सिंकिंग फंड में विनियोजित किये गये, जो कि 31 मार्च 2013 को अदत्त दायित्वों (₹ 25,539.88 करोड़) की आवश्यकता का 0.5 *प्रतिशत* (₹ 128 करोड़) है। 2012-13 के अन्त में इसमें कुल संचयन ₹ 1,128 करोड़ था। निधियों के कुल संचयन में से ₹ 1,053.62 करोड़ आर बी आई द्वारा निवेश किया गया ।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि(एस.डी.आर.एफ.):

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर आपदा राहत कोष, जो राज्य में संचालन मे था, को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के द्वारा बदल दिया गया है। निधियों के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे कि उत्तराखण्ड को 90:10 के अनुपात मे योगदान देना आवश्यक है।

वर्ष 2012-13 के आरंभ में इस निधि में ₹ 41.72 करोड़ शेष थे। वर्ष 2012-13 के दौरान राशि ₹ 129.72 करोड़ (90 *प्रतिशत* केन्द्र अंश ₹ 116.75 करोड़ एवं 10 *प्रतिशत* राज्य का अंश ₹ 12.97 करोड़) भारत एवं उत्तराखण्ड राज्य की समेकित निधियों से एस डी आर एफ में विनियोजित किये गये इसके विरुद्ध ₹ 134.59 करोड़ इस निधि से व्यय किये गये तथा ₹ 36.85 करोड़ वर्ष के अंत मे शेष थे।

1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी रहने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

राज्य विधायिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ कोई भी कानून पारित नहीं किया गया, जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, प्रत्याभूतियों की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है।

वित्त लेखे के **विवरण संख्या 9** के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ **तालिका-1.23** में दी गई है:

तालिका-1.23
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2010-11	2011-12	2012-13
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	2,122	2,722	2,722
प्रत्याभूति की बकाया राशि	1,511	1,739	1,570
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूति की अधिकतम राशि का *प्रतिशत*	18.28	19.88	17.29
एफ आर बी एम अधिनियम/कोई अन्य अधिनियम अथवा राज्य के आदेश के अनुसार मानदण्ड	एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा कोई भी नियम नहीं बनाया गया है।		

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2013 को बकाया प्रत्याभूति की राशि (₹ 1,570 करोड़), प्राथमिक रुप से उर्जा क्षेत्र (₹ 1,041 करोड़), सहकारिताओं (₹ 500 करोड़) और अन्य संस्थाओं (₹ 29 करोड़) के विरूद्ध थी। प्रत्याभूति राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि का *प्रतिशत* 2010-11 में 18.28 *प्रतिशत* से घटकर 2012-13 में 17.29 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष के दौरान कोई भी प्रत्याभूति आव्हानित नहीं की गई।

राज्य सरकार ने प्रत्याभूति देने योग्य निर्धारित सीमाओं के लिए, एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के अनुसरण में, कोई नियम नहीं बनाये हैं। उपरोक्त की अनुपस्थिति में यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति सीमाओं के दायरे में थी।

सरकार ने ₹ 25 करोड़ की प्रत्याभूति संग्रह उत्थित प्रत्याभूतियों के निपटान के लिए एक 'प्रत्याभूति विमोचन निधि' गठित किया है। वर्ष 2012-13 के दौरान उक्त निधि से न तो कोई धनराशि निकाली गई तथा न ही विनियोजित की गई।

1.10 ऋण प्रबंधन

(i) ऋण रूपरेखा

राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋणों) की परिपक्वता रूपरेखा **तालिका 1.24** एवं **चार्ट 1.12** में दी गई है।

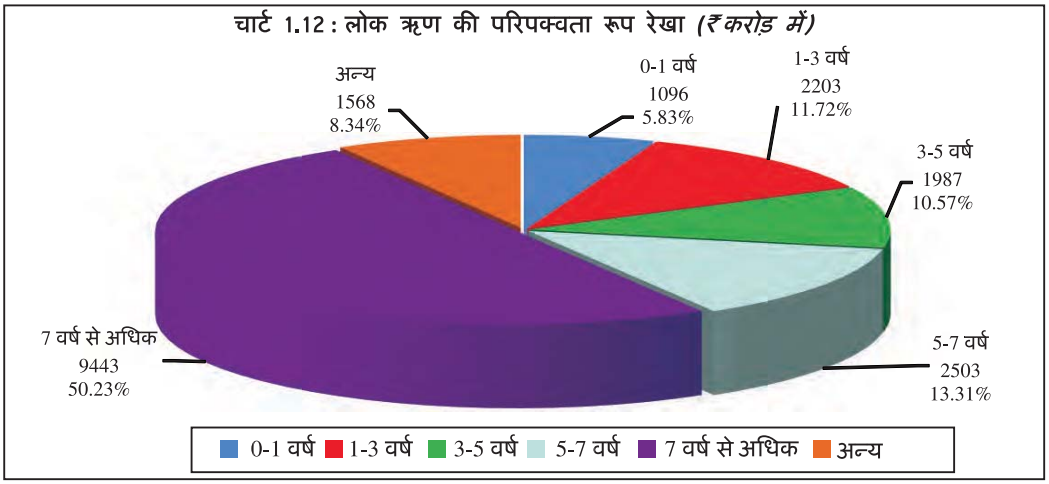
तालिका-1.24

लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा

परिपक्वता रूपरेखा	राशि *(₹ करोड़ में)*	कुल लोक ऋण पर प्रतिशतता
0-1 वर्ष	1,096	5.83
1-3 वर्ष	2,203	11.72
3-5 वर्ष	1,987	10.57
5-7 वर्ष	2,503	13.31
7 वर्ष से अधिक	9,443	50.23
अन्य (राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी)	1,568	8.34
योग	**18,800**	**100**

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 1.12 : लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा *(₹ करोड़ में)*



स्रोतः वित्त लेखे

वचनबद्ध व्यय-दायित्व के निर्वहन हेतु सरकार को और अधिक उधार लेना पड़ा चूँकि विगत पाँच वर्षों में किसी भी वर्ष में राजकोषीय आधिक्य उपलब्ध नहीं था। 31 मार्च 2013 को लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूप रेखा दर्शाती है कि 50.23 *प्रतिशत* लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता में था।

(ii) ऋण वहन क्षमता

राज्य सरकार के ऋणों के विस्तार के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड, ऋण स्थिरीकरण, ऋणेत्तर प्राप्तियों

की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों के अनुपात द्वारा मापित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के संदर्भ में राज्य सरकार की ऋण वहन क्षमता का आकलन करता है। **तालिका 1.25** वर्ष 2010-11 से आरम्भ करते हुए तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण वहन क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका-1.25

ऋण वहन क्षमता : सूचक एवं प्रवृत्तियाँ *(₹ करोड़ में)*

ऋण वहन क्षमता के सूचक[8]	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
ऋण स्थायित्विकरण[9] (मात्रात्मक विस्तार + प्राथमिक घाटा)	(+) 1,592	(+) 1,811	(+) 2,164
ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)[10]	(+) 940	(+) 86	(+) 157
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता[11]	820	308	5
ब्याज/भुगतानों का भार (ब्याज भुगतान/रा प्रा अनुपात)	*12.75*	*12.92*	*13.27*

तालिका-1.25 की प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्रारम्भिक घाटा न केवल धनात्मक था बल्कि उसने उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति भी दर्शायी। वर्ष 2012-13 के अन्त में यह ₹ 2,164 करोड़ पर था। ऋण- स रा घ उ अनुपात जो वर्ष 2008-09 में 29.05 *प्रतिशत* था, चालू वर्ष के दौरान 23.57 *प्रतिशत* तक गिरावट आयी। उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में, ऋण- स रा घ उ अनुपात 23.57 *प्रतिशत* पर था, जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित लक्ष्य (40 *प्रतिशत*) से अत्यधिक नीचे था।

ऋण स्थायित्व और इसकी वहन क्षमता का दूसरा सूचक, बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण-वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ,[12] बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा कर सकतीं। धनात्मक संसाधन अंतराल राज्य के ऋणों को संभालने की क्षमता को मजबूत करता है। **तालिका 1.25** वर्ष 2010-13 की अवधि हेतु परिभाषित संसाधन अंतराल को इंगित करती है।

राज्य ने वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में धनात्मक संसाधन अंतराल का अनुभव किया, जो बदले में 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे ले आया तथा राज्य ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमश: ₹ 716 करोड़ और ₹ 1,787 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 1,757 करोड़) तर्कसंगत सीमा तक नीचे लाया गया था, जो चालू वर्ष के दौरान (स रा घ उ का 1.48 *प्रतिशत*) ₹ 1,600 करोड़ तक और नीचे आ गया।

ऋण शोधन वर्ष 2008-10 के दौरान उच्चत्तर स्तर पर रहा था तथा वर्ष 2010-11 में थोड़ा सुधरा (0.83) जिससे यह इंगित होता है कि इस अवधि के दौरान पुरानी ऋण देयताओं को समाप्त करने के लिए ऋण निधियों का बढ़-चढ़ कर प्रयोग किया जा रहा है (**परिशिष्ट-1.3**)। तथापि, वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान इसने उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई। इसलिए चालू वर्ष के दौरान मूलधन एवं ब्याज को लौटाने

---

[8] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।

[9] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।

[10] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।

[11] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।

[12] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।

के पश्चात उधारी निधियों से, निधियों के पूँजीकरण/उत्पादक व्यय हेतु कोई निधि बाकी नहीं थी। तथापि, चालू वर्ष के दौरान आन्तरिक ऋण शोधन, नई ऋण प्राप्तियों का 48.18 *प्रतिशत* था; भारत सरकार के ऋणों में शोधन 82.48 *प्रतिशत* था जबकि अन्य देयताओं के प्रकरण में चुकौतियाँ नयी प्राप्तियों के 93.46 *प्रतिशत* थीं। यह प्रवृत्तियाँ इस तथ्य की ओर इंगित करती हैं कि सरकार का ध्यान पुरानी ऋण देयताओं की समाप्ति की ओर प्रतीत होता है।

1.10.1 बाजार ऋण

बाजार ऋण की स्थिति

तालिका 1.26 2008-13 की अवधि के लिए राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति दर्शाता है।

तालिका -1.26 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	1 अप्रैल के प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च को अन्तिम अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि (+) / कमी (-)	
					धनराशि	*प्रतिशत*
2008-09	5,000.94	1,010.69	126.53	5,885.10	884.16	*17.68*
2009-10	5,885.10	600.00	139.54	6,345.57	460.62	*7.82*
2010-11	6,345.53	991.52	102.00	7,235.05	889.52	*14.02*
2011-12	7,235.05	1,400.00	240.73	8,394.32	1,159.27	*16.02*
2012-13	8,394.32	1,750.00	949.87	9,194.45	800.13	*9.53*

स्रोत: संगत वर्ष के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 5,752.21 करोड़ एवं ₹ 1,558.67 करोड़ क्रमश ऋण लिया और पुनर्भुगतान किया। 2008-13 के दौरान पुनर्भुगतान राज्य सरकार के कुल ऋणों (₹ 5,752.21 करोड़) का 27.10 *प्रतिशत* था। इन ऋणों पर भुगतानित ब्याज 2008-09 में 7.61 *प्रतिशत* से 2012-13 में 8.45 *प्रतिशत* की औसत दर से वर्ष 2008-09 में ₹ 414 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 743 करोड़ हो गया। पुनर्भुगतान की धीमी गति आगामी वर्षों में ऋणों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को बढ़ाएगी। सरकार पर मौजूदा बाजार ऋण का दवाब भी विचारणीय होगा। उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2009-10 से आगे बाजार ऋणों में बढ़ाव की प्रवृत्ति थी। 2009-10 से 2012-13 के दौरान प्राप्तियों ने तिगुनी वृद्धि दर्शाई। यह राज्य सरकार की बाजार ऋण पर निरंतर निर्भरता को दर्शाती है।

एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 की धारा 4 (द) अनुबंधित करती है कि ऋणों का उपयोग चालू व्ययों के वित्तपोषण में न होकर स्व-पालनीय विकास क्रियाकलापों तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन या वृद्धि में होना चाहिए। सरकार को ऋण के प्रत्येक अंश हेतु यह उद्देश्य सूचित करना है कि प्राप्त ऋण का विकास योजनाओं विशेषतया उनमें जो ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन और उद्योगों और उनमें भी जो विशेषकर कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करती है, करना है। वित्त विभाग के अभिलेखों (2008-09 से 2012-13) ने दर्शाया कि सरकार ने उक्त उद्देश्यों हेतु बाजार ऋणों को उठाया जो **तालिका 1.27** में दिया गया है:

तालिका-1.27

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण और पुनर्भुगतान का विवरण *(₹ करोड़)*

वर्ष	बाजार ऋणों की धनराशि				
	लिया गया	पुनर्भुगतान के उद्देश्य हेतु		पूँजीगत व्यय के उद्देश्य हेतु	
		धनराशि	*प्रतिशत*	धनराशि	*प्रतिशत*
2008-09	1010.69	126.46	*12.51*	884.23	*87.49*
2009-10	600.00	139.53	*23.26*	460.47	*76.74*
2010-11	991.52	102.00	*10.29*	889.52	*89.71*
2011-12	1400.00	240.73	*17.14*	1160.00	*82.86*
2012-13	1750.00	950.00	*54.29*	800.00	*45.71*

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सरकार ने नए ऋणों (2008-09 से 2012-13) के औसतन 24 *प्रतिशत* का उपयोग परिपक्व बाजार ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु किया जबकि औसतन 76 *प्रतिशत* पूँजीगत व्यय हेतु संदर्भित वर्षों में प्रयोग किया गया। नए ऋणों से परिपक्व बाजार ऋणों का भुगतान इन ऋणों के उद्देश्यों को असफल करने के अतिरिक्त एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध था।

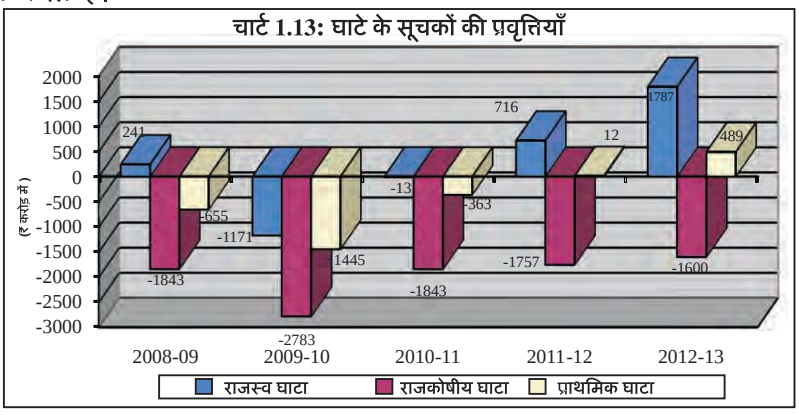
1.11 राजकोषीय असंतुलन

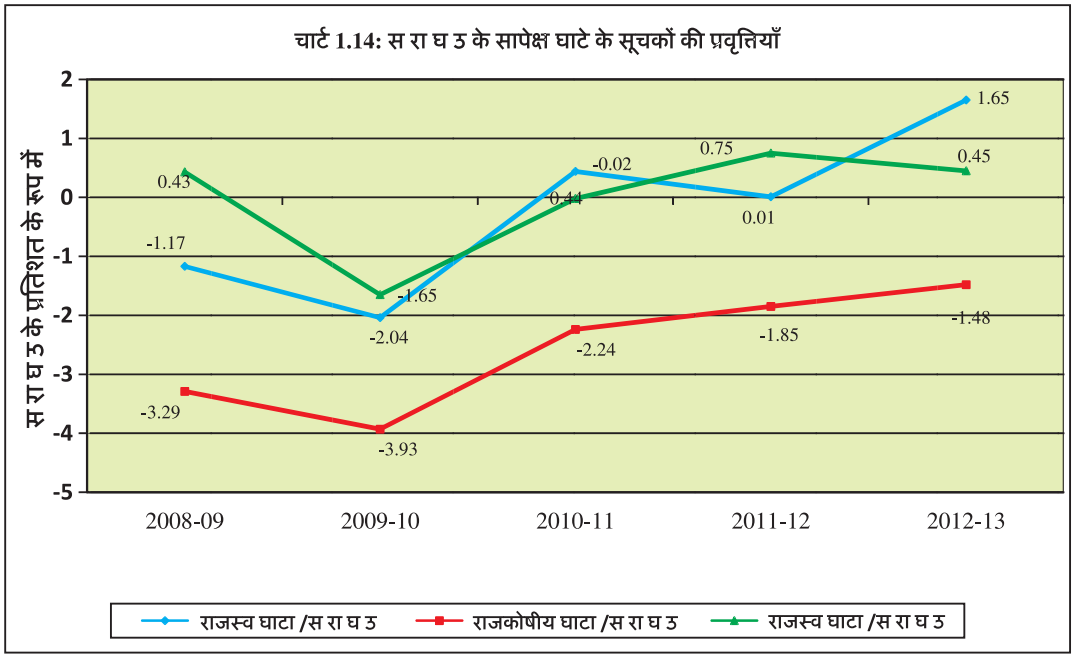
1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा-एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। पुनः, किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड, इन घाटों की प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण एवं वित्त पोषण के ढंग तथा एफ आर बी एम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन को भी प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.13 एवं **1.14**, 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.13: घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियाँ





राज्य ने 2008-09 तक राजस्व आधिक्य का अनुभव किया जो 2009-10 में मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन से घाटे में बदल गया। तथापि राज्य वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे लाने में और वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का आधिक्य प्राप्त करने में कामयाब रहा जो 2012-13 में बढकर ₹ 1,787 करोड़ हो गया।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2010-11 में कम किया गया और एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में निर्धारित चार *प्रतिशत* लक्ष्य से नीचे स रा घ उ का 2.19 *प्रतिशत* था। सरकार के द्वारा राजकोषीय समेकन के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप ही 2011-12 और 2012-13 में भी राजकोषीय घाटे में कमी हुई। ₹ 1,600 करोड़ का राजकोषीय घाटा, स रा घ उ के 1.48 *प्रतिशत* पर वर्तमान रूप में टिका है और इस संदर्भ में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3.5 *प्रतिशत* के अन्तर्गत ही है।

वर्ष 2007-09 तक कुछ नियन्त्रण में रहने वाले प्राथमिक घाटे ने 2009-10 (₹ 1,445 करोड़) में मात्रात्मक उछाल लिया था और वर्ष 2010-11 में नीचे (₹ 363 करोड़) आ गया और वर्ष 2011-12 में धनात्मक हो गया। वर्ष के दौरान भी यह धनात्मक दिशा में रहा और चालू वर्ष के दौरान बढकर ₹ 489 करोड़ हो गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि **तालिका 1.28** में परिलक्षित है।

तालिका-1.28
राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटे का विघटन						
1	राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	(+) 241	(-) 1,171	(-) 13	(+)716	(+)1,787
2	पूँजीगत व्यय	(-) 2,016	(-) 1,647	(-) 1,855	(-) 2,317	(-) 3,542
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 68	(+) 35	(+) 25	(-)156	(+)155
राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति						
1	बाजार ऋण	884	460	890	1,159	800
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 19	(-)5	16	20	6
3	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	120	672	921	332	505
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	204	70	182	131	215
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	531	1,066	870	626	271
6	जमा एवं अग्रिम	61	229	46	33	219
7	उचन्त एवं विविध	(-) 331	722	(-) 331	(-)412	479
8	प्रेषण	(-) 238	(-)129	(-) 303	(-)466	(-)101
9	अन्य	127	(-)6	242	190	66
10	कुल आधिक्य/घाटा(नकद शेष)	504	(-) 296	(-) 690	144	(-)860
11	**सकल राजकोषीय घाटा**	**1,843**	**2,783**	**1,843**	**1,757**	**1,600**

स्रोतः उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे, 2012-13

राजस्व आधिक्य जो कि 2009-10 में राजस्व व्यय में अत्यन्त उछाल के कारण घाटे में बदल गया था, वर्ष 2011-12 के दौरान पुन: आधिक्य में बदल गया और चालू वर्ष के दौरान पुनः ₹ 1,071 करोड़ से बढा और वर्ष 2012-13 के अन्त में ₹ 1,787 करोड़ पर रहा । राजकोषीय घाटा (₹ 1,600 करोड़) बड़ी मात्रा मे बाजार की उधारियों (₹ 800 करोड़) और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 505 करोड़) से प्रबन्धित किया गया। यद्यपि, वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि (52.88 *प्रतिशत*) हुई, फिर भी राजकोषीय घाटे को तर्कसंगत सीमा अर्थात् स रा घ उ के 3.5 *प्रतिशत* तक (तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार) चालू वर्ष के दौरान नीचे लाया गया (स रा घ उ का 1.48 *प्रतिशत*)।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटा एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता के सूचक होंगे। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक वर्तमान उपभोग के लिये ऋण निधियों का उपयोग किया गया था। पुनः राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं थे। प्राथमिक घाटे का विभाजन **(तालिका 1.29)** उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.29

प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणेत्तर प्राप्तियाँ*	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (3+4+5)**	**7 (2-3)**	**8 (2-6)**
2008-09	8,689	7,206	2,016	122	9,344	(+) 1,483	(-) 655
2009-10	9,551	9,319	1,647	30	10,996	(+)232	(-) 1,445
2010-11	11,693	10,141	1,855	60	12,056	(+) 1,552	(-) 363
2011-12	13,782	11,206	2,317	247	13,770	(+)2,576	(+)12
2012-13	16,175	11,871	3,542	273	15,686	(+)4,304	(+)489

** लोक ऋण प्राप्तियों से इतर प्राप्तियाँ अर्थात ऐसी प्राप्तियाँ जिन्हें वापस नहीं किया जाता है*

- ऋणेतर प्राप्तियाँ 2008-09 से 2012-13 तक 86.15 *प्रतिशत* बढ़ी और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। तथापि, अन्तराल जो 2009-10 में काफी कम हो गया था, पुन: 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई।
- कुल प्राथमिक व्यय में 2008-09 की तुलना में 2012-13 के दौरान ₹ 6,342 करोड़ (67.87 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, यह वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 4,665 करोड़ (64.74 *प्रतिशत*) की सीमा तक प्राथमिक राजस्व व्यय की वृद्धि के कारण थी।
- प्राथमिक राजस्व आधिक्य, जिसने 2009-10 में तीव्र उतार दर्शाया, पुन: पिछले तीन वर्षों के दौरान तीव्र उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई और वर्ष 2012-13 के दौरान बढकर ₹ 4,304 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2011-12 के दौरान, प्राथमिक घाटा, ऋणेत्तर प्राप्तियों में वृद्धि होने के कारण प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हुआ और वर्ष 2012-13 के दौरान भी धनात्मक रहा और वर्ष 2012-13 के अंत में बढकर ₹ 489 करोड़ हो गया।

1.12 विगत राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

उत्तराखण्ड में राज्य वित्त पर किसी भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति (सितम्बर 2013) द्वारा चर्चा नहीं की गई। तदानुसार, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

1.13 निष्कर्ष

चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,056 करोड़ (15.02 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः संघ के करों व शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 407 करोड़), राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 799 करोड़) और करेत्तर राजस्व (₹ 467 करोड़) में बढ़ोत्तरी के कारण थी। राज्य की व्यय पद्धति उदघाटित करती है कि कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व व्यय चालू वर्ष में घटा तथा करीब 78.54 *प्रतिशत* रहा। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) में विगत वर्ष की तुलना में 8.25 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन पर व्यय 49.63 *प्रतिशत* था और एन पी आर ई के एक बड़े अंश को खपत करने की निरंतरता बनाए रहा। वर्ष 2012-13 में पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 1,366 करोड़ था जो

राजस्व प्राप्तियों का 8.67 *प्रतिशत* था। पेंशन भुगतान, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक (₹ 1,329 करोड़) से कुछ अधिक (₹ 37 करोड़) था **(तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7)**। राज्य को आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के घटकों को नियंत्रित करने के लिए उपाय ढूँढने चाहिए तथा ब्याज कटौती के लिए आवश्यकता आधारित उधार पर आश्रित रहना चाहिए।

गत वर्ष की तुलना में 2012-13 में राज्य के पूँजीगत व्यय में ₹ 1,225 करोड़ की वृद्धि हुई जो मुख्यतः (i) सामाजिक सेवाओं और (ii) आर्थिक सेवाओं में वृद्धि के कारण थी। कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में पूँजीगत व्यय ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि में विचलनशील प्रवृत्ति दर्शाई जो वर्ष 2008-09 में 19 *प्रतिशत* व वर्ष 2012-13 में 20 *प्रतिशत* था। चालू वर्ष में इसने पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (52.87 *प्रतिशत*) दर्शाई लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने ब आ (₹ 3,653 करोड़) और एम टी एफ पी एस (₹ 4,547 करोड़) में निर्धारित लक्ष्य से नीचे (₹ 3,542 करोड़) रहा।

विकासपरक पूँजीगत व्यय के अंश ने भी अन्तर्वर्षीय भिन्नता दर्शाई लेकिन वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान बढ़ गया। तथापि समग्र विकासपरक व्यय वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान 69 *प्रतिशत* बढ़ गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में सरकार के निवेश पर पिछले तीन वर्षों में औसत प्रतिफल लगभग नगण्य था जबकि सरकार ने वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 के दौरान अपने ऋणों पर औसतन 7.89 *प्रतिशत* की दर से ब्याज भुगतान किया।

राज्य ने वर्ष 2007-08 से वर्ष 2008-09 तक राजस्व आधिक्य अनुभव किया जो वर्ष 2009-10 में मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के कारण घाटे में बदल गया तथापि राज्य वर्ष 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹13 करोड़) तक लाने में कामयाब हो पाया था और वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया जिसमें चालू वर्ष में पुनः सुधार आया और ₹ 1,787 करोड़ पर रहा।

राजकोषीय घाटा को जो कि 2009-10 के दौरान उच्च स्तर पर , स रा घ उ का 3.93 *प्रतिशत* था, जो 2010-11 और 2011-12 में 3.5 *प्रतिशत* की तर्कसंगत सीमा तक नीचे लाया गया। 2012-13 के दौरान ₹ 1,600 करोड़ का राज्य का राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 1.48 *प्रतिशत था,* जो राजकोषीय समेकन को दर्शाता है।

वर्ष 2012-13 के अंत में राज्य के रोकड़ शेष में ₹ 860 करोड़ का आधिक्य हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक में नकद शेषों के निवेश व भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर प्राप्त ब्याज नगण्य (1.06 *प्रतिशत)* था, जबकि सरकार ने 7.89 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर पर ऋण लिया। तथापि, राज्य निम्नतम नकद शेष बना रख पाया और वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट सुविधा का सहारा नहीं लिया।

2012-13 में ऋण - स रा घ उ अनुपात, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक 40.00 *प्रतिशत* से काफी नीचे, 23.57 *प्रतिशत* पर था। राज्य ने वर्ष 2011-12 में प्राथमिक आधिक्य की स्थिति प्राप्त कर ली थी जो चालू वित्तीय वर्ष में पर्याप्त रूप से बढ़ी (₹ 489 करोड़)। 31 मार्च 2013 को लोक ऋण ₹ 18,800 करोड़ है और ऋणों का 50 *प्रतिशत* सात वर्षों और अधिक की परिपक्वता अवधि में है ।

वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 1,568 करोड़ की एक बड़ी धनराशि सीधे राज्य क्रियानव्यन अभिकरणों को अन्तरित की गयी। तथापि, इन निधियों को राज्य बजट/राजकोष पद्धति के माध्यम से नहीं दिया

गया। जैसे कि यह निधियाँ राज्य बजट के बाहर रहती है, इनके उपयोग का अनुश्रवण करने के लिये एक भी अभिकरण नहीं है और तत्काल रूप से उपलब्ध कोई ऐसे आँकड़े नहीं है ताकि किसी विशेष वर्ष में प्रमुख चिन्हित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में वास्तव में कितना व्यय हुआ है, आँका जाए।

1.14 संस्तुतियाँ

सरकार को चाहिए कि:

- सभी परियोजनाओं को तत्परता से पूरा करने के लिए प्रभावशाली कार्ययोजना तैयार करे ताकि लोग समय पर परिलक्षित लाभ प्राप्त करें;
- निवेश में धन के बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय लेने हेतु विचार करे; और
- क्रियानव्यन अभिकरणों को सीधे अन्तरित धनराशि के उपयोग का अनुश्रवण के लिए एक प्रबन्ध सूचना प्रणाली स्थापित करने पर विचार करे।

अध्याय – 2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, दत्तमत एवं भारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के सापेक्ष बजट के भारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संदर्भ में विनियोग लेखों में उन अधिकृत को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधान को सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, भारित किया गया है। यह, ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया ऐसा व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2012-13 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति **तालिका 2.1** में दी गयी है:

तालिका-2.1

वर्ष 2012-13 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति *(₹ करोड़ में)*

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	1,34,84.90	8,22.24	1,43,07.14	1,16,86.24	(-)26,20.90
	II पूँजीगत	36,51.98	13,78.30	50,30.28	50,92.61	(+)62.33
	III ऋण एवं अग्रिम	2,64.05	1,55.21	4,19.26	2,72.57	(-)1,46.69
योग-दत्तमत		**1,74,00.93**	**23,55.75**	**1,97,56.68**	**1,70,51.42**	**(-) 27,05.26**
भारित	IV राजस्व	*22,32.21*	*99.87*	*2332.08*	*22,80.58*	*(-)51.50*
	V पूँजीगत	*1.50*	*9.50*	*11.00*	*9.02*	*(-)1.98*
	VI लोक ऋण- पुनर्भुगतान	*22,97.13*	*0.00*	*22,97.13*	*14,87.37*	*(-)8,09.76*
योग-भारित		**45,30.84**	**1,09.37**	**46,40.21**	**37,76.97**	**(-)8,63.24**
आकस्मिकता निधि में विनियोग (यदि कोई हो)		-	-	-	-	--
कुल योग		**2,19,31.77**	**24,65.12**	**2,43,96.89**	**2,08,28.39**	**(-) 35,68.50**

तालिका 2.1 के अनुसार, ₹ 35,68.50 करोड़ की बचत (निधियों के उपयोग में कमी), राजस्व खण्ड (36 प्रकरणों) और पूँजीगत खण्ड (23 प्रकरणों) के अनुदान तथा विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 54,03.84

करोड़ की बचत जो राजस्व खण्ड के अन्तर्गत एक अनुदान व एक विनियोग एवं पूँजीगत खण्ड के अन्तर्गत पाँच अनुदानों में ₹ 18,35.34 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई, के परिणामस्वरूप थी। जिन विभागों के विरूद्ध महत्वपूर्ण बचत (₹ 100 करोड़ से ज्यादा) जानकारी में आयी वे शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति (₹ 6,89.62 करोड), वित्त (₹ 611.22 करोड़), जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (₹ 461.21 करोड़), ऊर्जा (₹ 3,68.40 करोड़), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 3,64.38 करोड़), अनुसूचित जातियों का कल्याण (₹ 3,18.10 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 2,87.72 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 265.55 करोड़), खाद्य (₹ 230.83 करोड़), कल्याण (195.50 करोड़) और कृषि (₹ 1,31.83 करोड़) थे। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 के दौरान जिन विभागों में आवंटन पर महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य पाया गया उनमें खाद्य (₹ 18,10.59 करोड़), कृषि (₹ 13.27 करोड़), लोक निर्माण (₹ 6.35 करोड़) एवं उद्यान विभाग (₹ 4.50 करोड़) थे।

पर्याप्त बचत/आधिक्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध करते हुए बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) को उन्हें सूचित किया गया था (अगस्त 2013)। उनके उत्तर सितम्बर 2013 तक प्रतीक्षित थे।

2.3 वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्यय के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से पता चला कि बचत 49 प्रकरणों में, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं 29 प्रकरणों में कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थीं **(परिशिष्ट-2.1)**। ₹ 54,03.84 करोड़ की कुल बचत के विरूद्ध 16 अनुदानों से सम्बन्धित 21 प्रकरणों में ₹ 41,09.06 करोड़, (76.04 *प्रतिशत*)[1] की बचत हुई जैसा कि **तालिका 2.2** में प्रदर्शित है।

तालिका-2.2

₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची *(₹ करोड़ में)*

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व-दत्तमत						
1.	04 - न्याय प्रशासन	1,29.17	6.16	1,35.33	84.43	50.90
2.	06 - राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4,21.16	12.24	4,33.40	3,69.00	64.40
3.	07 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	26,29.00	13.36	26,42.36	20,93.18	5,49.18
4.	11 - शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	39,85.03	2,12.56	41,97.59	36,30.00	5,67.59
5.	12 - चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8,64.80	35.32	9,00.12	7,66.71	1,33.41
6.	13 - जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	5,37.30	85.59	6,22.89	4,69.67	1,53.22
7.	15 - कल्याण	6,39.20	69.68	7,08.88	5,16.92	1,91.96
8.	17 - कृषि कार्य एवं शोध	3,96.14	20.12	4,16.26	2,84.43	1,31.83
9.	19 - ग्रामीण विकास	3,78.20	11.32	3,89.52	2,56.52	1,33.00
10.	22 - लोक निर्माण	4,88.24	48.55	5,36.79	4,79.95	56.84
11.	25 - खाद्य	3,82.99	0.22	3,83.21	1,52.38	2,30.83
12.	30 - अनुसूचित जातियों का कल्याण	4,75.46	31.71	5,07.17	3,92.79	1,14.38
पूँजीगत-दत्तमत						
13.	11 - शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2,52.18	1,07.31	3,59.49	2,37.46	1,22.03
14.	12 - चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,88.38	1,77.45	3,65.83	1,34.86	2,30.97

[1] प्रत्येक प्रकरण में 50 करोड़ से अधिक।

15.	13 - जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	4,92.50	67.00	5,59.50	2,51.51	3,07.99
16.	19 - ग्रामीण विकास	2,92.36	20.00	3,12.36	1,79.81	1,32.55
17.	20 - सिंचाई एवं बाढ़	5,98.23	96.05	6,94.28	4,38.01	2,56.27
18.	21 - ऊर्जा	5,47.01	4,04.11	9,51.12	5,82.72	3,68.40
19.	26 - पर्यटन	52.45	21.89	74.34	19.02	55.32
20.	30 - अनुसूचित जातियों का कल्याण	3,19.04	42.56	3,61.60	1, 57.89	2,03.71
21.	31 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	92.36	2.42	94.78	40.50	54.28
योग		**1,41,61.20**	**14,85.62**	**15,66.82**	**1,15,37.76**	**41,09.06**

अधिकतर मामलों में बचत के कारण सितम्बर 2013 तक प्रतीक्षित थे।

2.3.2 निरन्तर बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान 19 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत हुई **(तालिका 2.3)।**

तालिका-2.3

पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची *(₹ करोड़ में)*

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
राजस्व-दत्तमत						
1	04-न्याय प्रशासन	16.29	28.57	29.91	28.05	50.90
2	05-निर्वाचन	3.68	3.65	1.03	4.71	4.57
3	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	67.57	56.74	29.52	43.94	64.40
4	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	394.33	418.97	106.35	580.10	5,49.18
5	12-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	122.06	91.88	124.39	153.99	1,33.41
6	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	88.69	47.75	372.80	235.77	1,53.22
7	15-कल्याण	93.53	80.43	83.72	197.45	1,91.96
8	16-श्रम एवं रोजगार	35.29	5.61	12.08	12.39	36.45
9	18- सहकारिता	7.72	1.83	4.87	10.30	6.03
10	19-ग्राम्य विकास	45.13	70.21	75.22	92.71	1,33.00
11	22- लोक निर्माण	51.18	28.64	34.94	35.43	56.85
12	23- उद्योग	13.08	1.34	5.15	14.47	11.32
13	24-परिवहन	11.56	5.62	2.52	1.37	5.90
14	26- पर्यटन	2.31	2.85	2.92	30.66	30.05
15	28-पशुपालन	7.38	8.49	15.53	4.48	9.04
पूँजीगत-दत्तमत						
1	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	45.12	51.24	8.78	72.43	20.60
2	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	14.57	7.80	60.20	166.31	122.03
3	15-कल्याण	6.39	5.09	13.74	22.03	3.54
4	23-उद्योग	5.41	9.55	11.54	13.35	23.69

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

2.3.3 व्ययाधिक्य

पाँच प्रकरणों में, ₹ 29,59.59 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 18,35.09 करोड़ अधिक था और प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था।

इसका ब्यौरा **परिशिष्ट-2.2** में दिया गया है। इनमें से निम्न अनुदानों/शीर्षों (**तालिका 2.4**) में पिछले पाँच वर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है।

तालिका-2.4
वर्ष 2008-13 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची *(₹ करोड़ में)*

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की राशि				
		2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
पूँजीगत-दत्तमत						
1	17-कृषि कार्य एवं शोध	11.72	11.73	30.82	18.33	13.27
2	25-खाद्य	5,64.40	9,16.31	12,07.14	12,83.25	18,10.59
योग		**5,76.12**	**9,28.04**	**12,37.96**	**13,01.58**	**18,23.86**

इन अनुदानों/शीर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य काल्पनिक बजट आकलनों का सूचक है। अतः सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्ध हेतु, इन शीर्षों के अन्तर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण अधिक यथार्थवादी होना चाहिए ताकि भविष्य में निरन्तर व्ययाधिक्य की पुनरावृत्ति न हो। निरन्तर व्ययाधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2013)।

2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि, बिना मूल आकलन/अनुपूरक माँग में कोई प्रावधान एवं बिना इसके पुनर्विनियोजन आदेश के प्रभाव के एक प्रकरण में ₹ 4.50 करोड़ का व्यय कर दिया गया, जैसा **तालिका-2.5** में वर्णित है।

तालिका-2.5
वर्ष 2012-13 के दौरान बिना प्रावधान के किये गये व्यय *(₹ करोड़ में)*

अनुदान की संख्या एवं नाम	बिना प्रावधान के व्यय की राशि	कारण/अभ्युक्तियाँ
29-उद्यान विकास (पूँजीगत दत्तमत)	4.50	कारण प्रतीक्षित थे

यद्यपि, 31 मार्च 2011 तथा 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया गया था, तथापि राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा अद्यतन वर्ष के दौरान बजट प्रावधान के बिना इसी शीर्ष में ₹ 4.50 करोड़ का व्यय किया है जो कि अनियमित है और इसके विनियमन की आवश्यकता है।

2.3.5 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोग पर व्ययाधिक्य का राज्य विधायिका द्वारा विनियमन किया जाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अन्तर्गत, व्यय के विनियमन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, व्ययाधिक्य का विनियमन लोक लेखा समिति (पी ए सी) द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। तथापि, 2005-12 के वर्षों के ₹ 73,93.91 करोड़ की राशि के व्ययाधिक्य का राज्य विधानमण्डल द्वारा विनियमन अब तक किया जाना प्रतीक्षित था। विनियमन हेतु लम्बित व्ययाधिक्य की वर्षवार राशि **तालिका-2.6** में सारांशित है।

तालिका-2.6

विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की राशि	विनियमन की स्थिति
	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोगों के ब्यौरे		
2005-06	7	7,8,17,20,22,25&29	6,63.50	राज्य सरकार द्वारा स्थिति सूचित नहीं की गयी
2006-07	6	7,17,20,22,25& 29	9,35.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 & 29	7,33.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25&29	11,46.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25&29	10,07.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 & 29	12,95.40	
2011-12	5	7,17,22,25&29	16,11.40	
योग			**73,93.91**	

विगत वर्षों के अनुदानों/विनियोगों में प्रावधान से अधिक किये गये व्यय को राज्य विधायिका द्वारा शीघ्रातिशीघ्र विनियमन कराने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

2.3.6 वर्ष 2012-13 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका 2.7 में वर्ष 2012-13 के दौरान पाँच अनुदानों में राज्य की संचित निधि (सी एफ एस) से प्राधिकृत से अधिक व्यय ₹ 18,35.34 करोड़ का सार सम्मिलित है।

तालिका-2.7

2012-13 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय *(₹ हजार में)*

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
राजस्व दत्तमत					
1	21	ऊर्जा	122876	125464	2588
राजस्व भारित					
1	12	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	--	*10*	*10*
पूंजीगत – दत्तमत					
1	14	सूचना	10000	13760	3760
2	17	कृषि कार्य एवं शोध	1783032	1915753	132721
3	22	लोक निर्माण	9132000	9195465	63465
4	25	खाद्य	320000	18425895	18105895
5	29	उद्यान विकास	00	45000	45000
योग			**11367908**	**29721347**	**18353439**

राज्य सरकार/विभाग द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों को अगस्त 2013 तक सूचित नहीं किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गये व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित कर लेना चाहिए।

2.3.7 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 37 प्रकरणों में जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक के थे, कुल ₹ 11,42.69 करोड़ प्राप्त किया गया, अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा **परिशिष्ट-2.3** में वर्णित किया गया है।

₹ 3,93.03 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान तीन प्रकरणों में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 18,30.22 करोड़ का व्ययाधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा **(परिशिष्ट-2.4)**।

2.3.8 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें पूर्वानुमानित हों, से दूसरी इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, को निधियों का स्थानान्तरण है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप 83 उपशीर्षों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक बचत/आधिक्य हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में वर्णित है। इस प्रकार चार अनुदानों में ₹ 185.40 करोड़ (प्रत्येक अनुदान में ₹ 20.00 करोड़ से अधिक) की बचत हुई जो इस प्रकार थी, अनुदान संख्या 11 - शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति में ₹ 74.56 करोड़, अनुदान संख्या 13 - जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास में ₹ 24.57 करोड़, अनुदान संख्या 19 - ग्रामीण विकास में ₹ 23.16 करोड़, अनुदान संख्या 22 - लोक निर्माण में ₹ 63.11 करोड़। बचत के कारण सरकार द्वारा सितम्बर 2013 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे। तथापि, 53 प्रकरणों में 20 से 31 मार्च 2013 के मध्य ₹ 25.46 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था।

उपर्युक्त प्रकरणों में पर्याप्त बचत प्रदर्शित करती है कि सम्बद्ध विभागों द्वारा निधियों को व्यय नहीं किया जा सका जैसा कि योजनाओं के अन्तर्गत प्राक्कलित एवं नियोजित था।

2.3.9 पर्याप्त अभ्यर्पण

110 उपशीर्षों में, योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन न किये जाने या धीमे क्रियान्वयन के कारण पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* से अधिक अभ्यर्पित किया गया) हुए। इन 110 उपशीर्षों में ₹ 8,57.29 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 6,43.14 करोड़ (75.02 *प्रतिशत*) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 53 योजनाओं में शत *प्रतिशत* अभ्यर्पण (₹ 207.26 करोड़) सम्मिलित है जैसा कि **परिशिष्ट-2.6** में विस्तारित है।

2.3.10 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

दो प्रकरणों में, अभ्यर्पित की गयी राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी, जो इन विभागों में बजटीय नियन्त्रण की कमी को इंगित करती है। इन प्रकरणों में ₹ 82.35 करोड़ की बचत के विरूद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 91.10 करोड़ थी परिणामस्वरूप ₹ 8.75 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.7 अ** में दिये गये हैं।

एक मामले (लोक निर्माण) में, ₹ 6.35 करोड़ का अन्तिम आधिक्य होते हुए भी ₹ 24.51 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.7 ब** में दिया गया है।

2.3.11 अनुमानित बचत जो अभ्यर्पित नहीं हुई

बजट नियमावली के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों के लिए जब और जैसे ही बचत का पुर्वानुमान हो जाए, आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों या उनका एक भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पित करें। तथापि, वर्ष 2012-13 के अंत में, नौ अनुदान एवं एक विनियोजन ऐसे थे जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक की बचत हुई फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 18,45.44 करोड़ (कुल बचत का 34.15 *प्रतिशत*) थी (**परिशिष्ट-2.8**)।

इसी प्रकार, ₹ 52,69.65 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से ₹ 11,82.79 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था और परिणाम स्वरूप ₹ 40,86.86 करोड़ (कुल बचत का

75.63 *प्रतिशत*), अभ्यर्पण नहीं हुआ। इसे **परिशिष्ट-2.9** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 22 प्रकरणों में (₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण), ₹ 1187.76 करोड़ मार्च 2013 के अंतिम दो कार्य दिवसों में अभ्यर्पित किए गए (**परिशिष्ट-2.10**)। यह अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य विकासात्मक कार्यों के प्रयोग में नहीं लायी जा सकी।

2.3.12 व्यय की तीव्रता

वित्तीय विनियम के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। इसके विपरीत, **परिशिष्ट-2.11** में सूचीबद्ध 50 उपमुख्य शीर्षों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक या एक वर्ष में किये जाने वाले कुल व्यय का 50 *प्रतिशत* से अधिक के व्यय अन्तिम तिमाही में या मार्च 2013 में किया गया था। **तालिका-2.8** भी उन मुख्य शीर्षों को दर्शाती है जिनमें 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय या तो वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया था अथवा अन्तिम माह में किया गया था।

तालिका-2.8

वित्तीय वर्ष 2012-13 के समापन के समय व्यय की तीव्रता के प्रकरण *(₹ करोड़ में)*

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2013 के दौरान व्यय	
			राशि *(₹ करोड़ में)*	कुल व्यय का *प्रतिशत*	राशि *(₹ करोड़ में)*	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	**2015**	19.44	10.16	52.26	4.92	25.31
2.	**2030**	22.95	15.51	67.58	7.69	33.51
3.	**2215**	4,15.52	2,17.01	52.23	1,05.96	25.50
4.	**2216**	1.90	1.18	62.11	0.95	50.00
5.	**2225**	2,05.28	1,02.84	50.10	69.84	34.02
6.	**2250**	43.81	31.00	70.76	23.29	53.16
7.	**2251**	0.06	0.05	83.33	0.04	66.67
8.	**2408**	1,47.50	1,13.15	76.71	1,10.47	74.89
9.	**2425**	35.15	20.06	57.07	8.83	25.12
10.	**2701**	13.17	7.38	56.04	4.88	37.05
11.	**2702**	68.75	45.64	66.39	16.93	24.63
12.	**2810**	13.86	9.95	71.79	1.58	11.40
13.	**3054**	1,83.26	1,02.71	56.05	86.38	47.14
14.	**3454**	16.30	8.24	50.55	6.18	37.91
15.	**4055**	28.50	22.78	79.93	21.76	76.35
16.	**4059**	1,00.87	82.50	81.79	39.27	38.93
17.	**4202**	2,46.82	2,18.41	88.49	1,80.11	72.97
18.	**4210**	1,34.52	1,15.88	86.14	1,01.51	75.46
19.	**4211**	4.80	2.89	60.21	2.05	42.71
20.	**4215**	1,12.97	66.24	58.64	17.44	15.44
21.	**4216**	12.31	7.43	60.36	5.67	46.06
22.	**4217**	1,42.82	74.97	52.49	74.97	52.49
23.	**4225**	37.35	36.37	97.38	32.42	86.80
24.	**4235**	5.98	3.85	64.38	3.85	64.38
25.	**4250**	17.25	10.59	61.39	10.59	61.39

26.	**4401**	17.23	25.82	1,49.85	20.64	1,19.79
27.	**4406**	41.51	24.25	58.42	15.40	37.10
28.	**4700**	2,57.95	1,67.79	65.05	1,40.69	54.54
29.	**4701**	0.61	0.61	1,00.00	0.56	91.80
30.	**4702**	88.79	67.09	75.56	39.94	44.98
31.	**4711**	39.50	25.20	63.80	24.60	62.28
32.	**4801**	5,16.12	4,54.88	88.13	4,52.67	87.71
33.	**4859**	16.16	13.81	85.46	10.70	66.21
34.	**5053**	95.44	95.17	99.72	95.18	99.73
35.	**5054**	8,72.77	4,90.54	56.20	3,57.02	40.91
36.	**5055**	0.93	0.54	58.06	0.54	58.06
37.	**5452**	20.23	14.83	73.31	5.69	28.13
38.	**6003**	14,58.74	7,79.82	53.46	4,17.22	28.60
39.	**6075**	3.08	3.08	1,00.00	0.00	0.00
40.	**6401**	156.36	1,40.83	90.07	1,00.83	64.49
41.	**6425**	2.31	1.80	77.92	0.96	41.56
42.	**7055**	25.00	25.00	1,00.00	25.00	1,00.00
43.	**7610**	1.03	0.56	54.37	0.17	16.50
योग		**56,44.90**	**36,58.41**	**65.29**	**26,45.39**	**46.86**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा वी एल सी से संकलित आँकड़े ।

संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान इन मुख्य शीर्षों के कुल व्यय ₹ 56,44.90 करोड़ का 65.29 *प्रतिशत* वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया। आगे, उपर्युक्त 26 विशिष्ट प्रकरणों में, ₹ 10 करोड़ से अधिक का व्यय अकेले माह मार्च 2013 में किया गया था।

वित्तीय विनियमन के दृष्टिकोण के विपरीत सरकार द्वारा भारी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में किया गया जो व्यय पर कमजोर वित्तीय नियन्त्रण का सूचक था। ठोस वित्तीय प्रबन्धन के लिए व्यय में एकरूपता बनाये रखा जाना चाहिए।

2.4 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

2.4.1 सार आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल (ए सी बिल) में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पहले के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक प्रभारों के विस्तृत बिल सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रेषित और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित कर दिये गये हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 3.68 करोड़ के ए सी बिलों के विरूद्ध केवल ₹ 0.74 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी बिलों) की राशि ही प्राप्त हुई, जिससे अगस्त 2013 तक ₹ 2.94 करोड़ के ए सी बिलों का निस्तारण अवशेष पड़ा रहा। वर्षवार विवरण **तालिका-2.9** में दिया गया है।

तालिका-2.9
सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना
(अगस्त 2013 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए सी बिलों की राशि	डी सी बिलों की राशि	अवशेष ए सी बिल	
			संख्या	राशि
2009-10	1.34	1.31	2	0.03
2010-11	40.13	32.25	64	7.88
2011-12	3.56	3.40	27	0.16
2012-13	3.68	0.74	70	2.94
योग	**48.71**	**37.70**	**163**	**11.01**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

जैसा कि ऊपर तालिका से देखा जा सकता है, अगस्त 2013 के अंत तक 163 ए सी बिलों की कुल अवशेष धनराशि ₹ 11.01 करोड़ थी। आगे यह भी पाया गया कि कुल बकाया ₹ 11.01 करोड़ में से पाँच ए सी बिलों के ज़रिये मुख्य शीर्ष 2245 अन्तर्गत राहत विभाग द्वारा भारी धनराशि 1.06 करोड़ (9.63 *प्रतिशत*) आहरित की गयी (2010-11 के दौरान) तथा डी सी बिलों के अप्रस्तुतीकरण के कारण अभी तक बकाया थी। 2012-13 के कुल बकाया ए सी बिलों (₹ 2.94 करोड़) में से भारी धनराशि ₹ 2.73 करोड़ (92.86 *प्रतिशत*) मुख्य शीर्ष 2202 के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा विभाग से सम्बन्धित था। तथापि, 2012-13 से पहले के बकाया आकस्मिक बिलों की धनराशि ₹ 36.96 करोड़ (82.03 *प्रतिशत*) में अगस्त 2013 तक भारी कमी हुई।

वर्ष 2012-13 तक विभागवार लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों के अगस्त 2013 तक के डी सी बिलों के लम्बन को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ठ 2.12** में दिया गया है।

सार आकस्मिक बिल आहरित किए जाने के बाद लम्बे समय तक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत न किये जाने से दुर्विनियोजन का जोखिम है और इसलिये इसके सघन अनुश्रवण की आवश्यकता है।

2.4.2 असमाधानित व्यय

व्यय को बजट आवंटनों के अन्तर्गत रखने और उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सशक्त करने के लिए वित्तीय नियमों में निहित है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाशोधन को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों के पक्ष से चूके वर्ष 2012-13 के दौरान भी निरंतर जारी रहीं। लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि पाँच नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 50,44.86 करोड़ शामिल हैं, वर्ष 2012-13 के दौरान असमाधानित रहे जो कुल शुद्ध व्यय ₹ 1,77,75.00 करोड़ का 28.38 *प्रतिशत* थे, जैसा **तालिका 2.10** में वर्णित हैः

तालिका-2.10

नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2012-13 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही *(₹ करोड़ में)*

क्रम संख्या	नियंत्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया
1	आयुक्त, राहत, राजस्व विभाग	1,35.42
2	प्रमुख सचिव, वित्त/ सम्पदा विभाग	28,68.99
3	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ	824.92
4	सचिव, ऊर्जा	5,30.03
5	प्रमुख सचिव, सामाजिक कल्याण	6,85.50
योग		**50,44.86**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा वी एल सी से संकलित आँकड़े।

₹ 50,44.86 करोड़ की भारी रकम का वर्ष 2012-13 के दौरान असमाधानित रह जाने का मुख्य कारण, समाधान हेतु नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा पहल न किया जाना था।

इस प्रकार, गबन तथा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं के निवारण हेतु सरकार को चाहिए कि संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं के समाधान को सुनिश्चित करें।

2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना, उत्तराखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम, 2001 (2001 के अधिनियम सं. 2) के अन्तर्गत की गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु लेना चाहिए, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। यह निधि एक अग्रदाय के स्वरूप की है तथा इसका वर्तमान संग्रह ₹ 200 करोड़ है (वर्ष के दौरान संग्रह को ₹ 600 करोड़ से ₹ 200 करोड़ तक कम कर दिया गया था)। इस निधि से किसी अग्रिम आहरण की उसी वित्त वर्ष में प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। तथापि, ₹ 32.06 करोड़ के अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरित किये गये जो 31 मार्च 2013 तक सेवा शीर्ष से आकस्मिकता निधि को समायोजित किये जाने शेष थे, जैसा कि नीचे **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका-2.11

वर्ष 2012-13 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई *(₹ करोड़ में)*

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग/ अभ्यर्पण	योग	वास्तविक व्यय	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	स्वीकृति का माह
1	03	2013-मंत्रीमण्डल	33.47	(-)1.16	32.31	32.79	1.00	03/2013
2	06	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	49.11	(-)0.09	49.02	40.60	0.002	01/2013
3	16	2230-श्रम एवं रोजगार	10.62	0.00	10.62	7.91	0.028	12/2012, 02/2013 & 03/2013
4	18	2425-सहकारिता	38.32	0.00	38.32	30.29	0.0007	11/2012
5	19	4515--अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	312.36	(-)105.21	207.15	179.81	18.32	03/2013
6	26	3452-पर्यटन	72.75	0.00	72.75	42.70	12.00	02/2013
7	**30**	2403-पशुपालन	3.33	0.00	3.33	3.28	0.71	03/2013
योग			**519.96**	**(-)106.46**	**413.50**	**337.38**	**32.0607**	

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा वी एल सी से संकलित आँकड़े ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि ₹ 32.06 करोड़ के व्यय वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से अग्रिमों के रूप में किये गये तथा उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (वर्ष 2001 के अधिनियम सं. 2) की धारा 5 के अन्तर्गत अपेक्षा अनुसार इसकी प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान नहीं की गई थी।

सरकार ने वर्ष के दौरान, पूँजीगत व्यय (₹ 18.32 करोड़) हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिमों का आश्रय लिया, जो प्रत्याशित थे तथा इसी कारणवश वित्तीय प्रबन्धन के विपरीत थे।

2.6 बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ

वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं में पायी गई कमियाँ निम्नानुसार थीः

- क्षेत्र - अ कर राजस्व के नीचे मुख्य शीर्ष 0029, 0039 के नीचे लघुशीर्ष 900 वसूली एवं उपमुख्य शीर्ष 01 पंजीयन शुल्क के नीचे लघुशीर्ष 901 दर्शाये गये है; जबकि मुख्य तथा लघुशीर्षो की सूची (खण्ड-I) के अनुसार कर राजस्व क्षेत्र-अ के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक मुख्यशीर्ष, उपमुख्य शीर्ष एवं लघुशीर्ष के नीचे लघुशीर्ष 900 वापसियाँ शीर्ष दर्शाया जाना चाहिए।
- बजट साहित्य खण्ड-V भाग 1 में मुख्यशीर्ष से 3454 में उपमुख्यशीर्ष 02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के अन्तर्गत लघुशीर्ष 001 निर्देशन तथा प्रशासन का प्रावधान किया गया है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची पुस्तिका में उपमुख्य शीर्ष 01 जनगणना के अन्तर्गत 001 निर्देशन तथा प्रशासन प्रावधानित है।
- बजट साहित्य में मुख्यशीर्ष 4059 के अन्तर्गत उपमुख्यशीर्ष 60 अन्य अंकित है जबकि मुख्य एवं लघु लेखाशीर्षों की सूची में उक्त मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत उपमुख्य शीर्ष 60 में अन्य भवन का प्रावधान है।
- अनुदान संख्या 22 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष 2059 में, उपमुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102 को 'मरम्मत एवं अनुरक्षण' के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इसे मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार उपमुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 053 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
- मुख्य शीर्ष 2245 के अन्तर्गत केवल एक उपमुख्य शीर्ष 05 को दर्शाया गया है, जिसके अन्तर्गत लघुशीर्ष 800 के बारे में उपबंध है। जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार दो और उपमुख्य शीर्ष 01- सूखा तथा 02- बाढ़ व चक्रवात हैं।
- मुख्य शीर्ष 2217 के अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-04 को 'कस्बों का एकीकृत विकास' के रूप में दर्शाया गया है जबकि इसे 'झुग्गियों का विकास' के रूप में, मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में प्रावधान अनुसार अंकित किया जाना चाहिए था।
- मुख्यशीर्ष 4235 में उप मुख्यशीर्ष 02 के अन्तर्गत लघुशीर्ष 104 में विकलांग व्यक्तियों का कल्याण अंकित है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची के अनुसार इसके अन्तर्गत 'वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तियों का कल्याण' योजना अंकित होना चाहिए था तथा 'विकलांग व्यक्तियों का कल्याण' लघुशीर्ष 101 के अन्तर्गत होना चाहिए था।
- अनुदान संख्या 17 के मुख्यशीर्ष 2402 के लघुशीर्ष 101 एवं 102 को क्रमशः 'मृदा संरक्षण तथा परीक्षण' एवं 'जल संरक्षण' के रूप में दर्शाया गया है जबकि लेखाओं के मुख्य एवं लघुशीर्षों की

सूची के अनुसार इसे 'मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण' एवं 'मृदा संरक्षण' के रूप में दिखाया जाना चाहिए था।

- राजस्व एवं पूँजी लेखों की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान में मुख्यशीर्ष 1601- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जिन योनजाओं हेतु अनुदान दिया जाता है उन योजनाओं में से कई योजनाओं को उक्त मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान नही किया गया है।
- मुख्यशीर्ष 2401 के अन्तर्गत लघुशीर्ष 119 मद का नाम अंकित नही है तथा 800 अन्य योजनाएं अंकित है जबकि लेखाओं के मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची में लघुशीर्ष 119 बागवानी तथा वनस्पति फसले तथा 800 अन्य व्यय अंकित है।
- बजट साहित्य के अनुसार अनुदान संख्या 30 में मुख्यशीर्ष 2211 के अन्तर्गत लघुशीर्ष 101 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अंकित है जबकि लेखाओं के मुख्य तथा लघुशीर्षो की सूची में लघुशीर्ष 101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें अंकित हैं।
- बजट साहित्य में मुख्यशीर्ष 2048 के अन्तर्गत लघुशीर्ष 797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों से अन्तरण अंकित है जबकि लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची पुस्तिका में केवल लघुशीर्ष 101 निक्षेप निधि 200 अन्य विनियोजन ही अंकित है।
- बजट साहित्य में मुख्यशीर्ष 2052 के अन्तर्गत लघुशीर्ष 800 अन्य व्यय अंकित है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची में लघुशीर्ष 091 सलंग्न कार्यालय एवं 092 अन्य कार्यालय ही प्रावधान है।
- मुख्यशीर्ष 2030 के उप मुख्यशीर्ष 02 स्टाम्प न्यायिकेतर के अन्तर्गत लघुशीर्ष 001 के आगे मद का नाम अंकित नही है। इसी प्रकार मुख्यशीर्ष 3604 के अन्तर्गत लघुशीर्ष 200 के आगे मद का नामे अंकित नहीं है, जिससे उक्त लघुशीर्ष किस मद से सम्बन्धित है। सुनिशचित किया जाना संभव नहीं है।

2.7 सहायता अनुदानों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

किसी संस्थान/संख्या को सहायता अनुदान, सरकार के राजस्व व्यय का घटक अवश्य होना चाहिए। लेकिन वर्ष 2012-13 के दौरान अनुमोदित बजट प्रावधान के विरूद्ध निम्नलिखित पूँजीगत परिव्यय से सम्बन्धित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत सहायता अनुदान के रूप में ₹ 433.05 करोड़ के वितरण में निर्धारित भारतीय शासकीय लेखांकन मानक (भा शा ले मा-2) का उल्लघंन किया गया था जिसका विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है:

तालिका 2.12

पूँजीगत मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत सहायता अनुदानों का गलत वर्गीकरण

मुख्यशीर्ष	राशि *(₹ करोड़ में)*
4202 - शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	115.46
4210 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1.50
4215 - जलापूर्ति तथा सफाई प्रबंधन पर पूँजीगत परिव्यय	112.97
4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	10.62
4401 - कृषि पालन पर पूँजीगत परिव्यय	15.00
4515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	177.50
योग	**433.05**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा वी एल सी से संकलित आँकड़े।

उक्त त्रृटिपूर्ण वर्गीकरण के सम्बन्ध में ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

2.8 कोषागार निरीक्षण परिणाम

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कोषागारों/उपकोषागारों की जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयीं जिसे **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13
कोषागारों के जाँच का परिणाम

क्रम संख्या	श्रेणी	राशि *(₹ करोड़ में)*
1.	असमायोजित ए सी बिल	12.11
2.	जिलाधिकारी उधमसिंह नगर द्वारा कोषागार नियम 24 के अन्तर्गत जारी अग्रिम का अभी तक प्रतिपूर्ति न होना	0.05
3.	व्ययगत जमा की धनराशि का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना	0.22
4.	पी एल ए से अनधिकृत वितरण	10.65
5.	यू पी सी एल उत्तराखण्ड एवं पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तरप्रदेश के पक्ष में पेंशनरों के बकाया की वापसी	7.90
6.	विभागाध्यक्षों/निदेशकों द्वारा पेंशनरों को उपादान का कम प्राधिकरण	0. 07

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा वी एल सी से संकलित आँकड़े।

- ए सी बिल के समायोजन, जिलाधिकारियों द्वारा कोषागार नियम-24 के अन्तर्गत जारी अग्रिम, पी एल ए से अनधिकृत भुगतान, व्यपगत जमा तथा पेंशन एवं उपादान के भुगतान के सम्बन्ध में कोषागार स्तर से कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है।

2.9 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ का समीक्षा हेतु चयन किया गया था जिससे निम्नलिखित उद्घटित हुआः

व्यय की तीव्रता

सामान्य वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि वर्ष के दौरान व्यय, माहवार/त्रैमासिक प्रवाह को ध्यान में रखते हुए एक समान रूप से किया जाना चाहिए। अनुदान संख्या 07 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ) के प्रकरण में उद्घटित हुआ कि 2012-13 के दौरान निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यय के समरूप प्रवाह को बनाये नहीं रखा गया जिससे व्यय में तीव्रता आई। विवरण नीचे **तालिका 2.14** में दर्शाया गया हैः

तालिका 2.14
अन्तिम तिमाही/मार्च 2013 में व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मुख्यशीर्ष (दत्तमत)	अन्तिम तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	2012-13 के दौरान कुल व्यय	अन्तिम तिमाही में व्यय का प्रतिशत	मार्च में व्यय का प्रतिशत
1.	2030 - स्टाम्प एवं पंजीयन	15.51	7.69	22.95	67.58	33.51
2.	2049 - ब्याज का भुगतान	10,14.89	6,97.81	20,88.73	48.59	33.41
3.	3454 - जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	8.24	6.18	16.30	50.55	37.91
योग		**10,38.64**	**7,11.68**	**21,27.98**	**48.81**	**33.44**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा वी एल सी से संकलित आँकड़े।

वर्ष 2012-13 की अन्तिम तिमाही में इस अनुदान के अन्तर्गत तीन मुख्यशीर्षों में व्यय इस तथ्य के साथ कुल व्यय का 48.81 *प्रतिशत* था कि इन शीर्षों में कुल व्यय का 33.44 *प्रतिशत* व्यय अकेले मार्च 2013 में किया गया था जिससे व्यय में तीव्रता आई। यह सरकार के वित्त विभाग द्वारा व्यय को विनियमित करने में आयोजना एवं नियंत्रण का अभाव इंगित करता है।

वर्ष की समाप्ति पर व्यय की तीव्रता निष्फल, निरर्थक या पुर्विनियोजित व्यय को बढ़ावा दे सकती है। विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाँ तक व्यवाहरिक रूप से सम्भव हो वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय में तीव्रता से बचने हेतु यथा निर्धारित पूरे वर्ष में एक समान रूप से व्यय किया जाये।

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

एक वित्तीय वर्ष के दौरान, अनुदानों/विनियोगों के अर्न्तगत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता की मध्यकालिक समीक्षा के उपरान्त पूर्वानुमानित व्ययाधिक्य को पूरा करने हेतु अनुपूरक अनुदान लिये जाते हैं। तथापि यह देखा गया कि अनुदान संख्या 07 के पाँच मुख्यशीर्षों के अधीन, बिना किसी उचित नियोजन के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये गये थे जैसा **तालिका 2.15** में सारणीबद्ध हैः

तालिका 2.15
अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त अनुपूरक प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				वास्तविक व्यय	बचत
	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
2030- स्टाम्प एवं पंजीयन	26.81	0.53	0.00	27.34	22.95	(-)4.39
2045 - सामग्री एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क	8.07	2.01	0.00	10.08	6.67	(-)3.41
2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएँ	140.97	3.94	(-)2.43	142.48	87.12	(-)55.36
3454 - जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यकीय	21.70	6.80	0.00	28.50	16.30	(-)12.20
4059 - लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	26.24	5.50	0.00	31.74	20.43	(-)11.31
योग	**223.79**	**18.78**	**(-)2.43**	**240.14**	**153.47**	**(-)86.67**

अनुदान संख्या 07 के अन्तर्गत मुख्य पाँच शीर्षों हेतु लिये गये 18.78 करोड़ अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि पाँच मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत/सम्पूर्ण बचत स्वयं विभाग द्वारा प्राप्त अनुपूरक अनुदान से अधिक थी। मुख्यशीर्ष 2052 के अन्तर्गत लिये गये मूल अनुदान का मुख्य भाग [₹ 55.36 करोड़ (39.27 *प्रतिशत*)] ₹ 2.43 करोड़ के पुनर्विनियोग के बावजूद भी विभाग द्वारा अव्ययित रह गया।

निधियों का उचित उपयोग करने हेतु उचित तंत्र सरकार लागू कर सकती है।

अप्रयुक्त प्रावधान

विभिन्न विकास योजनाओं के संचालन हेतु वार्षिक वित्त विवरण में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रावधान है। अनुदान संख्या 07 में यह देखा गया कि कुछ निश्चित उपशीर्षों के अन्तर्गत किया गया सम्पूर्ण बजट प्रावधान, वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्त तक अप्रयुक्त रहा जैसा कि **तालिका 2.16** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.16
लेखाशीर्षों का विवरण जिनमें सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

क्र स	लेखाशीर्ष	बजट प्रावधान	बचत
1.	2040-00-800-04-विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	2.50	2.50
2.	2045-00-103-04-सामग्री तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	2.00	2.00
3.	2052-00-800-03-सचिवालय, सामान्य सेवाएँ	50.00	50.00
4.	2071-01-101-06- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1.00	1.00
5.	2071-01-102-06- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1.00	1.00
6.	2071-01-104-06- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1.00	1.00
7.	2071-01-105-06- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	0.50	0.50
8.	2071-01-200-06- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3.00	3.00
9.	2071-01-800-05- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1.20	1.20
10.	3451-00-092-01- सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	1.30	1.30
11.	3451-00-092-06- सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	2.00	2.00
योग		**65.50**	**65.50**

वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदान सं. 07 के विभिन्न मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित सम्पूर्ण धनराशि ₹ 65.50 करोड़ अप्रयुक्त रही। यह दर्शाता है कि अनुमान एवं आयोजना के अनुसार व्यय नहीं किया जा सका। निधियों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

2.10 निष्कर्ष

विभिन्न अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 54,03.84 करोड़ की बचत राजस्व अनुभाग के एक अनुदान तथा एक विनियोग एवं पूँजीगत अनुभाग के पाँच अनुदानों के ₹ 18,35.34 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई। परिणामस्वरूप ₹ 35,68.50 करोड़ की समग्र बचत हुई।

वर्ष के दौरान छः अनुदानों एवं एक विनियोग के अन्तर्गत सात मामलों में अनुमोदित प्रावधान पर ₹ 18,35.34 करोड़ व्ययाधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

न्याय प्रशासन, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, वित्त कर नियोजन, ऊर्जा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास, कल्याण, ग्राम्य विकास तथा लोक निर्माण अनुदानों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर भारी बचत दर्शायी गयी। निधियों का अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक/अधिक पुनर्विनियोजन के प्रकरण भी थे। अन्तिम तिमाही/वित्त वर्ष के अन्त में व्यय की तीव्रता विभागों में अपर्याप्त बजट नियन्त्रण या इसके अभाव को इंगित करती है। बहुत से प्रकरणों में, पूर्वानुमानित बचत या तो अभ्यर्पित नहीं की गयी थीं या वर्ष के अन्त में मार्च माह में समर्पित की गयीं जिसके कारण दूसरे विकासात्मक उद्देश्यों हेतु इन निधियों के उपयोग की संभावना नहीं बची थी। आकस्मिकता निधि से स्वीकृत आहरण (यद्यपि कई प्रकरणों को तात्कालिक प्रकृति का न होने के बावजूद आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया था) तथा वर्ष के अन्त तक उसका समायोजन नहीं हुआ था।

वित्तीय प्रबन्धन में इस प्रकार की कमियों से बचने के लिये बजटीय नियन्त्रणों का कड़ाई से पालन किया जाए। अन्तिम क्षणों में निधियों की अवमुक्ति और पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के आदेशों को जारी करने से बचना चाहिए। सरकार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति केवल अप्रत्याशित एवं तात्कालिक प्रकृति के व्यय मात्र को वहन करने के लिए प्रदान करें तथा निधियों के समय पर समायोजन की प्रणाली को कारगर बनाना चाहिए। नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा कठोर अनुश्रवण तन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि नियत समय सीमा के अन्तर्गत सार आकस्मिकता बिलों के समायोजन को सुनिश्चित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राज्य सरकार के बजट प्रक्रिया में लेखाशीर्षों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का मामला प्रकाश में आया।

2.11 संस्तुतियाँ

सरकार यह सुनिश्चित करे कि :

- सभी विभागों को चाहिए कि भारी बचत/आधिक्यों से बचने के लिए व्यय के रूझान तथा निधियों की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए यथार्थवादी बजट आकलन प्रस्तुत करें।
- सभी विभागों को चाहिए कि आवंटनों के सापेक्ष व्यय का सघन अनुश्रवण करें तथा अनुदानों पर हो रहे व्ययाधिक्य से कड़े तरीके से बचें।
- सभी विभागों को चाहिए कि पहले से ही बचतों की संगणना करें तथा उनका अभ्यर्पण नियत तिथि तक करें ताकि निधि की आवश्यकता वाले अन्य विभागों द्वारा इनका प्रभावी उपयोग हो सके।
- प्रचालित नियमों के अन्तर्गत सार आकस्मिकता बिलों पर आहरित अग्रिमों को नियत अवधि के अन्दर समायोजित करने हेतु विभागों में अनुश्रवण तन्त्र लागू हो।
- बजट प्रक्रिया का निर्धारण करते समय लेखाशीर्षों के तहत सही मद दर्शायी जाय।

अध्याय – 3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचनाओं सहित अच्छी आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, कार्यविधि तथा अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयपरक गुणवत्ता, सुशासन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली और क्रियात्मक हों तो, रणनीतिक आयोजना, निर्णयन तथा शेयर धारकों के उत्तरदायित्व जैसे प्रबंधात्मक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में राज्य सरकार को सहायता पहुँचाते हैं। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधि एवं अनुदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपालना की स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वितीय नियमावली में उपबंध है कि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदत्त अनुदानों के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात उन्हें अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, संस्वीकृति तिथि से 18 माहों के अन्दर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अगस्त 2013 तक ₹ 617.59 करोड़ की राशि के 599 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे। इनमें से, ₹ 256.84 करोड़ धनराशि के 213 उपयोगिता प्रमाण पत्र (35.56 *प्रतिशत*) दो वर्षों तक की अवधि से लम्बित थे तथा दो वर्षों से ऊपर के ₹ 360.75 करोड़ धनराशि के 386 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में अवधि-वार विलम्ब **तालिका-3.1** में सारांशित है।

तालिका-3.1

अगस्त 2013 को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अवधि-वार बकाये *(₹ करोड़ में)*

क्रम संख्या	वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि
1	0-1	97	146.36
2	1-2	116	110.48
3	दो वर्षों से ऊपर	386	360.75
योग		**599**	**617.59**

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभीष्ट उद्देश्य पर ही अनुदान का उपयोग किया है, जिस हेतु उनकी स्वीकृति दी गयी थी। इसलिए, प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु विभागों द्वारा प्रयास किए जाएँ।

3.2 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलाप वाले कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षित है कि वे विहित प्रपत्र में वार्षिक रूप से वित्तीय कार्यकलापों के कार्य-चालन परिणाम प्रदर्शित करते हुये प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनके क्रियाकलापों का आकलन कर सके। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के वार्षिक अन्तिमीकृत लेखे, उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य तथा अपने कारोबार को संचालित करने में कार्य कुशलता को दर्शाते हैं। लेखों को समय पर अन्तिम रूप न दिये जाने के अभाव में, सरकारी निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान मण्डल की संवीक्षा के अन्तर्गत नहीं आ पाते। परिणामतः, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हों तो वे समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, सभी तरह के विलम्ब से, व्यवस्था में हर समय धोखाधड़ी व सार्वजनिक धन के निःस्राव की सम्भावना बनी रहती है।

सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे उपक्रम अपने लेखे तैयार करें तथा विहित समय सीमा के अन्तर्गत लेखापरीक्षार्थ प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रस्तुत करें। सितंबर 2013 तक, तीन ऐसे उपक्रमों में से दो ने लेखे तैयार नहीं किए थे तथा उनके लेखे वर्ष 2003-04 व उसके बाद से बकाये थे। प्रोफार्मा लेखे तैयार करने के बकाये व सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति **परिशिष्ट-3.1** में दी गयी है।

लेखे को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से, वित्तीय अनियमितता के जोखिम का पता नहीं लगता, अतः लेखे को तैयार कर लेखापरीक्षा को शीघ्रतम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.3 दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि

लेखापरीक्षा ने मार्च 2013 तक ₹ 1.44 करोड़ की सरकारी राशि के दुर्विनियोग, गबन व चोरी आदि के चार प्रकरण पाए जिन पर अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विवरण तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट-3.2** में दिया गया है तथा इन मामलों की प्रकृति **परिशिष्ट-3.3** में दी गई है। लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण तथा प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के लम्बित मामलों की संख्या को **तालिका 3.2** में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.2
31 मार्च 2013 के अनुसार दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के मामलों की रूपरेखा

लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण			लम्बित मामलों की प्रकृति		
सीमा वर्षों में	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति/विशिष्टियाँ	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)
0 – 1	01	37.18	दुर्विनियोग/माल की हानि	04	143.78
1 – 2	02	105.53			
2-3	--	--	--	--	--
3-4	--	--			
4-5	01	1.07	**योग**	**04**	**143.78**
5 एवं अधिक	--	--	वर्ष के दौरान हानियों के अपलेखन के मामले	--	--
योग	**04**	**143.78**	**कुल लम्बित मामले**	**04**	**143.78**

इनमे से ₹ 143.78 लाख की चोरी, दुर्विनियोग/हानि के अन्तिम कार्रवाई हेतु अनिर्णित चार मामलों में से ₹ 1.07 लाख का एक अनिर्णित मामला शिक्षा विभाग के पास था जबकि ₹ 142.71 लाख की पर्याप्त राशि के तीन मामलों को वन विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना प्रतीक्षित था।

इस प्रकार एक प्रभावपूर्ण पद्धति को दुर्विनियोग, हानि व गबन के प्रकरणों के शीघ्रतम निस्तारण हेतु स्थापित करने और भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.4 लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अधीन बुकिंग

2012-13 के दौरान 39 मुख्य लेखा शीर्षों (सरकार के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए) के अन्तर्गत ₹ 858.18 करोड़ राजस्व लेखा में लघु शीर्ष 'अन्य व्यय' – जो कुल राजस्व व्यय, संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन अभिलिखित – के 6.15 *प्रतिशत* अंश बनता है – के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 38 मुख्य लेखा शीर्षों (सरकार के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए) के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 2,462.87 करोड़ राजस्व लेखा में लघु शीर्ष 'अन्य प्राप्तियाँ', जो कुल राजस्व प्राप्तियों – संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन अभिलिखित- के 15.64 *प्रतिशत* अंश बनता है, के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। तीन मुख्य लेखा शीर्षों में व्यय राशि प्रचुर मात्रा (₹ 119.90 करोड़) में 'अन्य व्यय' के अधीन बुक की गई थी तथा नौ मुख्य लेखा शीर्षों में प्राप्तियों की प्रचुर रकम (₹ 1,830.78 करोड़)

'अन्य प्राप्तियाँ' के अधीन बुक की गई थी। वित्तीय लेखाओं में मुख्य योजनाओं का अलग से आरेखण नहीं किया है, तथापि इन लेखाओं के विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर या निम्न में, अनुदानों के विवरणात्मक माँगों में तथा संबन्धित शीर्ष-वार विनियोजित लेखाओं में सरकार लेखाओं के भाग बनकर आरेखित है।

लघु शीर्ष '800'–अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अधीन भारी रकम का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में पारदर्शिता/शुद्ध चित्रण को प्रभावित करता है।

3.5 मुख्य शीर्ष 8009 एवं 2049 के अंर्तगत त्रुटिपूर्ण आँकड़ों की प्रविष्टि

राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के ब्याज से सम्बन्धित आँकड़े कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध नही कराये जा रहे हैं। अतः वित्त लेखे 2012-13 में इस मद में बजट से सम्बन्धित आँकड़ों (₹ 80 करोड़) को सम्मिलित किया जा रहा है। यह लेखा के परिशुद्धता को कम करता है तथा साथ ही सामान्य भविष्य निधि के कपटपूर्ण आहरण के जोखिम को बढ़ाता है।

3.6 निष्कर्ष

सरकार द्वारा सूत्रबद्ध विभिन्न नियम, कार्यविधियाँ तथा निदेशनों के अनुपालन के संबन्ध में परिकल्पना के अनुसार सरकारी विभागों के अन्दर आंतरिक नियंत्रण तंत्र कार्यरत नहीं है। विभागीय तौर पर प्रबन्धित सरकारी उपक्रमों द्वारा वार्षिक कच्चे लेखाओं के उपक्रम की मूल आवश्यकताओं के अनुपालन खामियों में तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा ए सी बिलों पर आहरित भारी रकम के असमायोजन में, वित्तीय प्रतिवेदन कार्य परिशुद्ध तथा विश्वासयोग्य नहीं हो सकता। विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को दिए गए ऋणों तथा अनुदानों के विरूद्ध प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब सूचित करता है कि सरकार के अनुश्रवण तंत्र का सशक्तीकरण आवश्यक है जैसे 599 की संख्या में ₹ 617.59 करोड़ की यू सी जो प्रस्तुतीकरण हेतु नियत थे-प्रधान महालेकार (लेखा व हकदारी) को, लेखाओं के पुन:समाधान तथा निधियों के उचित उपयोग पर निगरानी रखने हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

हानि/दुर्विनियोग व गबन के प्रकरणों में विभागीय जाँचों में दोषियों को दण्डित करने हेतु तेजी लानी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के ब्याज से सम्बन्धित वास्तविक आँकडे राज्य सरकार से प्राप्त होने के कारण बजट के आँकड़े वित्त लेखे में समाहित किये जा रहे है।

3.7 संस्तुतियाँ

सरकार सुनिश्चित करने हेतु विचार करे कि :

- अनुदानित संस्थाओं को विशेष प्रयोजन हेतु अवमुक्त अनुदानों के संबन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से प्रस्तुत हों।
- सभी गबन व दुर्विनियोजन प्रकरणों संबंधी विभागीय जाँच में गति लाएँ तथा इन प्रकरणों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रणों का सशक्तिकरण करें।
- लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अधीन मुख्य योजनाओं के प्राप्तियों तथा व्यय को सम्मिलित करने के वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में सुधार लाएँ।

देहरादून (**सौरभ नारायन**)

दिनांक **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली (**शशि कान्त शर्मा**)

दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

(संदर्भः उत्तराखण्ड का परिचय; पृष्ठ-1)

अ. सामान्य आँकड़े*:

क्रम संख्या	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी
2	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	101.17 लाख
3	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल) (अखिल भारतीय औसत = 29.80 *प्रतिशत*)		*18.00 प्रतिशत*
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 *प्रतिशत*)	*71.60 प्रतिशत*
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 *प्रतिशत*)	*79.63 प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 44 प्रति 1000 जीवित जन्म)		36
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 66.10)		अनुपलब्ध
8	गिनी गुणांक**		
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.276)	0.231
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय = 0.376)	0.395
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) 2012-13 चालू मूल्य पर		108,343
10	प्रति व्यक्ति जी एस डी पी सी ए जी आर (2003-04 से 2012-13)		*18.00 प्रतिशत*
11	जी एस डी पी सी ए जी आर (2003-04 से 2012-13)		*19.80 प्रतिशत*
12	जनसंख्या वृद्धि (2003-04 से 2012-13)		*16.03*

ब : वित्तीय आँकड़े

सी ए जी आर (2003-04 से 2012-13)			
विवरण		आँकड़े (*प्रतिशत* में)	
सी ए जी आर		2003-04 से 2011-12	2003-04 से 2012-13
क	राजस्व प्राप्तियों का	18.17	17.82
ख	राजस्व कर का	16.45	16.20
ग	करेत्तर राजस्व का	15.05	17.69
घ	कुल व्यय	15.15	15.06
ड़	पूँजी व्यय	20.16	23.42
च	सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय	16.42	14.39
छ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राजस्व व्यय	18.99	18.75
ज	वेतन	20.65	19.32
झ	पेंशन	18.96	19.11

*सामान्य आँकड़ों का स्रोतः आँकड़ों की पुस्तिका जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए है, योजना आयोग, भारत सरकार - 3 मई 2013 (website:http://planningcommission.gov.in)

** *गिनी गुणांक जनसंख्या में आय की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक है, शून्य के समीप असमानता कम है; एक के समीप असमानता अधिक है।*

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भः पृष्ठ-1)

भाग अः सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना

सरकारी लेखों की संरचनाः राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

भाग- I: समेकित निधिः राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये जुटाए गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि, एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।

भाग- II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि एक प्रकार का अग्रदाय है जो अति आवश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम देने के लिये विधायिका द्वारा प्राधिकृत होने तक राज्यपाल के स्वेच्छा पर रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग- III: लोक लेखा: कतिपय लेनदेनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का अंश नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते है और जिन्हें राज्य विधायिका द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-1.1-क्रमशः

भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	
विवरण	विन्यास
खण्ड 1	
विवरण संख्या-1	वित्तीय स्थिति का विवरण।
विवरण संख्या-2	प्राप्ति तथा संवितरण का विवरण।
विवरण संख्या-3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण।
विवरण संख्या-4	समेकित निधि से व्यय का विवरण। लेखे पर कार्य एवं प्रकृति टिप्पणी।
परिशिष्ट I	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश।
खण्ड 2 ***भाग–I***	
विवरण संख्या-5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण।
विवरण संख्या-6	उधारियाँ तथा अन्य दायित्वों का विवरण।
विवरण संख्या-7	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विवरण।
विवरण संख्या-8	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण संख्या-9	सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूति का विवरण।
विवरण संख्या-10	दत्तमत्त तथा प्रभारित व्यय का विवरण।
भाग–II	
विवरण संख्या-11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-13	लघु शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-14	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-15	उधारियों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-16	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-17	राजस्व लेखा को छोड़कर व्यय के लिए निधि के स्रोतों तथा उपयोगों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-19	नैमित्तिक निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण।
भाग–III	
परिशिष्ट	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय।
III	उपदान पर तुलनात्मक व्यय।
IV	सहायतित अनुदान (योजनावार व संस्थावार)।
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ।
VI	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय एवं राज्य अयोजनागत योजनायें)।
VII	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों का कार्यदायी अभिकरणों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
VIII	शेषों का सारांश।
IX	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम।
X	अपूर्ण निर्माण कार्य।
XI	वेतन व गैर-वेतन अंश को पृथक्-पृथक् दर्शाते हुए अनुरक्षण व्यय।

परिशिष्ट-1.2
भाग अ
(संदर्भः पृष्ठ- 1)
राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि

एकवर्गीय राजकोषीय समुच्चयों के लिए अनुमानों सहित चयनित राजकोषीय आँकड़ों के लिए तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएँ तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोषीय दायित्व अधिनियम में तथा अन्य विवरणों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित है. **(परिशिष्ट- 1.2 का भाग ब)**। वचनबद्धताएँ/अनुमान, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों के प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के गुणात्मक मूल्याँकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ), राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य सम्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्यों पर स रा घ उ के *प्रतिशत* के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स रा घ उ द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजकोषीय आँकड़ों हेतु उत्प्लावकता गुणांक यह निर्धारित करने के लिए आगणित किया जाता है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चलते हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय, स रा घ उ के अलावा दूसरे कारकों से भी प्रभावित हैं।

विगत पाँच वर्षों हेतु स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ

	2008-09	2009-10	2010-11♣	2011-12♥	2012-13♠
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	56,025	70,730	83,966	94,159	108,343
स रा घ उ की वृद्धि दर	*22.18*	*26.25*	*18.71*	*12.14*	*15.06*

स्रोतः निदेशक, अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड

♣ अनन्तिम आगणन ♥ त्वरित आगणन ♠ अग्रिम आगणन

राजकोषीय क्षमता के आगणन हेतु पद्धति

राज्य सरकार की राजकोषीय क्षमता का आगणन करने के लिए, तेरहवें वित्त आयोग में दी गयी निम्न पद्धति अपनाई गयी।

चरण 1: कुल व्यय- स रा घ उ और पूँ व्यय/वि व्यय/सा से व्यय- कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत की गणना करें।

चरण 2: कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात के राष्ट्रीय औसत पर आधारित, कुल व्यय की गणना करें जिससे किसी भी राज्य में कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात, राष्ट्रीय औसत से कम न हो, अर्थात, यदि

कुल व्यय/स रा घ उ = X

कुल व्यय=X*स रा घ उ .....(1)

जहाँ X, कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।

जहाँ कहीं भी राज्यों का कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किये गये थे। जहाँ कहीं भी यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, यह राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 3: वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय-कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत के आधार पर सम्बन्धित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय की गणना करें, जिससे कि किसी भी राज्य में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न हों, अर्थात्, यदि

वि व्यय/कु व्यय = Y

वि व्यय = Y* कु व्यय .....(2)

जहाँ Y, वि व्यय-कु व्यय अनुपात का राष्ट्रीय औसत है

(2) में (1) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

वि व्यय = Y*X* स रा घ उ .....(3)

जहाँ कहीं भी राज्यों का वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय-कु व्यय और पूँ व्यय-कु व्यय अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किया गया। जहाँ यह अनुपात औसत से कम था, इन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 4: समीकरण (3) के अनुसार आगणित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय के आधार पर, सम्बन्धित प्रति व्यक्ति व्यय की गणना की गयी, अर्थात्

प्र व्य वि व्यय = वि व्यय/ज.....(4)

जहाँ प्र व्य वि व्यय, प्रति व्यक्ति विकास व्यय है और ज जनसंख्या है।

(4) में (3) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेगें

प्र व्य वि व्यय = (Y*X* स रा घ उ)/ज .....(5)

समीकरण (5), समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय उपलब्ध कराता है। यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय, प्रति व्यक्ति व्यय के राष्ट्रीय औसत से कम है, तब राज्य के व्यय का न्यून स्तर राजकोषीय क्षमता में कमी के कारण है। यह, व्यय के वास्तविक स्तर का चित्रण करता है जबकि सभी राज्य सरकारें इन क्षेत्रों को राजकोषीय प्राथमिकता, राष्ट्रीय औसत के बराबर देती है।

राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियाँ और पद्धतियों का आकलन करने में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषा नीचे दी गयी है:

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (X) की उत्प्लावकता, अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में	प्राचल(X) की वृद्धि दर/प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण भंडार*ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्ति का *प्रतिशत*	प्राप्त ब्याज [(आदि शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतिम शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम का निवल – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियाँ **घटाया** समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय जिसमें मुख्य शीर्ष 2048- ऋण की परिहार्यता के न्यूनीकरण के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय शामिल नहीं है।

परिशिष्ट-1.2

भाग ब

(संदर्भः उत्तराखण्ड का विवरण पैरा 1.1; पृष्ठ-2)

राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

(तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ के अनुरुप मार्च 2011 में आंशिक संशोधित)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करते हुए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करके और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय संचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विशेष रूप से राज्य सरकार--

(क) 1 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी;

(ख) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत वर्ष 2011-12 व 2012-13 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 *प्रतिशत* व तत्पश्चात् वर्ष 2013-14 व 2014-15 में 3 *प्रतिशत* रखेगी।

(ग) 1 अप्रैल 2011 से मार्च 2015 तक के आगामी चार वर्षों में जी एस डी पी की तुलना में राजकोषीय दायित्व का अनुपात 41.10 *प्रतिशत*, 40.00 *प्रतिशत*, 38.50 *प्रतिशत* व 37.20 *प्रतिशत* से अधिक न होना सुनिश्चित करेगी;

(घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्रत्येक छः माही में समीक्षित किए जाएँगे ।

(च) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी; एवं

(छ) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले दस वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस *प्रतिशत* से अधिक न हो।

मध्यकालिक राजकोषीय नीति के द्वारा राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(₹ करोड़ में)

	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (बजटीय)	2012-13 (संशोधित)	2013-14 (परियोजित)	2014-15 (परियोजित)	2015-16 (परियोजित)
ए. राज्य का राजस्व लेखा :							
1. स्वयं का कर राजस्व	4,405.48	5615.56	5980.26	6050.26	7111.42	8249.25	9569.13
2. स्वयं का करेत्तर राजस्व	678.06	1136.07	1208.17	1517.43	1216.26	1181.56	1276.09
3. स्वयं का कर + करेत्तर राजस्व (1+2)	**5,083.54**	**6751.63**	**7188.43**	**7567.69**	**8327.68**	**9430.81**	**10845.21**
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में अंश	2,460.07	2866.10	3388.45	3272.88	3896.39	4363.96	4887.63
5. आयोजनागत अनुदान	2,629.36	3354.51	4831.67	5531.67	6107.07	6717.78	7389.55
6. आयोजनेत्तर अनुदान	1,435.20	719.18	750.40	839.24	624.58	485.00	485.00
7. कुल केन्द्रीय अन्तरण (4 से 6)	**6,524.63**	**6939.79**	**8970.52**	**9643.79**	**10628.04**	**11566.73**	**12762.19**
8. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+7)	**11,608.17**	**13691.42**	**16158.95**	**17211.48**	**18955.72**	**20997.54**	**23607.40**
9. आयोजनागत व्यय	4,367.29	4625.16	7048.96	8184.23	8710.38	9581.42	10539.56
10. आयोजनेत्तर व्यय	10,348.56	12838.36	14882.81	15016.75	16619.46	18447.60	20476.84
11. वेतन व्यय	4,966.14	5511.88	6513.18	6505.22	7404.18	8144.60	8959.06
12. पेंशन	1,141.72	1135.10	1439.80	1439.80	1989.55	2208.40	2451.32
13. ब्याज भुगतान	1,479.58	1769.21	2025.00	2119.08	2540.85	2906.83	3320.94
14. उपदान-सामान्य							
15. उपदान-विद्युत							
16. कुल राजस्व व्यय (9+10)	**11,621.08**	**12975.32**	**15717.11**	**15985.32**	**18054.20**	**19949.89**	**22543.38**
17. वेतन+ब्याज+पेंशन (11+12+13)	7587.44	8416.19	9977.98	10064.10	11934.58	13259.83	14731.33
18. राजस्व प्राप्ति *प्रतिशत* के रूप में (17/8)	*65.36*	*61.47*	*61.75*	*58.47*	*62.96*	*63.15*	*62.40*
19. राजस्व अधिशेष/घाटा (8-16)	**- 12.91**	**716.10**	**441.84**	**1226.16**	**901.52**	**1047.65**	**1064.02**
बी. समेकित राजस्व लेखा:							
1. विद्युत के क्षेत्र में हानि/वास्तविक उपदान अन्तरण के निवल लाभ	-						
2. वर्ष के दौरान विद्युत उपयोगिता लेखा में बकायेदारों की वृद्धि (वृद्धि (-))	-						

3. आयव्ययक ऋण और पी एस यूज और एस पी यूज द्वारा लिये गये आयव्ययक ऋण पर ब्याज भुगतान	-						
4. योग (1 से 3)							
समेकित राजस्व अधिशेष/घाटा	**- 12.91**	**716.10**	**441.84**	**1226.16**	**901.52**	**1047.65**	**1064.02**
सी. समेकित ऋण:							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व	19806.99	21752.77	25028.11	24939.58	28498.94	32565.41	37166.65
2. कुल अनिस्तारित प्रत्याभूतियाँ	2042.28	1739.45	1739.45	1570.15	1570.15	1570.15	1570.15
ए) बजटकृत तथा एस पी वी ऋण हेतु प्रत्याभूतियाँ							
डी. पूँजीगत लेखा:							
1. पूँजीगत परिव्यय	1854.85	2317.31	3653.48	4547.27	4874.19	5264.13	5685.26
2. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	59.68	246.84	264.05	371.26	248.66	50.00	80.00
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	84.87	490.57	118.10	368.10	684.59	200.00	100.00
4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	2382.29	2335.52	3357.00	3357.00	3536.74	4066.47	4601.23
ई. सकल राजकोषीय घाटा (जी एफ डी):	**1842.57**	**1357.48**	**3357.59**	**3324.27**	**3536.74**	**4066.47**	**4601.23**
चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	75475.73	93161.72	107548.25	107548.25	121099.3	136357.80	153538.90
एफ. राजकोषीय घाटा :							
वास्तविक/मान ली गई नगण्य वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	*13.67*	*12.35*	*15.44*	*15.44*	*12.60*	*12.60*	*12.60*

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: प्रस्तर 1.3, 1.9.2 एवं 1.10 *(ii); पृष्ठ- (10, 31 & 35)*

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**8,635**	**9,486**	**11,608**	**13,691**	**15,747**
(i) कर राजस्व	**3,045(*35*)**	**3,559(*38*)**	**4,405(*38*)**	**5,616(41)**	**6,414(41)**
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,911(63)	2,247(63)	2,940(67)	3,644(65)	4,289(67)
राज्य आबकारी	528(17)	705(20)	756(17)	844(15)	1,118(17)
वाहनों पर कर	167(5)	184(5)	227(5)	335(6)	304(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	357(12)	399(11)	440(10)	524(9)	648(10)
भू-राजस्व	18(1)	9(0.25)	18(0.41)	10(--)	11(--)
माल एवं यात्रियों पर कर	6(-)	--	--	--	--
अन्य कर	58(2)	15(0.42)	24(0.54)	259(5)	44(1)
(ii) करेत्तर राजस्व	**699(8)**	**632 (7)**	**678(6)**	**1,136(8)**	**1,603(10)**
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	**1,507(18)**	**1,550(16)**	**2,460(21)**	**2,866(21)**	**3,273(21)**
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**3,384(39)**	**3,745(39)**	**4,065(35)**	**4,073(30)**	**4,457(28)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**54**	**65**	**85**	**91**	**428**
4. कुल राजस्व एवं ऋणेत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**8,689**	**9,551**	**11,693**	**13,782**	**16,175**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**1,544**	**1,682**	**2,427**	**2,336**	**2,968**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,399(91)	1,582(94)	2,384(98)	2,289(98)	2,933(99)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	127(8)	69(4)	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	18(1)	319(2)	43(2)	47(2)	35(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ(4+5)	**10,233**	**11,233**	**14,120**	**16,118**	**19,143**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**2**	**37**	**582**	**126**	**32**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**13,658**	**14,226**	**18,829**	**19,668**	**21,925**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**23,891**	**25,459**	**33,531**	**35,912**	**41,100**
भाग ब. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**8,394**	**10,657**	**11,621**	**12,975**	**13,960**
आयोजनागत	2,174(26)	2,299(22)	2,472(21)	2,321(18)	2,427(17)
आयोजनेत्तर	6,220(74)	8,358(78)	9,149(79)	10,654(82)	11,533(83)

सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतानों सहित)	3,104(37)	3,694(35)	4,180(36)	4,475(35)	5,372(38)
सामाजिक सेवायें	3,392(41)	4,980(47)	5,169(44)	6,019(46)	6,096(44)
आर्थिक सेवायें	1,623(19)	1,658(16)	1,864(16)	2,102(16)	1,995(14)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	275(3)	325(3)	408(4)	379(3)	497(4)
11. पूँजीगत व्यय	**2,016**	**1,647**	**1,855**	**2,317**	**3,542**
आयोजनागत	1,902(94)	995(60)	1,859(100)	2,071(89)	2,972(84)
आयोजनेत्तर	114(6)	651(40)	(-) 4	246(11)	570(16)
सामान्य सेवायें	174(9)	109(7)	105(5)	77(3)	129(4)
सामाजिक सेवायें	281(14)	109(7)	235(13)	369(16)	715(20)
आर्थिक सेवायें	1,561(77)	1,429(87)	1,515(82)	1,871(81)	2,698(76)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**122**	**30**	**60**	**247**	**273**
13. योग *(10+11+12)*	**10,532**	**12,334**	**13,536**	**15,539**	**17,775**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**355**	**473**	**519**	**1,016**	**1,472**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	318	437	448	667	1,412
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	45	323	31
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	37	36	26	26	29
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग		**-**	**515**	**(-) 400**	--
16. समेकित निधि से कुल संवितरण *(13+14+15)*	**10,887**	**12,807**	**14,570**	**16,155**	**19,247**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**32**	**71**	**537**	**69**	**32**
18. लोक लेखा संवितरण	**13,477**	**12,322**	**17,733**	**19,832**	**20,961**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**24,396**	**25,200**	**32,840**	**36,056**	**40,240**
भाग स.घाटा आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(+) 241**	**(-) 1,171**	**(-) 13**	**(+)716**	**(+)1,787**
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	**1,843**	**2,783**	**1,843**	**1,757**	**1,600**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-) 655**	**(-) 1,445**	**(-) 363**	**(+) 12**	**(+)489**
भाग द. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**1,188**	**1,338**	**1,480**	**1,769**	**2,089**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**275**	**324**	**408**	**379**	**497**
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	**83**	**107/09**	**93**	**73**	**2**
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**3**	**2**	**1**	**0.88**	**0.01**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)@	**56,025**	**70,730**	**83,966**	**94,159**	**1,08,343**
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)	**16,276**	**18,748**	**21,598**	**23,609**	**25,540**
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	**1,802**	**1,511**	**1,511**	**1,739**	**1,570**
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	**1,677**	**1,386**	**2,122**	**2,722**	**2,722**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	**382**	**140**	**89**	**63**	**192**

32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	**539**	**2,081**	**63**	**121.80**	**95**
भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक					
I संसाधन का जुटाव	**0.05**	**0.05**	**0.05**	**0.06**	**0.06**
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
स्वयं का करेत्तर राजस्व /स रा घ उ	**0.09**	**0.07**	**0.08**	**0.07**	**0.07**
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ					
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/स रा घ उ	**0.19**	**0.17**	**0.16**	**0.17**	**0.16**
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियाँ	**1.22**	**1.30**	**1.17**	**1.13**	**1.13**
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	**0.80**	**0.86**	**0.86**	**0.83**	**0.79**
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	**0.35**	**0.41**	**0.40**	**0.41**	**0.4**
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	**0.30**	**0.25**	**0.25**	**0.26**	**0.26**
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**0.19**	**0.13**	**0.14**	**0.15**	**0.20**
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**0.17**	**0.12**	**0.13**	**0.14**	**0.19**
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स रा घ उ	**(+)0.004**	**(-) 0.017**	*	**(+)0.008**	**0.016**
राजकोषीय घाटा/स रा घ उ	**-0.033**	**-0.039**	**- 0.022**	**-0.018**	**-0.015**
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) /स रा घ उ	**-0.012**	**-0.020**	**-0.004**	*	**0.005**
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	**(+)0.131**	**(-)0.420**	**(-)0.007**	**(+)0.408**	**(-)1.117**
प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	**(-)0.016**	**(-)0.036**	**(-)0.018**	**(-)0.011**	**(-)0.002**
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	**0.29**	**0.27**	**0.26**	**0.25**	**0.24**
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	**1.88**	**1.98**	**1.86**	**1.72**	**1.62**
मात्रात्मक विस्तार के सापेक्ष प्राथमिक घाटा	**(+) 1,694**	**(+)2,083**	**(+)1,592**	**(+)1,811**	**(+)2,164**
ऋण पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	**0.95**	**0.95**	**0.83**	**0.94**	**1.00**
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	**0.23**	**0.07**	**0.21**	**0.05**	**0.19**
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	**(+) 357**	**(-) 1,384**	**(-) 46**	**(-)250**	**(+)775**
वित्तीय परिसम्पतियाँ/दायित्व	**0.76**	**0.82**	**0.77**	**0.82**	**0.90**

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित स रा घ उ के आँकड़े ग्रहण किये गये हैं।

* संगणन योग्य नहीं।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.1, एवं 1.9.2; पृष्ठ -2 एवं 31)

भाग अ

वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ					संवितरण					
विविध मद	2011-12				विविध मद	2011-12	2012-13			
							आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
खण्ड-अ राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियाँ		**13,691.24**		**15,747.22**	**I-राजस्व व्यय**	**12,975.19**	**11,533.36**	**2,426.86**	**13,960.22**	**13,960.22**
(i) कर राजस्व	5,615.62		6,414.24		सामान्य सेवायें	**4,475.11**	**5,368.13**	**4.10**	**5,372.23**	
(ii) करेत्तर राजस्व	1,136.13		1,602.88		सामाजिक सेवायें	**6,019.65**	**4,146.27**	**1,949.57**	**6,095.84**	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	2,866.04		3,272.88		शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3,462.86	3,121.04	618.74	3,739.78	
(iv) आयोजनेत्तर अनुदान	762.09		868.64		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	698.05	486.58	318.89	805.47	
(v) राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,839.85		3,040.12		जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	435.35	146.10	362.53	508.63	
(vi) केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	471.51		548.46		सूचना एवं प्रसारण	36.37	40.34	1.15	41.49	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	177.37	80.89	124.39	205.28	
		--			श्रम तथा श्रमिक कल्याण	54.00	52.44	18.18	70.62	
					समाज कल्याण एवं पोषण	1,136.36	212.92	467.78	680.70	
					अन्य	19.29	5.96	37.91	43.87	
					आर्थिक सेवायें	**2,101.63**	**1522.10**	**473.19**	**1,995.29**	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	1,191.58	811.30	246.76	1,058.06	
					ग्राम्य विकास	335.29	155.54	129.42	284.96	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	288.85	306.63	2.25	308.88	
					ऊर्जा	9.98	3.47	10.43	13.90	
					उद्योग एवं खनिज	42.86	26.81	16.62	43.43	
					परिवहन	175.30	190.64	19.24	209.88	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	13.62	0.85	8.30	9.15	
					सामान्य आर्थिक सेवायें	44.15	26.86	40.17	67.03	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	**378.80**	**496.86**	**--**	**496.86**	
योग		**13,691.24**		**15,747.22**	**योग**	**12,975.19**				**13,960.22**
II-राजस्व घाटा खण्ड-ब को अन्तरित		--		--	**II-** राजस्व अधिशेष खण्ड-ब को अन्तरित	**716.05**				**1787.00**

योग		**13,691.24**		**15,747.22**	**योग**	**13,691.24**				**15,747.22**
III-स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष		**1,229.40**		**1,085.18**	**III- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट**					
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	**IV- पूँजीगत परिव्यय**	**2,316.94**	**570.41**	**2,971.68**	**3,542.09**	**3,542.09**
					सामान्य सेवायें	**77.47**	**5.52**	**123.85**	**129.37**	
					सामाजिक सेवायें	**368.58**	**6.25**	**708.57**	**714.82**	
					शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	131.47	6.25	240.57	246.82	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	93.66	--	139.31	139.31	
					जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	119.62	--	268.11	268.11	
					सूचना एवं प्रसारण	-	--	--	--	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11.93	--	37.35	37.35	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	4.16	--	5.98	5.98	
					अन्य	7.74	--	17.25	17.25	
					आर्थिक सेवायें	**1,870.89**	**558.64**	**2,139.26**	**2,697.90**	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	259.64	558.65	(-)16.68	541.97	
					ग्राम्य विकास	226.03	--	246.73	246.73	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	455.82	(-) 0.01	386.86	386.85	
					ऊर्जा	41.78	--	516.12	516.12	
					उद्योग एवं खनिज	0.62	--	16.86	16.86	
					परिवहन	857.30	--	969.14	969.14	
					सामान्य आर्थिक सेवायें	29.70	--	20.23	20.23	
					योग	**2,316.94**				**3,542.09**
V-*ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ*		**90.65**		**428.44**	V- *संवितरित ऋण एवं अग्रिम*	**246.83**				**272.57**
विद्युत परियोजनाओं से	84.75		422.16		*विद्युत परियोजनाओं के लिए*	129.09	--	84.35	84.35	
सरकारी कर्मचारियों से	5.36		4.49		*सरकारी कर्मचारियों को*	1.17	1.03	--	1.03	
अन्य से	0.54		1.79		*अन्य को*	116.57	3.52	183.67	187.19	
VI- राजस्व अधिशेष नीचे लाया गया	--	**716.05**		**1787.00**	**VI- राजस्व घाटा नीचे लाया गया**	-				
VII- लोक ऋण प्राप्तियाँ		**2,335.52**		**2,967.43**	**VII- लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**1,015.78**				**1,472.21**
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	2,289.12		2,932.72		अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	666.62			1,412.90	
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-		--		अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	322.90			30.69	

केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	46.40		34.71		केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	26.26			28.62	
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोग	–			--	**VIII-** आकस्मिकता निधि को विनियोग	**(-)400.00**				--
IX- आकस्मिकता निधि में अन्तरित राशि		**126.13**		**32.22**	**IX-** आकस्मिकता निधि से व्यय	**69.07**				**32.07**
X- लोक लेखा प्राप्तियाँ		**19,668.05**		**21,925.45**	**X- लोक लेखा संवितरण**	**19,832.00**				**20,961.24**
लघु बचत एवं भविष्य निधि	1,272.45		1,159.18		लघु बचत एवं भविष्य निधि	646.40			888.06	
आरक्षित निधियाँ	648.94		279.72		आरक्षित निधियाँ	592.74			183.09	
जमा एवं अग्रिम	2,330.92		2,359.47		जमा एवं अग्रिम	2,298.02			2,140.68	
उचंत एवं विविध	12,366.08		15,010.04		उचंत एवं विविध	12,779.05			14,531.10	
प्रेषण	3,049.66		3,117.04		प्रेषण	3,515.79			3,218.31	
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवर ड्राफ्ट					**XI-अन्त में रोकड़ शेष**	**1,085.18**				**1,945.54**
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	(-) 5.38			--	
					स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	(-) 3.02			(-) 3.02	
					रिजर्व बैंक में जमा	116.01			(-)5.21	
					रोकड़ शेष का निवेश व नैमित्तिक निधि के निवेश	977.57			1,953.77	
योग	**24,165.80**			**28,225.72**	**योग**	**24,165.80**				**28,225.72**

परिशिष्ट-1.4 (क्रमशः)

भाग ब

(संदर्भः प्रस्तर 1.9.1 ; पृष्ठ-31)

31 मार्च 2013 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2012 को	दायित्व	31.03.2013 को
16,848.09	**आन्तरिक ऋण**	**18,337.22**
83,94.18	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	9,194.32
0.14	ब्याज वहन न करने वाले बाजार ऋण	0.13
1.50	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50
8421.58	अन्य संस्थाओं से ऋण	9,141.27
30.69	अर्थोपाय अग्रिम	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	--
455.46	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**	**461.54**
0.53	1984-85 से पहले के ऋण	0.53
7.95	आयोजनेत्तर ऋण	6.65
420.82	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	430.19
0.04	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.04
26.12	केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	24.13
102.70	**आकस्मिकता निधि**	**102.85**
4,449.22	**लघु बचत, भविष्य निधि आदि**	**4,720.34**
1,652.70	**जमा**	**1,871.49**
1,131.46	**आरक्षित निधियाँ**	**1,228.09**
-	**प्रेषण शेष**	**--**
24,639.63	**योग**	**26,721.53**

परिशिष्ट-1.4 भाग ब (क्रमशः)

31.03.2012 को	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2013 को
15,839.88	**अचल परिसमपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**	**19,381.97**
1,338.47	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1,857.55
14,501.41	अन्य पूँजीगत परिव्यय	17,524.42
874.08	**ऋण एवं अग्रिम**	**718.21**
414.67	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	76.86
462.38	अन्य विकास ऋण	629.70
(-) 2.97	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	11.65
115.00	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	**115.00**
1,340.47	**प्रेषण**	**1,441.73**
838.34	**उचंत एवं विविध शेष**	**359.41**
1,085.19	**रोकड़**	**1,945.54**
(-)5.38	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	
116.01	रिजर्व बैंक में जमा	(-)5.21
(-) 2.15	विभागीय रोकड़ शेष सहित	(-)2.15
(-)0.86	स्थायी अग्रिम	(-)0.87
977.57	रोकड़ शेष निवेश	1,953.77
4,546.67	**सरकारी लेखों में घाटा**	**2,759.67**
716.05	(i) चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटायें	1,787.00
-	(ii) विविध घाटा	--
5,262.72	वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	4,546.67
24,639.63	**योग**	**26,721.53**

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्वोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़ना होगा। **परिशिष्ट 1.4** में यथादर्शित सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर होने की स्थिति को इंगित करता है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा भण्डार के आँकड़ो में भिन्नता इत्यादि जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं। उचंत तथा विविध अवशेषों में, जारी परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन आदि सम्मिलित हैं। " रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखों में प्रदर्शित एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए आँकड़ों के मध्य ₹ 11.27 करोड़ (डेबिट) का अन्तर था जिसका मिलान किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भः प्रस्तर 1.2.2; पृष्ठ-9)

2012-13 के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बजट से बाहरी अन्तरित निधियों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	कार्यक्रम/योजना	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राशि
1	राष्ट्रीय एस जे ई संस्थाओं के निधिपन हेतु योजना	एन आई वी एचः पंजीकृत समितियाँ [सरकारी, स्वायत्त निकायों (ए बी)]	14.20
2	आजीविका स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार एस जी एस वाई/एन आर एल एम	डी आर डी एः पंजीकृत समितियाँ (सरकारी, ए बी.)	15.08
3	प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना	राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, पंजीकृत (एन जी ओ)	5.55
4	वनीकरण एवं वन प्रबन्ध	उत्तराखण्ड राज्य वन विकास एजेन्सी, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी, ए बी)	6.25
5	स्वायत्त संस्थायें एवं पेशेवर निकाय	आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान परीक्षण विज्ञान (ए आर आई ई एस), पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 14.83 करोड) और वाडिया संस्थान हिमालयन पुरातत्व (₹ 5.14 करोड़)	19.97
6	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	परियोजना प्रबंधन ईकाई स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड मक्खावाला, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी, स्वायत्त निकाय)	25.42
7	डी आर डी ए प्रशासन	विभिन्न जिलों के डी आर डी ए, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	8.13
8	वन एवं वन्य जीवन संस्थाओं को सहायता अनुदान	वन अनुसंधान संस्थान (भारतीय वनीकरण अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद), पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹109.76) और डब्लू आई आई (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹12.21 करोड़)	121.97
9	ग्रिड इन्ट्रेक्टिव रिन्यूवल पॉवर एम एन आर ई	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, राज्य सरकार पी एस यू	6.21
10	स्वास्थ्य हेतु जनशक्ति	महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून, उत्तराखण्ड राज्य सरकार के संस्थान	6.76
11	जल विद्युत परियोजनायें	जल विद्युत राजकीय संस्थान, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	4.74
12	एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम (आई डब्लयू एम पी)	डी आर डी ए उत्तरकाशी समितियाँ प्रकारः पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 12.79 करोड) और वाटर शेड पी एस यू (₹ 4.73 करोड़)	17.52
13	महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	विभिन्न जिलों की पंजीकृत समितियों के डी आर डी ए (सरकारी स्वायत्त निकाय)	268.27
14	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम - III	उत्तराख्ण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समितियाँ, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	11.74
15	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	लघु किसानों कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी), पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	16.25
16	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	एस डब्लू एस एम उत्तराखण्ड देहरादून पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	74.28
17	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति, पंजीकृत	113.38

	(एन आर एच एम और जे आई आई टी) केन्द्र प्रायोजित	समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 110.34 करोड़) और एस पी ओ उत्तराखण्ड, देहरादून (राज्य सरकार) पी एस यू (₹ 3.04 करोड़)	
18	ऑफ ग्रिड डी आर पी एस	उत्तराखण्ड ऊर्जा नवीनीकरण विकास समिति, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 6.46 करोड़), रिलायन्स खाद्य प्रसंस्करण कम्पनी, निजी क्षेत्र कम्पनी (₹ 0.02 करोड़), मैसर्स गौतम पॉलिमर्स। निजी क्षेत्र कम्पनी (₹ 2.76 करोड़), उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राज्य सरकार पी एस यू (₹ 0.01 करोड़), सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, राज्य सरकार की सस्थायें (₹ 0.12 करोड़) और आई आई टी रूड़की, उत्तराखण्ड पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 1.13 करोड़)	10.50
19	पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पी वाई के के ए)	राज्य युवा कल्याण परिषद उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	4.67
20	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)	उत्तराखण्ड ग्राम सड़क विकास समिति देहरादून, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	151.24
21	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान, ऋषिकेश पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	16.50
22	प्रोजेक्ट/इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलपमेन्ट फॉर डेस्टिनेशन्स एण्ड सर्विसस	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, स्टेटयूटरी बॉडीज	11.71
23	आर एण्ड डी इन न्यू एण्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलोजीज	आई आई टी रूड़की (₹ 8 करोड़) और यूनीवर्सिटी आफ पेट्रोलियम और एनर्जी स्टेडीज (स्टेटयूरी बॉडीज) (₹ 5.35 करोड़)	13.35
24	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद, पंजीकृत संस्थायें (सरकारी स्वायत्त निकाय)	96.64
25	संरक्षण और विकास के लिये अनुसंधान एवं विकास	जी बी पंत संस्थान हिमालयन, पर्यावरण एवं विकास पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 6.49 करोड़), वन अनुसंधान संस्थान, आई सी एफ आर ई, केन्द्र सरकार (₹ 0.13 करोड़), जी बी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, स्टेटयूटरी बॉडीज (₹ 0.01 करोड़)	6.63
26	अनुसंधान एवं विकास सहायक एस ई आर सी	डी ए वी (पी जी) महाविद्यालय, देहरादून, राज्य सरकार संस्थाये (₹ 0.07 करोड़), गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, पंजीकृत संस्थायें (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 0.55 करोड़), आई आई टी रूड़की, रूड़की, उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 3.10 करोड़), आपदा प्रबन्धन केन्द्र, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 0.44 करोड़), इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजूकेशन, उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 0.10 करोड़) और कुमाऊँ विश्वविद्यालय, स्टेटयूटूरी बॉडीज (₹ 0.41 करोड़)	4.67
27	अनुसंधान एवं विकास जल स्रोत	राष्ट्रीय विद्युत जल संस्थान, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 10.50 करोड़), आई आई टी रूड़की (₹ 0.08 करोड़) और ₹ 0.02 करोड़ एन जी ओ को	10.60
28	ग्रामीण आवास (आई ए वाई)	जिला ग्रामीण विकास समिति, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	40.81
29	सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, सरकारी समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	180.45

30	नए आई आई एम की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	9.13
31	नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना (एन आई टी एस) चौधरी घनी खान संस्थान को शामिल करते हुए डी एच ई	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	9.50
32	कौशल विकास	राज्य परियोजना क्रियान्वयन ईकाई समिति, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	2.08
33	भारतीय तकनीकी संस्थान को सहायता	आई आई टी रूड़की, उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	146.20
34	राज्य सहायता विस्तृतीकरण योजना को राज्य के विस्तृतीकरण सुधार के लिये	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी), पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	4.63
35	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन यापन अभियान (एन यू एल एम)	राज्य ग्रामीण विकास समिति उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	6.26
36	अन्य	विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियां	106.71
योग			**1,568.00**

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भः प्रस्तर 1.8.3; पृष्ठ-28)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	शासकीय पूँजी का मध्यमान	ह्रासित लागत पर ब्लॉक परिसम्पतियाँ	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया मूल्य ह्रास	व्यापार	निवल लाभ/हानि	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल (8+9)	पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रूड़की	2009-10	188.81	90.43	6.61	608.22	(-) 0.79	27.76	26.97	31.62
2(अ)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2002-03	-	58.25	6.64	19,644.70	(-) 1,873.25	-	(-) 1,873.25	-
2(ब)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	-	9.97	1.00	8,357.23	(-) 1,797.44	-	(-) 1,797.44	-

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.1 ; पृष्ठ - 44)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ 1 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व-दत्तमत					
1.	01	विधानमण्डल	19.06	2.09	10.96
2.	04	न्याय प्रशासन	1,35.33	50.90	37.61
3.	05	निर्वाचन	24.01	4.57	19.03
4.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4,33.40	64.40	14.85
5.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	26,42.36	5,49.18	20.78
6.	08	आबकारी	9.44	1.02	10.80
7.	10	पुलिस एवं कारागार	8,48.30	32.17	3.79
8.	11	शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	41,97.59	5,67.59	13.52
9.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,00.12	1,33.41	14.82
10.	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	6,22.89	1,53.22	24.60
11.	14	सूचना	43.14	1.84	4.27
12.	15	कल्याण	7,08.88	1,91.96	27.08
13.	16	श्रम एवं रोजगार	1,12.98	36.45	32.26
14.	17	कृषि कार्य एवं शोध	4,16.26	1,31.83	31.67
15.	18	सहकारिता	38.32	6.03	15.74
16.	19	ग्राम्य विकास	3,89.52	1,33.00	34.14
17.	20	सिंचाई व बाढ़	3,46.89	31.45	9.07
18.	22	लोक निर्माण	5,36.79	56.85	10.59
19.	23	उद्योग	71.39	11.32	15.86
20.	24	परिवहन	32.90	5.90	17.93
21.	25	खाद्य	3,83.21	2,30.83	60.24
22.	26	पर्यटन	72.75	30.05	41.31
23.	27	वन	3,72.90	27.10	7.27
24.	28	पशुपालन	1,33.32	9.04	6.78
25.	29	उद्यान विकास	1,08.91	7.19	6.60
26.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	5,07.17	1,14.39	22.55
27.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,53.54	36.68	23.89
योग			**1,42,61.37**	**26,20.46**	**18.37**
राजस्व-भारित					
1.	04	न्याय प्रशासन	*28.47*	*5.87*	*20.62*
2.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	*22,81.08*	*41.44*	*1.82*
3.	09	लोक सेवा आयोग	*9.59*	*1.93*	*20.13*
4.	22	लोक निर्माण	*3.88*	*1.02*	*26.29*
योग			***23,23.02***	***50.26***	***2.16***

पूँजीगत-दत्तमत					
1.	01	विधान मण्डल	24.60	22.00	89.43
2.	04	न्याय प्रशासन	21.00	3.76	17.90
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	51.04	9.12	17.87
4.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	70.52	20.60	29.21
5.	10	पुलिस एवं कारागार	76.18	43.76	57.44
6.	11	शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	3,59.49	1,22.03	33.95
7.	12	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,65.83	2,30.97	63.14
8.	13	जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास	5,59.50	3,07.99	55.05
9.	15	कल्याण	26.36	3.54	13.43
10.	19	ग्राम्य विकास	3,12.36	1,32.55	42.44
11.	20	सिंचाई व बाढ़	6,94.28	2,56.27	36.91
12.	21	ऊर्जा	9,51.12	3,68.40	38.73
13.	23	उद्योग	40.55	23.69	58.42
14.	24	परिवहन	1,65.20	43.95	26.60
15.	26	पर्यटन	74.34	55.32	74.41
16.	27	वन	57.76	16.32	28.25
17.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	3,61.60	2,03.71	56.34
18.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	94.78	54.28	57.27
योग			**43,06.51**	**19,18.26**	**44.54**
पूँजीगत-भारित					
1.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	22,97.13	8,09.76	35.25
2.	09	लोक सेवा आयोग	10.00	1.46	14.60
योग			**23,07.13**	**8,11.22**	**35.16**
महा योग			**2,31,98.03**	**54,00.20**	**23.28**

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.3 ; पृष्ठ -46)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ 1 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	व्ययाधिक्य	व्ययाधिक्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पूँजीगत(दत्तमत)						
1.	14	सूचना	1.00	1.38	0.38	38.00
2.	17	कृषि कार्य एवं शोध	1,78.30	1,91.57	13.27	7.44
3.	22	लोक निर्माण	9,13.20	9,19.55	6.35	0.70
4.	25	खाद्य	32.00	18,42.59	18,10.59	5658.09
5.	29	उद्यान विकास	0.00	4.50	4.50	100.00
योग			**11,24.50**	**29,59.59**	**18,35.09**	**163.19**

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7 ; पृष्ठ -47)

प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क - राजस्व(दत्तमत)					
1.	01 विधानमण्डल	18.84	16.97	1.87	0.22
2.	04 न्याय प्रशासन	1,29.17	84.43	44.74	6.16
3.	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4,21.16	3,69.00	52.16	12.24
4.	07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	26,29.00	20,93.18	5,35.82	13.36
5.	08 आबकारी	9.13	8.42	0.71	0.31
6.	11 शिक्षा,क्रीड़ा,युवा कल्याण एवं संस्कृति	39,85.03	36,30.00	3,55.03	2,12.56
7.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8,64.80	7,66.71	98.09	35.32
8.	15 कल्याण	6,39.20	5,16.92	1,22.28	69.68
9.	16 श्रम एवं राजगार	81.72	76.53	5.19	31.27
10.	17 कृषि कार्य एवं शोध	396.14	2,84.43	1,11.71	20.12
11.	18 सहकारिता	37.01	32.29	4.72	1.31
12.	19 ग्रामीण विकास	3,78.19	2,56.52	1,21.67	11.32
13.	20 सिंचाई एवं बाढ़	3,46.49	3,15.43	31.06	0.40
14.	22 लोक निर्माण	4,88.24	4,79.95	8.29	48.55
15.	23 उद्योग	65.52	60.07	5.45	5.87
16.	24 यातायात	32.52	27.00	5.52	0.38
17.	25 खाद्य	3,82.99	1,52.38	2,30.61	0.22
18.	26 पर्यटन	51.13	42.70	8.43	21.61
19.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	4,75.47	3,92.79	82.68	31.71
20.	31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	1,37.49	1,16.85	20.64	16.04
कुल राजस्व (दत्तमत)		**1,15,69.24**	**97,22.57**	**18,46.67**	**5,38.65**
ख - राजस्व (भारित)					
1.	04 न्याय प्रशासन	*23.95*	*22.60*	*1.35*	*4.52*
2.	09 लोक सेवा आयोग	*9.33*	*7.66*	*1.67*	*0.26*
3.	22 लोक निर्माण	*3.15*	*2.86*	*0.29*	*0.73*
कुल राजस्व (भारित)		***36.43***	***33.12***	***3.31***	***5.51***
ग- पूँजीगत (दत्तमत)					
1.	01 विधानमण्डल	22.60	2.60	20.00	2.00
2.	04 न्याय प्रशासन	20.00	17.24	2.76	1.00

3.	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	55.44	49.92	5.52	15.08
4.	10 पुलिस और कारागार	41.00	32.42	8.58	35.18
5.	11 शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2,52.18	2,37.46	14.72	1,07.32
6.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,88.38	1,34.86	53.52	1,77.45
7.	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	4,92.50	2,51.51	2,40.99	67.00
8.	19 ग्रामीण विकास	2,92.36	1,79.81	1,12.55	20.00
9.	20 सिंचाई एवं बाढ़	5,98.23	4,38.01	1,60.22	96.05
10.	23 उद्योग	35.55	16.86	18.69	5.00
11.	26 पर्यटन	52.45	19.03	33.42	21.89
12.	27 वन	52.18	41.43	10.75	5.58
13.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	3,19.04	1,57.89	1,61.15	42.56
14.	31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	92.36	40.50	51.86	2.42
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		**25,14.27**	**16,19.54**	**8,94.73**	**5,98.53**
महा योग		**1,41,19.94**	**1,13,75.23**	**27,44.71**	**11,42.69**

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ-47)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1.	17	कृषि कार्य एवं शोध (पूँजीगत-दत्तमत)	26.47	1,51.83	1,78.30	1,91.58	13.28
2.	22	लोक निर्माण (पूँजीगत-दत्तमत)	6,97.00	2,16.20	9,13.20	9,19.55	6.35
3.	25	खाद्य (पूँजीगत-दत्तमत)	7.00	25.00	32.00	18,42.59	18,10.59
योग			**7,30.47**	**3,93.03**	**11,23.50**	**29,53.71**	**18,30.22**

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ-48)

₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी)/आधिक्य में परिणत निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ लाख में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोग	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
1.	02	राज्यपाल	2012-03-090-03	(-)5.30	(-)29.11
2.			2012-03-103-03	(+)0.70	(-)17.01
3.	03	मंत्री परिषद	2013-00-105-03	(-)0.02	(+)42.20
4.	04	न्याय प्रशासन	2014-00-105-03	(-)21,16.33	(+)35.39
5.			2014-00-105-04	(-)3,28.05	(+)1,54.62
6.			2014-00-114-04	(-)77.64	(-)51.20
7.			2014-00-800-01	(-)14,03.95	(+)56.86
8.			2014-00-800-04	(-)56.46	(+)12.10
9.			2014-00-800-14	(-)4,54.67	(-)41.58
10.	05	चुनाव	2015-00-103-01	(-)34.18	(-)60.00
11.			2015-00-103-05	(-)1,30.43	(+)29.79
12.			2015-00-105-04	(-)1,60.46	(-)20.65
13.			2015-00-106-03	(-)83.34	(+)56.84
14.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2245-80-800-05	(-)37.00	(-)13.00
15.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2040-00-001-04	(-)73.75	(+)81.75
16.	08	आबकारी	2039-00-001-03	(-)3.00	(-)31.53
			2039-00-001-04	(+)3.00	(-)70.66
17.	10	पुलिस एवं कारागार	2055-00-001-03	(+)8.00	(-)1,59.26
			2055-00-109-04	(-)8.00	(-)1,47.07
18.	11	शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-01-101-04	(-)1,01,09.30	(-)36,92.38
19.			2202-01-102-07	(-)4.02	(+)60.74
20.			2202-01-102-18	(-)1,15.76	(-)1,24.41
21.			2202-01-104-03	(-)2,51.35	(-)4,30.66
22.			2202-01-104-05	(-)4,25.78	(-)34.32
23.			2202-03-103-03	(-)10,36.16	(-)1,90.80
24.			2202-03-103-04	(-)1,63.51	(-)55.01
25.			2202-03-103-08	(-)65.78	(-)114.74
26.			2202-03-104-03	(-)1.64	(+)3,35.00
27.			2203-00-001-03	(-)10.03	(+)20.59
28.			2203-00-105-03	(-)6,88.78	(+)44.59
29.			2203-00-112-03	(-)1,01.59	(-)80.00
30.			2204-00-001-10	(+)1.43	(+)11.78

31.			2205-00-001-03	(-)8.46	(+)1,28.00
32.			2205-00-103-03	(-)20.49	(+)16.79
33.			4202-01-201-03	(-)21.33	(-)14,26.35
34.			4202-01-202-01	(-)9,81.36	(-)37,63.66
35.			4202-01-203-18	(-)0.01	(+)1,13.51
36.			4202-03-102-01	(-)80.00	(-)10,00.00
37.			4202-03-102-13	(-)1,76.41	(-)2,23.59
38.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-03	(-)2,52.87	(+)48.34
39.			2210-01-110-05	(-)1,13.96	(-) 94.92
40.			2210-03-104-03	(-)6,01.80	(-)87.40
41.			2210-03-110-09	(-)52.41	(+)21.93
42.			2210-03-110-17	(-)7,36.88	(+)19.12
43.			2210-03-110-23	(-)5.59	(-)11.51
44.			4210-02-110-08	(-)5.50	(-)14.41
45.	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	2215-01-101-05	(-)21.91	(+)25,13.40
46.			2215-01-101-97	(-)5,43.00	(-)24,57.00
47.			2215-01-800-04	(-)13.90	(-)16.70
48.			2215-02-106-05	(-)5.66	(-)14.34
49.	15	कल्याण	2235-02-102-01	(-)24,14.05	(-)1,12.37
50.			2235-02-102-06	(-)1,22.71	(+)13.13
51.	17	कृषि कार्य एवं शोध	2415-80-120-05	(-)1,11.94	(-)1,38.06
52.			2415-80-120-08	(+)1,11.94	(-)53.84
53.	18	सहकारिता	2425-00-800-19	(-)4,20.00	(-)1,80.00
54.	19	ग्राम्य विकास	2501-01-800-01	(-)33,01.73	(-)19.99
55.			2515-00-102-01	(-)7.07	(+)20.00
56.			2515-00-800-06	(-)1.27	(-)20.31
57.			2515-00-800-08	(-)20.62	(-)23,15.94
58.	20	सिंचाई एवं बाढ़	2700-00-001-04	(-)12,35.37	(-)89.14
59.			2701-13-101-02	(-)0.04	(-)13.03
60.			2701-14-101-02	(-)30.00	(-)15.00
61.			2702-03-102-03	(-)5.74	(-)3,99.98
62.			2702-03-103-03	(-)0.04	(+)4,99.93
63.			4700-05-800-01	(-)76,21.92	(-)19,37.71
64.			4700-06-800-02	(-)2,78.57	(+)6,03.36
65.			4702-00-800-01	(-)1,36,88.94	(-)3,48.72
66.	22	लोक निर्माण	3054-04-337-03	(-)16.68	(+)9,66.08
67.			4059-80-800-09	(-)20.00	(+)19.99
68.			4059-80-800-10	(-)10.18	(-)25.00
69.			5054-03-101-03	(-)43.30	(+)9,64.16
70.			5054-04-800-01	(-)1,00.49	(-)7,07.47
71.			5054-04-800-03	(-)12,63.55	(+)18,07.00
72.			5054-04-800-05	(-)20.50	(-)26.65
73.			5054-04-800-06	(-)41.05	(+)64,33.83

74.			5054-04-800-97	(-)75,99.34	(-)63,10.53
75.	23	उद्योग	2851-00-102-17	(-)2.00	(-)1,88.00
76.			2851-00-102-23	(+)19.00	(+)1,88.00
77.			2853-02-001-03	(-)29.04	(-)29.99
78.			2853-02-102-03	(-)0.04	(+)30.00
79.	29	उद्यान विकास	2401-00-119-03	(-)35.56	(-)5,88.04
80.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	4202-01-201-02	(-)94.76	(+)23.20
81.			4702-00-800-01	(-)36,00.00	(+)1,32.88
82.			5054-04-800-02	(-)51.79	(+)11,07.05
83.			5054-04-800-97	(-)34,00.00	(-)11,00.00

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ-48)

वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए भारी अभ्यर्पण

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान/विनियोग (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण का प्रतिशत
1.	03-मंत्री परिषद	2013-00-101-04	8.80	6.73	76.48
2.	04- न्याय प्रशासन	2014-00-105-04	4,11.95	3,28.05	79.63
3.		2014-00-105-05	50.0	50.00	1,00.00
4.		2014-00-800-01	20,44.40	14,03.95	68.67
5.		2014-00-800-10	46.22	46.22	1,00.00
6.		2014-00-800-14	6,49.60	4,54.67	70.00
7.	05- निर्वाचन	2015-00-106-05	66.00	33.35	50.53
8.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2245-80-800-03	50.00	50.00	1,00.00
9.		2245-80-800-08	92.22	63.56	68.92
10.	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं	2052-00-090-04	4.00	2.08	52.00
11.	विविध सेवाएँ	2052-00-090-11	38.14	29.31	76.85
12.		2052-00-090-13	26.00	17.04	65.54
13.		3451-00-092-04	2,00.00	1,71.58	85.79
14.		3451-00-092-05	10.00	10.00	1,00.00
15.		3451-00-092-09	5.00	3.92	78.40
16.		4216-02-800-11	1,00.00	1,00.00	1,00.00
17.		4216-02-800-13	1,00.00	1,00.00	1,00.00
18.		4216-02-800-14	1,00.00	1,00.00	1,00.00
19.		4216-02-800-15	50.00	32.78	65.56
20.		4216-02-800-16	500.00	4,87.33	97.47
21.	11-शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-01-102-01	5,90.00	3,77.49	63.98
22.		2202-01-104-05	5,22.02	4,25.78	81.56
23.		2202-01-800-99	10.00	10.00	1,00.00
24.		2202-03-800-08	3.00	3.00	1,00.00
25.		2202-05-102-04	78.94	68.94	87.33
26.		2202-05-102-06	20.00	20.00	1,00.00
27.		2202-05-102-07	10.00	10.00	1,00.00
28.		2202-05-102-09	2.50	2.50	1,00.00
29.		2202-05-102-10	10.00	10.00	1,00.00
30.		2202-05-102-11	25.00	25.00	1,00.00
31.		2202-05-102-12	15.00	15.00	1,00.00
32.		2202-05-102-13	54.31	41.12	75.71
33.		2203-00-104-04	30.00	30.00	1,00.00
34.		2203-00-800-97	15,00.00	13,00.00	86.67
35.		2204-00-001-05	80.00	43.33	54.16
36.		2204-00-001-09	20.00	20.00	1,00.00
37.		2204-00-104-03	10.00	09.00	90.00
38.		2205-00-102-01	12.75	12.69	99.53

39.		4202-01-203-11	50.00	27.42	54.84
40.		4202-02-104-01	16,00.01	12,00.01	75.00
41.		4202-02-105-07	5,00.00	5,00.00	1,00.00
42.		4202-02-105-09	5,00.00	5,00.00	1,00.00
43.		4202-04-106-03	2,80.00	1,61.40	57.64
44.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-001-05	3,50.00	2,39.22	68.35
45.		2210-01-110-20	12.70	9.73	76.61
46.	15- कल्याण	2235-02-102-03	1,46,00.00	95,13.71	65.16
47.		2235-02-103-13	50.00	39.41	78.82
48.	19- ग्राम्य विकास	2515-00-102-05	10,34.88	954.78	92.26
49.		2515-00-102-12	2,00.00	1,33.43	66.72
50.		2515-00-102-18	44.01	26.66	60.58
51.		2515-00-102-19	6,00.00	6,00.00	1,00.00
52.		2515-00-102-21	80.00	80.00	1,00.00
53.		2515-00-102-97	55,00.00	37,52.00	68.22
54.		4515-00-102-04	25.00	25.00	1,00.00
55.		4515-00-102-05	5,00.00	3,33.33	66.67
56.		4515-00-102-09	50,00.00	50,00.00	1,00.00
57.	20- सिंचाई एवं बाढ़	2700-80-800-01	19,00.00	19,00.00	1,00.00
58.		2702-02-005-05	15.72	12.87	81.87
59.		2701-14-101-02	45.00	30.00	66.67
60.		4702-00-800-01	2,26,03.00	1,36,88.94	60.56
61.	22- लोक निर्माण	3054-80-800-04	95.00	85.61	90.12
62.		5054-04-800-07	50.00	50.00	1,00.00
63.	23- उद्योग	2851-00-102-20	10.00	10.00	1,00.00
64.		2851-00-102-21	15.00	15.00	1,00.00
65.		2851-00-800-07	1,00.00	1,00.00	1,00.00
66.		3425-60-600-01	7,20.00	7,20.00	1,00.00
67.		4859-02-800-01	28,04.00	22,93.00	81.78
68.		4859-02-800-10	2,00.00	2,00.00	1,00.00
69.	24-परिवहन	3055-00-190-06	5,00.00	4,20.40	84.08
70.		5055-00-050-06	40,00.00	40,00.00	1,00.00
71.		5055-00-050-07	50.00	50.00	1,00.00
72.		5055-00-050-08	50.00	50.00	1,00.00
73.		5055-00-050-09	1,00.00	1,00.00	1,00.00
74.	29- उद्यान विकास	2401-00-119-16	19.00	18.53	97.53
75.		2401-00-119-18	50.00	46.59	93.18
76.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	2202-03-103-03	50.00	50.00	1,00.00
77.		2205-00-102-02	55.00	42.71	77.65
78.		2210-03-103-03	33.50	33.50	1,00.00
79.		2010-03-110-91	1,25.00	1,25.00	1,00.00
80.		2235-02-102-02	42,00.03	28,53.14	67.93
81.		4202-01-201-01	8,57.70	5,51.95	64.35
82.		4202-02-105-03	1,60.00	1,60.00	1,00.00
83.		4202-02-105-04	1,25.00	1,25.00	1,00.00
84.		4202-02-105-05	1,00.00	1,00.00	1,00.00

85.		4210-02-110-02	1,50.00	1,50.00	1,00.00
86.		4210-02-110-03	20.00	20.00	1,00.00
87.		4210-02-110-04	80.00	80.00	1,00.00
88.		4702-00-800-01	36,00.00	36,00.00	1,00.00
89.		4702-00-800-02	30.00	30.00	1,00.00
90.		5055-00-800-03	30.00	20.00	66.67
91.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2202-01-800-01	822.59	6,32.00	76.83
92.		2202-03-796-03	6.00	6.00	1,00.00
93.		2203-00-105-03	40.00	40.00	1,00.00
94.		2210-03-796-06	10.40	8.09	77.79
95.		2210-06-800-02	3.00	2.49	83.00
96.		2235-02-796-01	873.60	618.02	70.74
97.		2501-01-796-01	372.18	187.46	50.37
98.		2515-00-796-10	15.00	11.54	76.93
99.		2515-00-796-13	40.00	40.00	100.00
100.		2515-00-796-14	10.00	10.00	100.00
101.		2515-00-796-97	96.56	50.56	52.36
102.		4202-01-201-01	180.57	140.41	77.76
103.		4202-01-203-03	80.00	66.20	82.75
104.		4202-02-104-03	70.00	68.91	98.44
105.		4202-02-105-03	35.00	35.00	100.00
106.		4202-02-105-05	30.00	30.00	100.00
107.		4702-00-796-01	1090.00	1090.00	100.00
108.		5054-04-796-01	30.00	29.20	97.33
109.		5054-04-796-97	500.00	500.00	100.00
110.		5055-00-800-03	8.40	5.60	66.67
योग			**8,52,28.70**	**6,43,14.24**	**75.02**

परिशिष्ट-2.7 अ

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ-48)

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत					
1.	04-न्याय प्रशासन	1,35.33	50.90	52.68	1.78
2.	20-सिंचाई	3,46.89	31.45	38.42	6.97
योग		**4,82.22**	**82.35**	**91.10**	**8.75**

परिशिष्ट-2.7 ब

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ-48)

अन्तिम आधिक्य के बावजूद अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	अभ्यर्पित राशि
पूँजीगत- दत्तमत					
1.	22-लोक निर्माण	9,13.20	9,19.55	6.35	24.51
योग		**9,13.20**	**9,19.55**	**6.35**	**24.51**

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ-48)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ 10 करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

I – अनुदान			
क्रम संख्या	**अनुदान संख्या**	**अनुदान/विनियोग का नाम**	**बचत**
1.	01	विधान मण्डल (पूँजीगत-दत्तमत)	22.00
2.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत-भारित)	8,09.76
3.	25	खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	2,30.84
4.	26	पर्यटन (राजस्व-दत्तमत)	30.05
5.	26	पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	55.32
6.	10	पुलिस एवं कारागार (राजस्व-दत्तमत)	32.17
7.	10	पुलिस एवं कारागार (पूँजीगत-दत्तमत)	43.76
8.	16	श्रम एवं रोजगार (राजस्व-दत्तमत)	36.45
9.	17	कृषि कार्य एवं शोध (राजस्व-दत्तमत)	1,31.83
10.	21	ऊर्जा (पूँजीगत-दत्तमत)	3,68.40
11.	27	वन (पूँजीगत-दत्तमत)	16.32
12.	27	वन (राजस्व-दत्तमत)	27.10
योग			**1,804.00**
13.	7	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-भारित)	*41.44*
योग			***41.44***
महा योग			**18,45.44**

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ-49)

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष था
1	2	3	4	5
1.	01- विधान मण्डल (राजस्व -दत्तमत)	2.09	0	2.09
2.	01- विधान मण्डल (पूँजीगत-दत्तमत)	22.00	0	22.00
3.	04-न्याय प्रशासन (पूँजीगत-दत्तमत)	3.76	0.24	3.52
4.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	64.40	2.20	62.20
5.	07-वित्त कर नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-दत्तमत)	5,49.18	5.79	5,43.39
6.	07- वित्त कर नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-भारित)	*41.44*	*0*	*41.44*
7.	07- वित्त कर नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत-दत्तमत)	20.60	8.55	12.05
8.	07- वित्त कर नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत- भारित)	*8,09.76*	*0*	*8,09.76*
9.	08- आबकारी (राजस्व-दत्तमत)	1.02	0	1.02
10.	09 – लोक सेवा आयोग (राजस्व-भारित)	1.93	0	1.93
11.	09 – लोक सेवा आयोग (पूँजीगत- भारित)	1.46	0	1.46
12.	10- पुलिस एवं कारागार (राजस्व-दत्तमत)	32.17	0	32.17
13.	10- पुलिस एवं कारागार (पूँजीगत-दत्तमत)	43.76	0	43.76
14.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति (राजस्व-दत्तमत)	5,67.60	2,44.31	3,23.29
15.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति (पूँजीगत-दत्तमत)	1,22.03	35.77	86.26
16.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	1,33.41	67.51	65.90
17.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	2,30.97	1.35	2,29.62
18.	13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (राजस्व-दत्तमत)	1,53.22	32.72	1,20.50
19.	13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	3,07.99	0.01	3,07.98
20.	14- सूचना (राजस्व-दत्तमत)	1.84	0	1.84
21.	15-कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	1,91.96	1,21.58	70.38
22.	15-कल्याण (पूँजीगत -दत्तमत)	3.54	1.00	2.54
23.	16-श्रम एवं रोजगार (राजस्व-दत्तमत)	36.45	0	36.45
24.	17-कृषि कार्य एवं शोध (राजस्व-दत्तमत)	1,31.83	0	1,31.83
25.	17-कृषि कार्य एवं शोध (पूँजीगत-दत्तमत)	13.27	0	13.27
26.	18- सहकारिता (राजस्व-दत्तमत)	6.03	0	6.03
27.	19-ग्राम्य विकास (राजस्व-दत्तमत)	1,33.00	95.74	37.26
28.	19-ग्राम्य विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	1,32.55	1,05.21	27.34
29.	20- सिंचाई एवं बाढ़ (पूँजीगत-दत्तमत)	2,56.27	2,15.89	40.38
30.	21- ऊर्जा (पूँजीगत-दत्तमत)	3,68.40	0	3,68.40
31.	22-लोक निर्माण (राजस्व-दत्तमत)	56.85	0.45	56.40
32.	24-परिवहन (पूँजीगत-दत्तमत)	43.95	42.70	1.25
33.	25- खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	2,30.84	0	2,30.84

34.	26- पर्यटन (राजस्व-दत्तमत)	30.05	0	30.05
35.	26- पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	55.32	0	55.32
36.	27- वन (राजस्व-दत्तमत)	27.10	0	27.10
37.	27- वन (पूँजीगत-दत्तमत)	16.32	0	16.32
38.	28-पशुपालन (राजस्व-दत्तमत)	9.04	0	9.04
39.	29-उद्यान विकास (राजस्व-दत्तमत)	7.19	2.16	5.03
40.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	1,14.39	70.25	44.14
41.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	2,03.71	85.28	1,18.43
42.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	36.68	19.46	17.22
43.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	54.28	24.62	29.66
योग		**52,69.65**	**11,82.79**	**40,86.86**

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ-49)

30/31 मार्च 2013 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान का *प्रतिशत*
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	11	2202- सामान्य शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	212.85	5.26
2.	11	2203- तकनीकी शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	29.08	28.27
3.	11	4202- सामान्य शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	35.77	9.95
4.	12	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (राजस्व-दत्तमत)	53.93	6.64
5.	12	2211- परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	13.58	15.39
6.	13	2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व-दत्तमत)	32.43	7.50
7.	15	2235- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	121.58	21.03
8.	19	2501- ग्राम्य विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (राजस्व-दत्तमत)	33.02	42.00
9.	19	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (राजस्व-दत्तमत)	62.72	20.17
10.	19	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	105.21	33.68
11.	20	2700- वृहद सिंचाई (राजस्व-दत्तमत)	36.71	14.09
12.	20	4700- वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	79.00	22.18
13.	20	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	136.89	59.81
14.	22	5054- सड़कों व पुलों पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	24.21	2.66
15.	23	4859- दूर संचार एवं यान्त्रिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	22.93	58.66
16.	24	5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	42.70	98.16
17.	30	2202- सामान्य शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	24.37	20.63
18.	30	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	28.53	24.56
19.	30	4202- शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	10.53	32.18
20.	30	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	36.30	100.00
21.	30	5054- सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	34.52	41.89
22.	31	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय पूँजीगत -दत्तमत)	10.90	95.20
योग			**1187.76**	**12.70**

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.12; पृष्ठ-49)

व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखाशीर्ष योजना/सेवा	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2013 के दौरान किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
					जनवरी-मार्च 2012	मार्च 2013
1.	2015	10.16	4.92	19.44	52.26	25.31
2.	2030	15.51	7.69	22.95	67.58	33.51
3.	2049	10,14.89	6,97.81	20,88.73	48.59	33.41
4.	2203	31.04	17.87	74.06	41.91	24.13
5.	2215	2,17.01	1,05.96	4,15.52	52.23	25.50
6.	2216	1.18	0.95	1.90	62.11	50.00
7.	2217	41.99	33.07	91.21	46.04	36.26
8.	2225	1,02.84	69.84	2,05.28	50.10	34.02
9.	2250	31.00	23.29	43.81	70.76	53.16
10.	2251	0.05	0.04	0.06	83.33	66.67
11.	2408	1,13.15	1,10.47	1,47.50	76.71	74.89
12.	2425	20.06	8.83	35.15	57.07	25.12
13.	2501	27.39	13.28	58.54	46.79	22.69
14.	2701	7.38	4.88	13.17	56.04	37.05
15.	2702	45.64	16.93	68.75	66.39	24.63
16.	2711	1.86	0.99	4.14	44.93	23.91
17.	2810	9.95	1.58	13.86	71.79	11.40
18.	3054	1,02.71	86.38	1,83.26	56.05	47.14
19.	3454	8.24	6.18	16.30	50.55	37.91
20.	4055	22.78	21.76	28.50	79.93	76.35
21.	4059	82.50	39.27	1,00.87	81.79	38.93
22.	4202	2,18.41	1,80.11	2,46.82	88.49	72.97
23.	4210	1,15.88	1,01.51	1,34.52	86.14	75.46
24.	4211	2.89	2.05	4.80	60.21	42.71
25.	4215	66.24	17.44	1,12.97	58.64	15.44
26.	4216	7.43	5.67	12.31	60.36	46.06
27.	4217	74.97	74.97	1,42.82	52.49	52.49
28.	4225	36.37	32.42	37.35	97.38	86.80
29.	4235	3.85	3.85	5.98	64.38	64.38
30.	4250	10.59	10.59	17.25	61.39	61.39
31.	4401	25.82	20.64	17.23	149.85	119.79
32.	4403	3.33	2.39	7.03	47.37	34.00
33.	4406	24.25	15.40	41.51	58.42	37.10
34.	4515	1,07.98	37.79	2,46.73	43.76	15.32
35.	4700	1,67.79	1,40.69	2,57.95	65.05	54.54
36.	4701	0.61	0.56	0.61	100.00	91.80

37.	4702	67.09	39.94	88.79	75.56	44.98
38.	4711	25.20	24.60	39.50	63.80	62.28
39.	4801	4,54.88	4,52.67	5,16.12	88.13	87.71
40.	4859	13.81	10.70	16.16	85.46	66.21
41.	5053	95.17	95.18	95.44	99.72	99.73
42.	5054	4,90.54	3,57.02	8,72.77	56.20	40.91
43.	5055	0.54	0.54	0.93	58.06	58.06
44.	5452	14.83	5.69	20.23	73.31	28.13
45.	6003	7,79.82	4,17.22	14,58.74	53.46	28.60
46.	6075	3.08	0.00	3.08	100.00	0.00
47.	6401	1,40.83	1,00.83	1,56.36	90.07	64.49
48.	6425	1.80	0.96	2.31	77.92	41.56
49.	7055	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00
50.	7610	0.56	0.17	1.03	54.37	16.50
योग		**48,86.89**	**34,48.59**	**82,15.34**	**59.48**	**41.98**

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भः प्रस्तर 2.4.1 ; पृष्ठ-51)

वर्ष 2012-13 तक के लम्बित डी. सी. बिल

(अगस्त 2013 को स्थिति)

(₹ लाख में)

विभाग	मुख्य शीर्ष	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
पशुपालन	2403	6	5.22
चुनाव	2015	5	9.93
सामान्य शिक्षा	2202	75	2,73.43
चिकित्सा	2210	8	4,48.82
दैवीय आपदा में राहत	2245	5	1,05.84
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235	5	81.76
श्रम एवं रोजगार	2230	1	15.00
शिक्षा, खेल-कूद एवं संस्कृति	2205	2	87.44
खाद्य भण्डारण एवं भण्डारागार	4408	10	40.00
अन्य		46	34.19
योग		**163**	**11,01.63**

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भः प्रस्तर 3.2; पृष्ठ-60)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखो के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखो की अवधि	अन्तिम रूप दिए गए पिछले लेखाओं के अनुसार निवेश *(₹ करोड़ में)*	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु अभ्युक्ति/कारण
सिंचाई विभाग:				
1.	सिंचाई कार्यशाला, खण्ड, रूड़की	2009-10	1.89	--
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग				
2.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2002-03	--	--
3.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	--	

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भः प्रस्तर 3.3; पृष्ठ-60)

दुर्विनियोग, चोरी/हानि आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण (वे मामलें जिनमें मार्च 2013 के अन्त में अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	विलम्बित मामलों की संख्या						
		0-1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 वर्ष या अधिक	कुल मामलों की संख्या
1.	शिक्षा	--	--	--	--	01 (3/2009)	--	01
2.	वन	01 (3/2012)	02 (4/2011 और 6/2011)	--	--	--	--	03
योग		**01**	**02**	**--**	**--**	**01**	**--**	**04**

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भः प्रस्तर 3.3; पृष्ठ-60)

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सम्पत्ति की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सम्पत्ति का दुर्विनियोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
शिक्षा	--	--	01	1.07	01	1.07
वन	--	--	03	142.71	03	142.71
योग	**--**	**--**	**04**	**143.78**	**04**	**143.78**

परिशिष्ट-4.1

शब्दावली

क्रमांक	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की तन्यता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक *प्रतिशत* तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 *प्रतिशत* बिन्दुओं तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	*कोर पब्लिक गुड्स* ऐसी वस्तुएँ है जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु के दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुडस ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर पोषण के समर्थन हेतु प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रुग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियाँ की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन

		बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर – ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियाँ की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्राप्तियाँ का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।
11.	ऋणेत्तर प्राप्तियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

http://agua.cag.gov.in

Designed & Printed at Shiva Offset Press, Dehradun Ph. 0135-2715748